₹75/-
विशेषांक
सीमा संघोष
वर्ष 2024
भारत के प्रथम गाँव
RNI No. : DELBIL/2021/79984

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्री
भारत
DEFENCE MINISTER
INDIA

संदेश

मुझे बताया गया है कि सीमा जागरण मंच के मुखपत्र सीमा संघोष के वार्षिक विशेषांक 'भारत के प्रथम गाँव' का प्रकाशन हो रहा है। राष्ट्र की सुरक्षा में निश्चित ही 'प्रथम गाँवों' का योगदान अतुलनीय है। इनके विकास से राष्ट्रीय-सुरक्षा का विशेष संबंध है।

मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि सीमा संघोष पत्रिका, देश की सीमा सुरक्षा से जुड़े सांगोपांग विषयों को लेकर जनजागरण का महत्वपूर्ण कार्य करती रही है। प्रथम गाँव, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस दृष्टि से सीमा संघोष पत्रिका का यह वार्षिक विशेषांक एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है।

सीमा संघोष के संपादक मंडल और इससे सम्बद्ध सभी कार्मिकों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और मैं उपरोक्त पत्रिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

"जय हिंद"

(राजनाथ सिंह)

नई दिल्ली
12 फरवरी, 2024

Office : Room No. 104, Ministry of Defence, South Block, New Delhi-110011
Tel. : +91 11 23012286, +91 11 23019030, Fax : +91 11 23015403
E-mail : rmo@mod.nic.in

शुभकामना संदेश

मुझे अवगत कराया गया है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सीमा जागरण मंच मुखपत्र सीमा संघोष के वार्षिक विशेषांक का प्रकाशन हो रहा है। इस बार का विषय "भारत के प्रथम गाँव" सीमा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सीमा क्षेत्रों में रहने वाले हमारे प्रथम गाँव के नागरिकों का सीमा सुरक्षा में बहुत ही अहम योगदान रहता है।

मैं सीमा संघोष की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण विषय को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उनके प्रयास की सराहना करते हुए इस अंक के सफल प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। मुझे विश्वास है की सीमा संघोष की टोली भविष्य में भी सीमा सुरक्षा को लेकर जनजागृति के लिए ऐसे सम्बंधित विषयों पर सजगता से सभी देशवासियों को जागृत करने का प्रयास करती रहेगी।

(आलोक)

अ. भा. सह प्रचार प्रमुख

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

संरक्षक

लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) विष्णुकान्त चतुर्वेदी

सलाहकार

लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) अरुण साहनी

निदेशक

रविन्द्र अग्रवाल

मुख्य संपादक

दीपांशु गर्ग

उप संपादक

डॉ. प्रदीप कुमार

राजीव रंजन प्रसाद

डॉ. चंद्रवीर सिंह भाटी

डिजिटल मीडिया प्रमुख

धीरज कुमार झा

प्रकाशकों और लेखकों ने सीमा संघोष की सामग्री के संबंध में अपने अधिकार सुरक्षित रखे हैं। प्रकाशकों की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर कोई भी कॉपीराइट कार्य किसी भी रूप या किसी भी माध्यम से पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यहाँ उपयोग की गई छवियाँ सार्वजनिक डोमेन से हैं, उनके संबंधित स्वामियों की है और केवल जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए यहाँ उपयोग की जा रही हैं। यह पत्रिका गैर-व्यावसायिक, गैर-लाभदायक और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य लेकर प्रस्तुत की गयी है।

'अंतिम और प्रथम', यदि इन दो शब्दों का हम विश्लेषण करें तो पाएंगे कि "अंतिम" शब्द पंक्ति में सबसे आखिरी होने का द्योतक है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह महत्वहीन वस्तु अथवा स्थान, जिस पर हमारा ध्यान सबसे अंत में जाता हो। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो अब तक सभी सीमांत गाँवों को अंतिम गाँव कहा जाता था। इन अंतिम गाँवों की कोई उपयोगिता ना मानते हुए पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा हमेशा इनकी उपेक्षा की जाती रही थी। इन गाँवों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव था तथा सड़कें इस दृष्टिकोण के कारण नहीं बनाई जाती थीं कि कहीं दुश्मन देश के सैनिक इनका इस्तेमाल कर देश के भीतर न घुस आएं। इन्हीं कारणों से सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसके विषय में अभी तक हम केवल सुनते हुए आये थे। यह आश्चर्य की बात है कि उस समय के नीति निर्धारकों द्वारा कभी इस विषय पर ना तो चिंतन किया गया, न ही कोई समाधान देने की पहल की गयी।

इस संबंध में सरकारों को दोष देना भर न्याय संगत नहीं होगा; हम सभी देशवासी जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, वे भी इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हम सभी लोगों ने कभी सीमा सुरक्षा या सीमान्तवासियों को लेकर उतनी जिज्ञासा और सजगता नहीं दिखाई जितनी बाकी विषयों पर हम दिखते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों पर हम कभी चर्चा ही नहीं करते हैं। अपनी दिनचर्या में हम राजनीति की, फिल्मों की, आने वाले आईफोन के नए मॉडल की, विदेश में छुट्टियां

मनाने जैसे विषयों पर तो बहुत बातें करते हैं लेकिन सीमांत क्षेत्र में रहने वाले हमारे नागरिकों के जीवन की कठिनाइयों से हमारा कोई सरोकार नहीं रहता। सीमा सुरक्षा या राष्ट्र सुरक्षा केवल सीमा प्रहरियों का विषय है, इस भाव के साथ हम इस गंभीर विषय की ओर ध्यान नहीं देते। सीमा पर वीरान होते गाँव, सरहद पर होती घुसपैठ, दुश्मन देश की कुटिल चालें और सबसे कम जानकारी वाले इन भू भाग से हम सभी नागरिकों की आत्मीयता उतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिए।

अब सीमा पर अंतिम गाँव, प्रथम गाँव कहलाये जायेंगे। उत्तराखंड सीमा पर स्थित माणा गाँव से इसकी शुरुआत हो चुकी है। यह निर्णय केवल नाम बदलने का नहीं है अपितु हमारी सोच बदलने का है। हम सभी देशवासियों का इन क्षेत्रों के प्रति दृष्टिकोण बदलने का है। प्रथम शब्द प्राथमिकता बतलाता है, इन गाँवों से हो रहे पलायन को रोकने की वर्तमान सरकार की दृढ़संकल्पता को प्रदर्शित करता है। यहाँ आधारभूत सुविधाओं को पहुँचाने के लिए सरकार के मजबूत इरादों को बतलाता है। हमारे सीमान्तवासी "First Line of Civil Defence" कहे जाते हैं और वे हमारे सीमा प्रहरियों की आँख और कान बनकर उनका सहयोग करते हैं। कहते हैं जहाँ तक आपकी भाषा और संस्कृति का प्रसार हो जाता है, वहाँ तक आपकी सीमाएं भी फ़ैल जाती हैं और इसीलिये सीमांत गाँवों का बना रहना राष्ट्रहित में अत्यंत आवश्यक है। सीमांत गाँवो को प्रथम गाँव कहलाये जाने का यह निर्णय जहाँ एक ओर यहाँ रह रहे लोगों को गौरवान्वित होने का अवसर देगा, वहीँ यह सभी देशवासियों को इनकी महत्ता बताते हुए उनके साथ आपसी समन्वय व सामंजस्य बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करेगा।

जितनी तेज़ी से युद्ध के प्रकार बदल रहे हैं, उसमें सूचना युद्ध के साथ-साथ एक नये तरह का युद्ध है मनोवैज्ञानिक युद्ध! जिसकी विशेषता है "विनिंग विदऑउट फाइटिंग" यानि दुश्मन देश से युद्ध लड़े बिना ही मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको हरा देना। चीन की थ्री वारफेयर स्ट्रेटेजी में भी लीगल वॉर, सूचना युद्ध के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध भी सम्मिलित है। हम अक्सर उत्तरी सीमा पर चीन के इस युद्ध प्रकार को देखते भी रहते हैं। वे हमारे चरवाहों को हमारी ही भूमि पर बार-बार यह कहकर रोक देते हैं कि वे चीन के इलाका में आ गए हैं। ऐसी घटनाएं या हरकतें चीन की इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। भारतीय क्षेत्रों में अपने झंडे लगाकर चीन मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बनाने की कोशिश करता है। अंतिम गाँव को प्रथम गाँव कहे जाने का यह निर्णय दुश्मन देशों को कठोर सन्देश देने का सबसे जरूरी कार्य भी करेगा। हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह मनोवैज्ञानिक सन्देश सभी देशों तक जायेगा और सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में लगातार कराये जा रहे विकास कार्य, इन दूरस्थ क्षेत्रों को सम्पूर्ण देश से जोड़ने का काम करेंगे।

सीमा संघोष के इस विशेष अंक में हम उन गाँवो की बात करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत के प्रथम गाँव हैं। केवल माणा ही नहीं अपितु ऐसे सभी गाँव जो भारत की स्थलीय या जलीय सीमा से भारत में प्रवेश करते ही सबसे पहले गाँव हैं, प्रथम गाँव कहलाये जाने चाहिए। ऐसे प्रथम गाँवो की सूची बहुत लम्बी है लेकिन हमने चिन्हित करते हुए कुछ गाँवो का विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन करके वहाँ के बारे में जानकारियाँ जुटाई हैं। जिसे सभी देशवासियों तक पहुँचाने का हमारा प्रयास है।

यह अंक समर्पित है प्रथम गाँवो के सभी निवासियों को, विषम परिस्थितियों में भी वहाँ रहते हुए देश के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को, देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे सीमांत नागरिकों को, सुविधाओं के अभाव में भी पलायन ना करने की उनकी इच्छाशक्ति को और देश की सुरक्षा में लगातार योगदान देने की उनकी दृढ़संकल्पता को। मैं आशा करता हूँ कि सीमा सुरक्षा और राष्ट्र सुरक्षा के संकल्प में सीमा संघोष

अनुक्रमणिका

"वाइब्रेंट विलेज योजना" और देश के प्रथम गाँव	06
राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु प्रथम गाँवों को सुदृढ़ करना आवश्यक	09
प्रथम गाँव और राष्ट्रीय दायित्व	12
भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए "ऑरेंज इकोनॉमी" को बढ़ावा देना	16
सुचेतगढ़: जम्मू का एक महत्वपूर्ण प्रथम गाँव	20
हुसैनीवाला: ऐतिहासिक महत्व वाला पंजाब का प्रथम गाँव	24
हिन्द-पाक सीमा प्रहरी: ठाकुर बलवंतसिंह बाखासर	28
प्रथम गाँव नादाबेट : गुजरात का वाघा	31
सीमा प्रबंधन के मुख्य घटक: भारत के प्रथम गाँव	37
वर्कला: भारतीय तट का एक धरोहर	41
पुनर्निर्माण की बाट जोहता प्रथम गाँव धनुष्कोडी	45
ओडिशा तट : एक अवलोकन	48
सत्रसाल : असम की सीमा के प्रथम गाँव का विहंगावलोकन	51
भैरबकुंड: इंडो-भूटान बॉर्डर का प्रथम गाँव	54
प्रथम सूर्योदय का गाँव : किबिथू	58
भारत-बांग्लादेश के बीच 'सीमायें जुड़ रही हैं, दिल जुड़ रहे हैं: डॉकी	61
प्रथम गाँव चंपई: मिजोरम का धान का कटोरा	66
नागा पहाड़ियों में पहला आईएनए प्रशासित गाँव	69
उत्तराखंड में चीन सीमा से प्रवासन-चुनौतियाँ एवं समाधान	72
थारू संस्कृति का केंद्र : प्रथम गाँव जिगना	76
सुरक्षित सीमा के लिए तटीय आबादी का मजबूत होना आवश्यक	79
सिंधु तीरे का प्रथम गाँव चुलिचांग	84
निकोबार के प्रथम गाँव	88
भारत के दक्षिणतम छोर पर स्थित प्रथम गाँव शास्त्री नगर	92

की यह कलम रूपी आहुत सभी देशवासियों की सीमा सुरक्षा के प्रति हमारी सोच बदलने का कार्य करेगी और सीमान्तवासियों को सभी देशवासियों के साथ एक सूत्र में पिरोने का कार्य करेगी। यह अंक सभी नागरिकों को प्रथम गाँव के निवासियों के साथ संपर्क और आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा और सीमा क्षेत्र में स्थित पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करेगा।

मुझे आशा है कि हम सभी सीमा सुरक्षा के इस महवत्पूर्ण विषय के सन्दर्भ में अपनी भूमिका पर विचार करते हुए अधिक जागृत होंगे और सभी को जागृत करने के लिए प्रयास भी करेंगे। क्यूंकि जब जागृत होगा समाज, तभी सुरक्षित होगी सीमा और जब सुरक्षित होगी सीमा, तभी समर्थ बनेगा भारत।

इसी विश्वास के साथ सीमा संघोष की पूरी टीम के साथ, यह अंक मैं आप सभी देशवासियों को प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द, जय सीमा संघोष

- दीपांशु गर्ग

“वाइब्रेंट विलेज योजना” और देश के प्रथम गाँव

ले.ज. (रि) गुरमीत सिंह

PVSM, UYSM, AVSM, VSM

भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल व उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल

जय हिन्द,

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीमावर्ती गाँवों के प्रति आमजन का दृष्टिकोण बदला है, अब सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले व यहाँ भ्रमण पर आने वाले लोग इन्हें अंतिम नहीं अपितु भारत के प्रथम गाँव के रूप में जानते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता हैं। राष्ट्र की सुरक्षा हेतु सीमाओं का सुरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए केंद्र सरकार बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का लगातार कार्य कर रही है। देश के प्रथम गाँवों में मूलभूत सुविधाएँ प्रदान कर वहाँ विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। “वाइब्रेंट विलेज” योजना से अब यह सब संभव होता दिख रहा है।

सीमावर्ती गाँव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। विकसित सीमावर्ती क्षेत्र अधिक सुरक्षित होते हैं और सीमा पर अवैध गतिविधियों जैसे तस्करी और घुसपैठ को रोकने में मदद कर सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास से स्थानीय समुदायों की आय में वृद्धि होती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इससे वहां के निवासियों का जीवन स्तर सुधरता है। सीमावर्ती गाँव दूर-दराज बसे होते हैं और सामाजिक-आर्थिक विकास से वंचित रह जाते हैं। उनका विकास सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है। विकसित सीमावर्ती गाँव अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं, खासकर जब व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सुधार होता है। सीमावर्ती क्षेत्र अक्सर प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, आदि के लिए संवेदनशील होते हैं। इन क्षेत्रों का विकास आपदा प्रबंधन और

प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार कर सकता है। आधुनिक सुविधाओं और प्रौद्योगिकी तक पहुंच सीमावर्ती गाँवों के निवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है। इन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास महत्वपूर्ण है ताकि वहां के निवासियों को बेहतर जीवन स्तर और अवसर प्राप्त हो सके। ये गाँव राष्ट्रीय एकीकरण के प्रतीक होते हैं। उनका विकास राष्ट्रीय पहचान और एकता को मजबूत करता है।

भारत सरकार की 'वाइब्रेंट विलेज योजना' (Vibrant Village Programme) एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य देश के सुदूर और सीमावर्ती गाँवों में विकास को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 विकासखंडों में 2967 गाँवों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 662 गाँवों की लगभग 1 लाख 42 हजार की आबादी को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना पर 2022 से लेकर 2026 तक 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

कार्यक्रम का एक अन्य लक्ष्य सीमावर्ती गाँवों से पलायन रोकना है। इस हेतु ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। पलायन से प्रभावित गाँवों में पूर्ववर्ती स्थिति बनाने के लिए 5 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम का तीसरा लक्ष्य है, सीमावर्ती गाँवों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएँ विकसित करना। वाइब्रेंट विलेज योजना" ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी वित्तीय सहायता, संसाधनों की उपलब्धता और प्रशासनिक समर्थन प्रदान करती है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि, स्वावलंबन और ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करना है। नगरीय क्षेत्रों में भार ना बढ़े इसके लिए गाँवों को भी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

उत्तराखंड अपनी विविधतापूर्ण प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस योजना के तहत यह राज्य विशेष रूप से लाभान्वित हो रहा है। उत्तराखण्ड, अपनी प्राकृतिक समृद्धि और मनोरम सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहां के गाँवों की भव्यता और विशिष्टता न केवल राज्य की पहचान हैं, बल्कि पूरे देश के लिए एक अनमोल धरोहर है। इसी परिप्रेक्ष्य में, भारत सरकार की 'वाइब्रेंट विलेज योजना' उत्तराखण्ड के ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

उत्तराखंड के कई गाँव सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। इस योजना के माध्यम से इन गाँवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, जैसे कि सड़कों का निर्माण, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा का प्रसार और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार किया जा सकता है। उत्तराखंड से बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन को रोकने में यह योजना सहायक हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन युवाओं को अपने गाँवों में ही रोजगार प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

उत्तराखण्ड के तीन सीमावर्ती जिलों; उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली को इस कार्यक्रम के अंतर्गत चुना गया है। इन तीन जिलों के कुल 51 गाँवों को इस योजना में शामिल किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र में एक भी गाँव ऐसा नहीं होगा जहां मूलभूत सुविधाएँ नहीं होंगी। पर्यटन, स्थानीय संस्कृति और भाषा का संरक्षण और संवर्धन करते हुए इन गाँवों का विकास किया जाएगा। इस योजना की सफलता में सामुदायिक भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता और सुझाव इस योजना के हर चरण में महत्वपूर्ण हैं, जिससे योजना के लाभ सीधे और प्रभावी रूप से उन तक पहुँच सकें।

उत्तराखंड के गाँवों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर अतुलनीय है। इस योजना के अंतर्गत, इन गाँवों को पर्यटन के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। इस योजना के तहत गाँवों को उनकी स्थानीय विशेषताओं के अनुसार संसाधन और सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना से उत्तराखंड के गाँवों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बल मिलेगा, जिससे वहां की जीवन शैली में सुधार होगा। इस योजना का उद्देश्य हमारे गाँवों को आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से लैस करना है, ताकि आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ वे एक समृद्ध और संतुलित विकास की ओर अग्रसर हो सकें। उत्तराखण्ड में इस योजना का क्रियान्वयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां के गाँव पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां विकास की चुनौतियां अधिक हैं।

सीमावर्ती गाँवों में बुनियादी ढांचे का विकास जैसे सड़कें, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिकता है। इन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में सुधार करना भी महत्वपूर्ण है। कृषि, पर्यटन, और अन्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों और सामाजिक न्याय के प्रयासों के माध्यम से समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। 'वाइब्रेंट विलेज योजना' उत्तराखंड के लिए एक अवसर है जिसके माध्यम से न केवल राज्य के सीमावर्ती गाँवों में विकास किया जा सकता है, बल्कि यह योजना समग्र रूप से राज्य के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने में भी सहायक होगी। इस प्रकार, इस योजना का क्रियान्वयन उत्तराखंड के लिए नई दिशा और गति प्रदान करेगा। इस योजना की सफलता में सामुदायिक भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता और सुझाव इस योजना के हर चरण में महत्वपूर्ण हैं, जिससे योजना के लाभ सीधे और प्रभावी रूप से उन तक पहुँच सकें। हमारा लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से उत्तराखण्ड के गाँव न केवल अधिक वाइब्रेंट बनें, बल्कि एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करें, जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सके। इस प्रकार, 'वाइब्रेंट विलेज योजना' न केवल उत्तराखण्ड के विकास का एक नया आयाम है, बल्कि यह भारतीय ग्रामीण जीवन की समृद्धि और विविधता को नई ऊँचाईयों तक ले जाने का एक सार्थक प्रयास भी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु प्रथम गाँवों को सुदृढ़ करना आवश्यक

जनरल (रि.) वी.के.सिंह
PVSM AVSM YSM ADC

पूर्व सेनाध्यक्ष व राज्य मंत्री, भारत सरकार

राष्ट्रीय सुरक्षा के विस्तृत तंत्र में सीमा पर गाँवों की पहली पंक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्सर नज़रअंदाज किये जाने वाले ये गाँव व बस्तियाँ बाहरी खतरों के खिलाफ प्रारंभिक रक्षा का कार्य करते हैं और किसी राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह लेख इस बात के बहुआयामी पहलुओं पर प्रकाश डालता है कि इन गाँवों की सुरक्षा सर्वोपरि क्यों है और यह किसी देश के समग्र सुरक्षा तंत्र को सीधे कैसे प्रभावित करती है।

सामरिक महत्व

सीमा पर गाँवों की पहली पंक्ति की भौगोलिक स्थिति उन्हें रणनीतिक महत्व प्रदान करती है। सबसे आगे स्थित, ये बस्तियाँ किसी भी बाहरी आक्रमण की स्थिति में संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। सीमा से उनकी निकटता के कारण अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे घुसपैठियों या शत्रु ताकतों के लिए तत्काल लक्ष्य बन जाते हैं। सीमा से उनकी निकटता के कारण इनके संपर्क मार्ग व इनकी भौगोलिक बनावट तथा इनके बचाव या रण संरचना भी शत्रु ताकतों को रोकने में योगदान देती हैं। इस प्रकार,

किसी भी अनधिकृत प्रवेश या शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए इन गाँवों को सुरक्षित करना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि उसके बिना पूरे देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

मानव ढाल की गतिशीलता:

इन सीमावर्ती गाँवों के निवासी अनजाने में राष्ट्रीय सुरक्षा के अग्रिम पंक्ति के रक्षक बन जाते हैं। सीमा के नजदीक रहते हुए, वे किसी भी संभावित खतरे के खिलाफ प्रारंभिक बफर के रूप में कार्य करते हैं। संघर्ष के समय में, नापाक गतिविधियों को विफल करने में उनका लचीलापन और सुरक्षा बलों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है।

इन गाँवों की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा से परे तक फैली हुई है; इसमें उन निवासियों के जीवन और

> सीमा पर गाँवों की पहली पंक्ति की सुरक्षा केवल क्षेत्रीय अखंडता का मामला नहीं है; इसमें एक राष्ट्र के अस्तित्व का सार समाहित है। ये बस्तियाँ वे जीवित संरचनाएं हैं, जो बाहरी खतरों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में खड़ी हैं।

कल्याण की रक्षा करना शामिल है जो खुद को राष्ट्रीय रक्षा में सबसे आगे पाते हैं।

आर्थिक स्थिरता :

किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता उसकी सीमाओं की सुरक्षा से जटिल रूप से जुड़ी होती है। गाँवों की पहली पंक्ति अक्सर कृषि, व्यापार और अन्य स्थानीय व्यवसायों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन क्षेत्रों की सुरक्षा में कोई भी समझौता आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान पैदा कर सकता है, जिससे न केवल स्थानीय आबादी की आजीविका प्रभावित होगी बल्कि राष्ट्र के समग्र आर्थिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। इसलिए, इन गाँवों की सुरक्षा के बुनियादी ढांचे में निवेश पूरे देश की आर्थिक स्थिरता में एक निवेश है।

सांस्कृतिक संरक्षण :

रणनीतिक और आर्थिक विचारों से परे, सीमा पर गाँवों की पहली पंक्ति किसी देश की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक भी है। ये बस्तियाँ अक्सर किसी देश की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक महत्व का सार प्रस्तुत करती हैं। इन क्षेत्रों को बाहरी खतरों से बचाने से पीढ़ियों से पनप रही सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण सुनिश्चित होता है। इन गाँवों में सुरक्षा उपाय न केवल निवासियों की भौतिक भलाई की रक्षा करते हैं बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत की अमूर्त समृद्धि की भी रक्षा करते हैं।

निवारण और सीमा नियंत्रण :

गाँवों की पहली पंक्ति की सुरक्षा संभावित हमलावरों के लिए निवारक के रूप में कार्य करती है। एक अच्छी तरह से संरक्षित सीमा न केवल बाहरी ताकतों को इसे तोड़ने की कोशिश करने से हतोत्साहित करती है, बल्कि स्थानीय आबादी के बीच विश्वास की भावना भी स्थापित करती है। बदले में यह समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच एक मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देती है, जिससे किसी भी बाहरी खतरे के खिलाफ एकजुट मोर्चा तैयार होता है। इन गाँवों के निवासियों के सहयोग से लागू किए गए प्रभावी सीमा नियंत्रण उपाय क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में योगदान करते हैं।

प्रौद्योगिकी एकीकरण :

आधुनिक युग में एक ऐसा सुरक्षा परिदृश्य विकसित

की आवश्यकता हो गई है। सीमा पर गाँवों की पहली पंक्ति कोई अपवाद नहीं है। निगरानी प्रणाली, ड्रोन तकनीक और अन्य परिष्कृत निगरानी उपकरण लागू करने से सीमा सुरक्षा की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। ये प्रौद्योगिकियां न केवल सुरक्षा बलों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करती हैं, बल्कि संभावित खतरों के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया की भी अनुमति देती हैं, जिससे गाँवों और पूरे देश दोनों के लिए जोखिम कम हो जाता है।

सामुदायिक सशक्तिकरण :

एक मजबूत सुरक्षा ढांचे के लिए गाँवों की पहली पंक्ति में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। निवासियों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों को रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और उपकरण एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों के बीच स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने से एक सहयोगी वातावरण बनता है जहां सुरक्षा बल और समुदाय साथ मिलकर काम करते हैं। यह तालमेल बाहरी खतरों के खिलाफ एक लचीला रक्षा तंत्र बनाने में सक्षम हैं।

चुनौतियाँ और शमन :

सीमा पर गाँवों की पहली पंक्ति को सुरक्षित करने के महत्व के बावजूद विभिन्न चुनौतियाँ मौजूद हैं। सीमित संसाधन, कठिन इलाके और सीमा पार से घुसपैठ का लगातार खतरा कई अवरोध उत्पन्न करता है। हालाँकि, बुनियादी ढांचे में निवेश, बेहतर कनेक्टिविटी और खुफिया जानकारी साझा करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे सक्रिय उपाय इन चुनौतियों को कम कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो तात्कालिक चिंताओं और दीर्घकालिक स्थिरता दोनों को संबोधित करे।

निष्कर्ष :

निष्कर्षतः, सीमा पर गाँवों की पहली पंक्ति की सुरक्षा केवल क्षेत्रीय अखंडता का मामला नहीं है; इसमें एक राष्ट्र के अस्तित्व का सार समाहित है। ये बस्तियाँ वे जीवित संरचनाएं हैं, जो बाहरी खतरों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में खड़ी हैं। व्यापक सुरक्षा नीतियों को तैयार करने के लिए उनके रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानना आवश्यक है। इन सीमावर्ती गाँवों की सुरक्षा को प्राथमिकता देकर, राष्ट्र अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, अपने नागरिकों की रक्षा कर सकते हैं और उनकी स्थायी समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं।

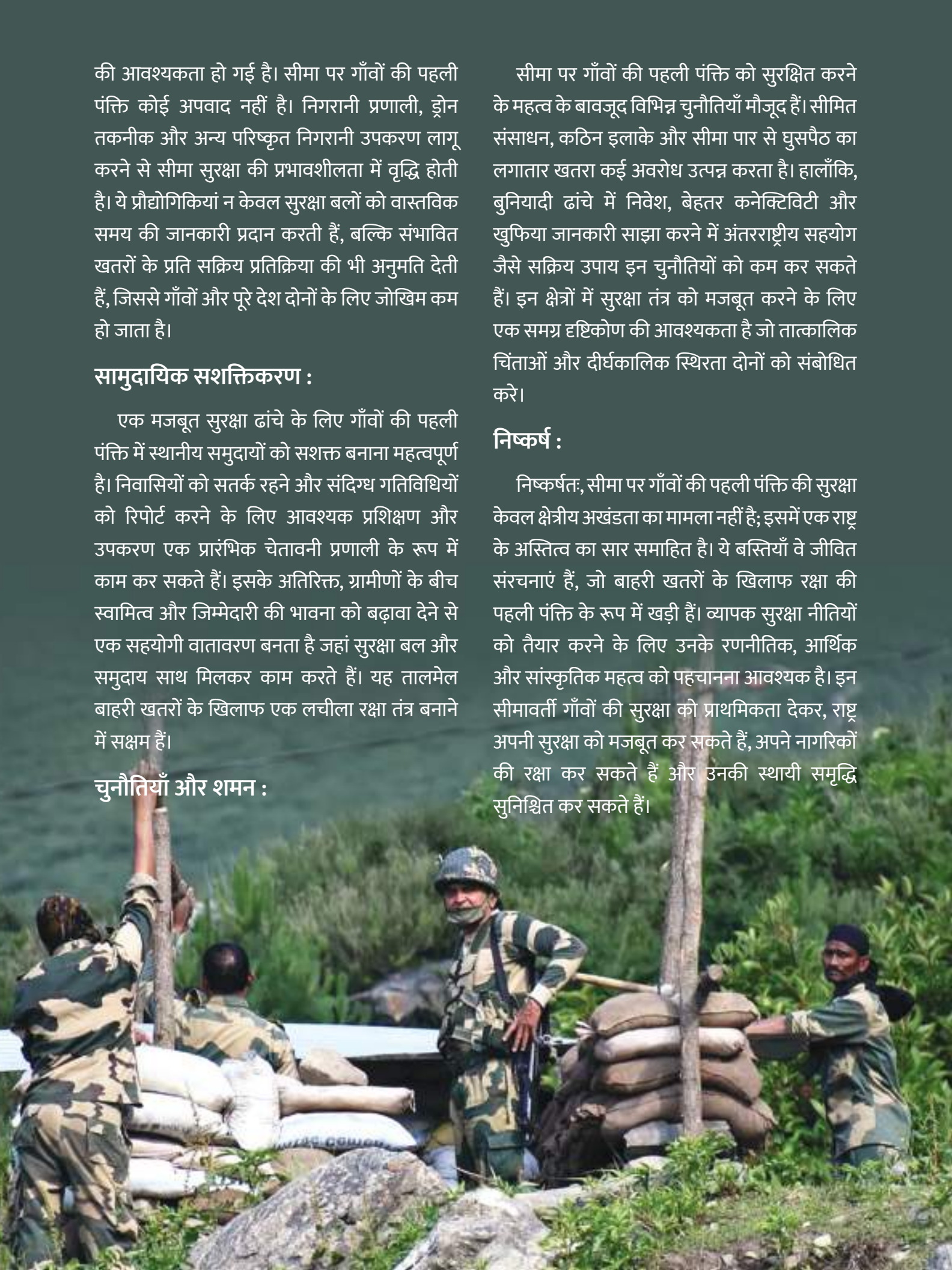

प्रथम गाँव और राष्ट्रीय दायित्व

लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी

PVSM, AVSM, SM

राष्ट्रीय अध्यक्ष-अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद

राष्ट्र की सीमाओं पर हमारे खूबसूरत गाँव जिनको अभी तक सीमावर्ती क्षेत्रों में, दूरदराज के इलाकों में 'अन्तिम गाँव' के नाम से संबोधित किया जाता था, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको 'प्रथम गाँव' के नाम से संबोधित किया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। जब सोच बदलती है तो विचार बदलते हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों में भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है, उनका मनोबल बढ़ता है। प्रथम गाँव को आकर्षण का केंद्र बनाने में हमें अभी बहुत कुछ करना है। नामकरण केवल एक छोटी सी पहल है। लेकिन इसका भावनात्मक प्रभाव दूरगामी है। इन गाँवों के विकास के लिए बहुत कुछ करना है जिससे कि वहां रहने वाले नागरिकों को सुख सुविधाएं मिल जाए, वहां जीवनयापन के लिए कुछ संसाधन उपलब्ध हो जायें तो ये गाँव हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हो जायेंगे।

हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां

रहने वाले नागरिक इन गाँवों से पलायन न करें। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूरदराज के इलाकों में रहने वाले हमारे देशवासी सदैव हमारी शक्ति होते हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बारे में सेना को और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रथम सूचना हमारे ये नागरिक ही देते हैं। युद्ध के समय में भी सशस्त्र सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे यही नागरिक खड़े होते हैं। हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने और गौरवान्वित करने में सदैव तत्पर रहते हैं।

प्रथम गाँव को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय, सभी स्तरों पर कार्य करना पड़ेगा। जब सभी स्तरों पर मिलजुल कर, समन्वय के साथ विकास और प्रगति पथ पर चलेंगे तो हम सफलता के शिखर पर निश्चित रूप से पहुंचेंगे।

प्रथम गाँव का विकास और यह निर्धारित करने के लिए कि इन ग्रामों से कोई भी पलायन न हो, तो इसके लिए सभी स्तर पर लगन, प्रतिबद्धता और परिश्रम की जरूरत है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है, और इसलिए एक अहम विषय है।

राष्ट्रीय स्तर

राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य विकास से संबंधित है। संचार माध्यमों का विस्तार, सड़क मार्ग या रेल मार्ग से जैसे भी मुमकिन हो, ऐसे प्रथम गाँवों को जोड़ना चाहिए। हवाई माध्यम से भी जहां तक मुमकिन हो ऐसे गाँवों को जोड़ना जरूरी है, जैसे कि टूटिंग, वालोंग, मोरेह इत्यादि हैं।

इन्टरनेट कनेक्टिविटी और दूरसंचार के अन्य साधनों का भी इन इलाकों में सुरक्षा को मद्देनजर विकास किया जाना चाहिए। मनोरंजन, टेलीविजन आदि की सुविधा को भी उपलब्ध कराना होगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात जो राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार का दायित्व है, वह ऐसे गाँवों की विरासत, यहां की धरोहर, संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करना है। इन विरासत और धरोहर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सही ढंग से प्रस्तुत करना राष्ट्रीय नेतृत्व का एक बहुत बड़ा

दायित्व है।

राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे इलाकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन इलाकों में जीवनयापन के लिए कुछ सुविधाएं स्थापित करना आवश्यक है जिनमें पर्यटन का विकास भी शामिल होना चाहिए। ऐसे इलाकों की जो पूंजी है जैसे खनिज, जंगल, फल, फूल इत्यादि इनका राष्ट्र के निर्माण में सदुपयोग करना भी राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा योगदान होगा।

एक और सुझाव है। प्रथम गाँवों को आबाद करने के लिए हम सबको स्थानीय लोगों के सहयोग से कुछ पूर्व सैनिकों को भी ऐसे गाँवों में स्थापित करना चाहिए। यह बहुत सोच-समझकर, संवेदनशील तरीके से, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखकर करना पड़ेगा। इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रांतीय/स्थानीय नेतृत्व को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जब सभी की सहमति हो तब ही यह करना चाहिए। कुछ सहुलियत आपको पूर्व सैनिकों को देनी पड़ेगी जिससे वो ऐसे इलाकों में रहने के लिए आकर्षित होंगे।

प्रादेशिक स्तर

प्रादेशिक स्तर पर भी यह आवश्यक होगा कि इन दूरदराज के इलाकों में जीवनयापन के लिए सारी सुविधाएं स्थापित की जाएं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है:- शिक्षा और स्वास्थ्य। राज्य को शिक्षा से संबंधित सभी सुविधाएं जिनमें उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास आदि शामिल हैं, स्थापित करनी चाहिए। यदि प्रत्येक गाँव में मुमकिन नहीं है तो कुछ गाँवों के समूह में ये सुविधाएं विकसित की जाएं। ध्यान रहे कि गाँवों का समूह इस तरह बनाया जाए जिनमें आपस में यातायात के साधन उपलब्ध हों। स्थान विशेष की और गाँव की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यवसाय और पर्यटन के स्थल भी विकसित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं जैसे कि प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र इन सभी गाँवों में विकसित किए जाने चाहिए। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ गाँवों के समूह में हर सप्ताह जरूर आयें। चिकित्सावाहन (एम्बुलेंस) इत्यादि का भी प्रावधान होना चाहिए। जरूरी सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी इत्यादि का प्रावधान इन गाँवों में जल्द से जल्द विकसित किया जाना चाहिए। जरूरी सेवाओं का विस्तार और उनकी देखभाल एक बहुत ही आवश्यक कार्य हैं। इनका प्रावधान केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सुनिश्चित करना होगा।

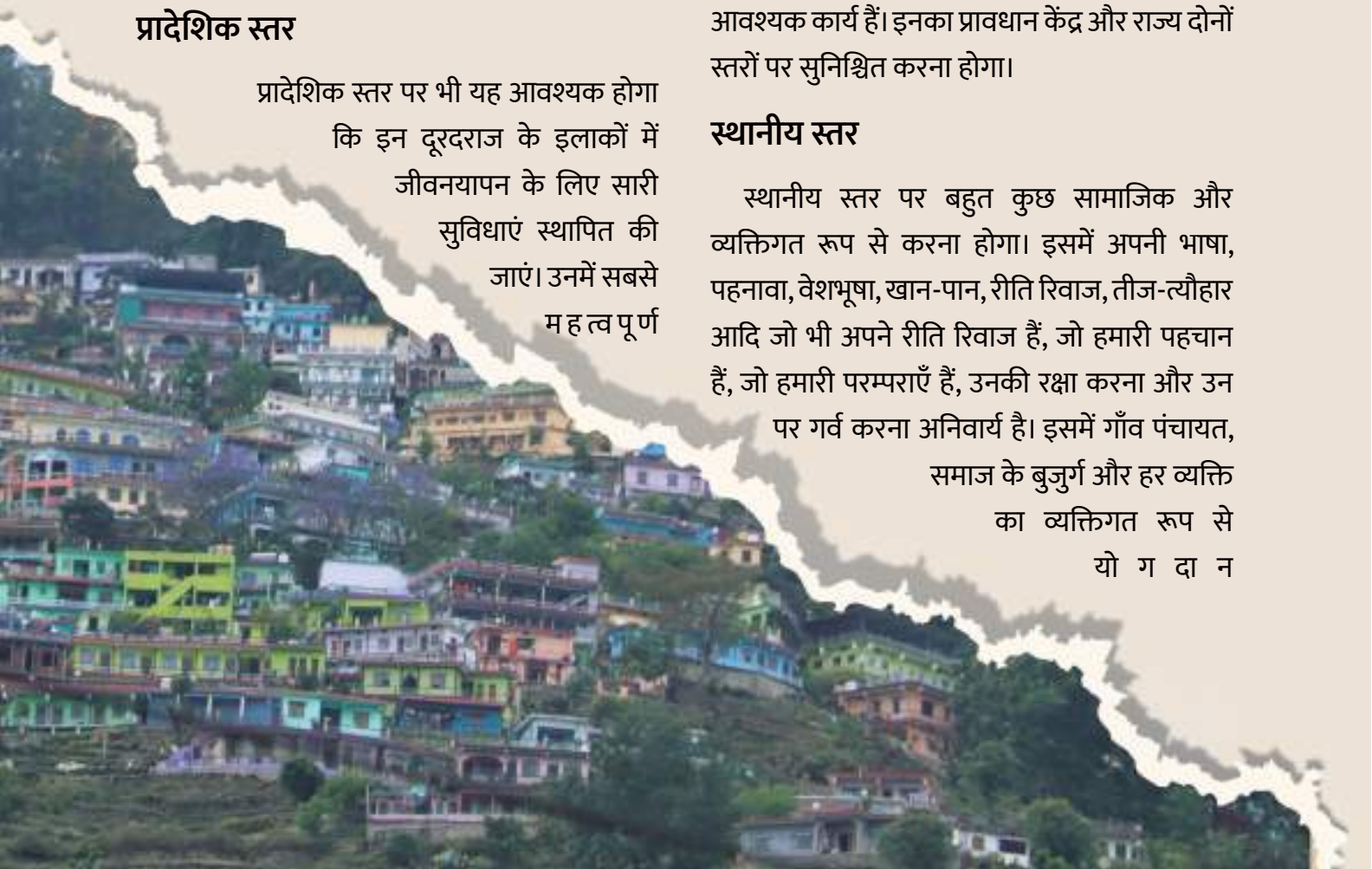

स्थानीय स्तर

स्थानीय स्तर पर बहुत कुछ सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से करना होगा। इसमें अपनी भाषा, पहनावा, वेशभूषा, खान-पान, रीति रिवाज, तीज-त्यौहार आदि जो भी अपने रीति रिवाज हैं, जो हमारी पहचान हैं, जो हमारी परम्पराएँ हैं, उनकी रक्षा करना और उन पर गर्व करना अनिवार्य है। इसमें गाँव पंचायत, समाज के बुजुर्ग और हर व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से योगदान

महत्वपूर्ण है। हम सबको मिलकर, प्रशासनिक अधिकारियों और वरिष्ठजनों के सहयोग से अपनी परंपराओं को जन जन तक पहुंचाना है। इन इलाकों में हर एक गाँव की एक अलग विशेषता है जिनका संरक्षण करना है। उन प्रथाओं का सही मायनों में प्रस्तुत करना है। अगर कुछ भ्रांतियां हैं तो समाज के वरिष्ठजनों के सहयोग से दूर करना है।

इन गाँवों में क्षेत्र विशेष के नागरिकों की कला, कौशल, नृत्य, वेशभूषा, तीज त्यौहार, खान-पान आदि की विशिष्टता है। प्रशासनिक अधिकारियों को और स्थानीय सेना अधिकारियों को इन सब कार्यक्रमों, प्रदर्शनी इत्यादि में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए और स्थानीय निवासियों का हौसला अफजाई करनी चाहिए जिससे उनको अपनी परंपराओं पर गर्व हो। हमारे प्रथम गाँव हमारी संस्कृति, संस्कार, विकास, प्रगति और विरासत के प्रतीक बनें, यह हम सबकी हार्दिक इच्छा है। प्रथम गाँव का विकास और यह निर्धारित करने के लिए कि हमारे इन गाँवों से कोई भी पलायन न हो, इसके लिए सभी स्तर पर लगन, प्रतिबद्धता और परिश्रम की जरूरत है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है और इसलिए एक अहम विषय है। सभी को इस विषय पर आत्ममंथन करना पड़ेगा और जो भी मुमकिन हो उस दिशा में तन, मन और धन से सम्पूर्ण योगदान देना होगा। प्रथम गाँव और जीवन्त (Vibrant) गाँव आपस में एक-दूसरे के पूरक हैं। जीवंत गाँव अभी अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में ही पहचाने गये हैं। करीब तीन हजार जीवंत गाँवों की पहचान हुई है। इसी तरह हमारी सभी जमीनी और समुद्री सीमाओं पर इनकी पहचान कर हमें इन गाँवों का विकास करना है। हमारे युवाओं को शक्ति देनी है। उन्हें अवसर प्रदान करने हैं जिससे वे अपनी क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन कर सकें। दूरदराज के इलाकों में मातृशक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने पड़ेंगे जिससे वे स्वावलंबी बनें और अपने परिवार की प्रगति में सहायक बन सकें।

जब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतीक प्रथम गाँवों को उनका यथोचित सम्मान मिलेगा, ये इलाके राष्ट्र के विकास, प्रगति और विरासत की दृष्टि से हम सबको गौरवान्वित करेंगे तब इन भारत के वीरों का मनोबल बढ़ेगा वो अपनी परंपराओं की रक्षा, अपनी जन्मभूमि की रक्षा और अपने परिवार के हित और कल्याण के लिए अपने गाँव के विकास, प्रगति में तन, मन और धन से योगदान करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा में अति आवश्यक हमारे स्थानीय लोगों का सहयोग मिलेगा। प्रथम गाँव जैसा कि नाम से प्रदर्शित होता है। सदैव प्रथम रहेंगे और अपना महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रीय सुरक्षा में सदैव देते रहेंगे।

सभी को मिलकर ही प्रथम गाँव की परिभाषा को सही मायने में जमीन पर उतारना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रथम गाँव हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक बनेंगे। प्रथम गाँव हमारे आकर्षण का केंद्र बने, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयत्न करना पड़ेगा। हम जरुर कामयाब होंगे इसमें मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है।

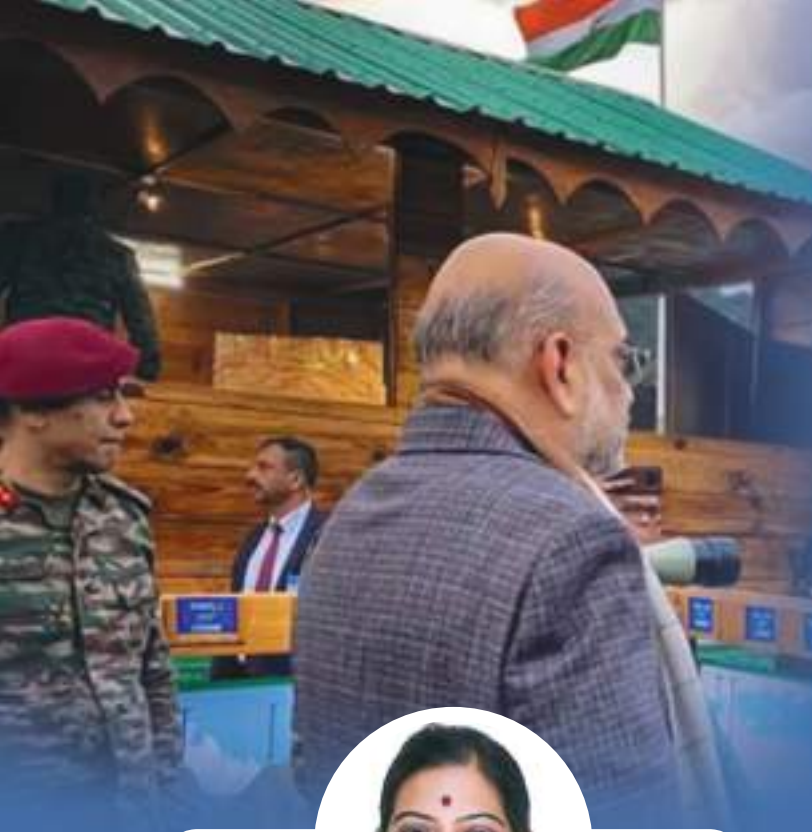

डॉ. हर्षा भार्गवी पंडीरी

लेखक एवं समीक्षक

भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए "ऑरेंज इकोनॉमी" को बढ़ावा देना

परिचय :

जीवित विरासत, जिसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी जाना जाता है, सांस्कृतिक पहचान और विविधता को पोषित करते हुए सतत विकास के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करती है। इसका संरक्षण समुदायों के भीतर आपसी संबंध और पहचान की भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों में परिवर्तन अक्सर इस विरासत के प्रसार को खतरे में डालते हैं। भारत में, जहां सांस्कृतिक विविधता फलती-फूलती है, जीवित विरासत का संरक्षण न केवल सांस्कृतिक संवर्धन के लिए बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी एक अवसर प्रस्तुत करता है।

यह लेख भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाकर और सतत विकास को बढ़ावा देकर सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवासन को रोकने के उद्देश्य से आजीविका के वैकल्पिक समाधानों का अन्वेषण करता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से जीवंत गांवों का दौरा करने का आग्रह करते हुए सांस्कृतिक आदान-प्रदान के महत्व और दूरदराज के सीमावर्ती गांवों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया है। उन्होंने बुनियादी ढांचे, आर्थिक अवसरों और सांस्कृतिक संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए सीमावर्ती गांवों को भारत के "पहले गांव" के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी और एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने में सीमावर्ती गांवों के

राष्ट्रीय महत्व पर भी जोर दिया है।

गुजरात के बनासकाठा में 'नाडाबेट भारत-पाक सीमा' पर्यटन परियोजना का उद्घाटन करते हुए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस परियोजना से 10 वर्षों के भीतर 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बीच संयुक्त उद्यम पर्यटकों को बीएसएफ कर्मियों के बारे में जानने और विभिन्न खेल और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।

भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का लाभ उठाना

भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक अक्षुण्ण संपत्ति के रूप में इसकी सांस्कृतिक एवं आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वास्तुकला से लेकर संगीत तक की विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं देश के रचनात्मक परिदृश्य की नींव हैं, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद को समृद्ध करती हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के अध्ययन से पता चलता है कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक जीडीपी में लगभग 3% का योगदान देती है।रचनात्मक अर्थव्यवस्था को अब "नारंगी अर्थव्यवस्था"(ऑरेंज इकोनॉमि) के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा और सांस्कृतिक प्रेरणा का मिश्रण शामिल है।

रचनात्मक अर्थव्यवस्था वार्षिक राजस्व में 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का उत्पादन करती है और विश्व स्तर पर लगभग 50 मिलियन रोजगार के अवसर प्रदान करती है। रचनात्मक व्यवसायों में गैर-रचनात्मक व्यवसायों की तुलना में 88% अधिक वेतन मिलता है। इसके अलावा, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) जैसी पहल रचनात्मक अर्थव्यवस्था की क्षमता को उजागर कर सकती है, विशेष रूप से स्थानीय कलाकार समुदायों को सशक्त बनाकर और नवाचार-आधारित रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देकर। हालांकि, इस क्षेत्र के लाभों को पूरी तरह से भुनाने के लिए आंकड़ों की कमी और अनौपचारिक क्षेत्र के प्रभुत्व जैसी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।

बढ़ते प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियाँ

बढ़ते प्रवास के कारण भारत को अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पारंपरिक मूल्यों, रीति-रिवाजों और भाषाओं का ह्रास हो सकता है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विशिष्ट पहचान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए, सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने, ऐतिहासिक स्थलों और कलाकृतियों को संरक्षित करने और सांस्कृतिक संरक्षण का समर्थन करने वाली नीतियों को लागू करने जैसे उपाय सहायक हो सकते हैं। भारत ने शास्त्रीय संगीत और नृत्य विधाओं को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करने और सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना जैसी पहल की है ताकि भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। आज की वैश्वीकृत दुनिया में सांस्कृतिक प्रथाओं का विलय और विघटन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

भारत ने सांस्कृतिक प्रथाओं की सुरक्षा के लिए नियम लागू कर सांस्कृतिक अधिकारों की सार्वभौमिकता में योगदान करने के प्रयास किए हैं और प्रवास के बावजूद उनके संरक्षण को सुनिश्चित किया है। इन प्रयासों में सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं की मान्यता और संरक्षण शामिल हैं। भाषा क्षय/भाषा हानि व सांस्कृतिक विशिष्टता पर इसका प्रभाव भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। सांस्कृतिक केंद्रों व संग्रहालयों की स्थापना, त्यौहारों और सांस्कृतिक एकीकरण कार्यक्रमों को लागू करके प्रवासन के बीच अपनी

सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए भारत ने कदम उठाये हैं। मानव संस्कृतियों की समृद्ध विविधता को संरक्षित करने के लिए सांस्कृतिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और संग्रह करना महत्वपूर्ण है।

सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के माध्यम से प्रवासन की विवेचना

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई 2020 से 2021 तक भारत में 28.9 प्रतिशत प्रवास दर की सूचना दी, जिसमें 51.8 प्रतिशत ग्रामीण और शेष शहरी क्षेत्रों में है। अधिकांश प्रवासन एक ही राज्य के भीतर हुआ, जिसमें 92.6% महिलाएं और 65.6% पुरुष एक ही राज्य के भीतर गतिशील रहे । प्रवासन दर राज्य के भीतर 87.5% थी, जिसमें 11.8% प्रवासी दूसरे देश में जा रहे थे। भारत में, 55 प्रतिशत प्रवास ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, जिसमें महिला प्रवासियों को मुख्य चालक माना गया। इस दशक में आंतरिक प्रवासियों की संख्या में 45 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें अंतः-राज्यीय प्रवासियों का 2011 में कुल प्रवासियों का 86.8 प्रतिशत और 2001 में 83.7 प्रतिशत था। अधिकांश आंतरिक प्रवासी अल्प दूरी के अंतः-राज्यीय प्रवासी हैं, अन्य विकासशील देशों की तुलना में लंबी दूरी के अंतर-राज्यीय प्रवास की दर कम है।

भारत में प्रवास की दर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आजीविका के वैकल्पिक साधनों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर, समुदाय न केवल अपनी विरासत को संरक्षित कर सकते हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर स्थायी आर्थिक अवसर भी पैदा कर सकते हैं। कला और शिल्प क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षमता निर्माण की पहल स्थानीय कारीगरों को सशक्त बना सकती है और प्रवास के दबाव को कम कर सकती है। इस प्रयास में मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण कदम हैं।

सरकारी पहल और कार्यक्रम

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) और प्रसाद योजना जैसी सरकारी पहल सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) को 15 फरवरी, 2023 को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय व्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की उत्तरी सीमा के निकट 19 जिलों के 46 ब्लॉक के चुनिंदा गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसका उद्देश्य कृषि, बागवानी, पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत, कौशल विकास, उद्यमिता, सहकारी समितियों, सड़क संपर्क, आवास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, टेलीविजन व दूरसंचार संपर्क और वित्तीय समावेशन के माध्यम से आजीविका के अवसर पैदा करना है। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और स्थानीय परंपराओं को प्रकाश में लाने/ बढावा देने के प्रयास इन कार्यक्रमों का अभिन्न अंग हैं।

सीमा पर्यटन: विकास और संरक्षण के बीच संतुलन

सीमा पर्यटन में आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं हैं लेकिन विकास और संरक्षण के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। गुजरात में नाडाबेट भारत-पाक सीमा पर्यटन परियोजना जैसी पहल स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए पर्यटन के अवसरों का लाभ उठाने के प्रयासों का उदाहरण है। इसके अलावा विनियमों को आसान बनाना और स्थानीय लोगों और रक्षा कर्मियों के बीच विश्वास को बढ़ावा देना सीमा पर्यटन की पूरी क्षमता को उजागर करता है, जिससे आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों में भागीदारी

निभायी जा सकती है।

सामुदायिक और सांस्कृतिक पर्यटन: स्थानीय अनुभवों का लाभ उठाना:

सामुदायिक और सांस्कृतिक पर्यटन यात्रियों को स्थानीय समुदायों और परंपराओं के साथ जुड़ने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। जबकि सामुदायिक पर्यटन प्रत्यक्ष बातचीत और प्रामाणिक अनुभवों पर जोर देता है, सांस्कृतिक पर्यटन सांस्कृतिक कलाकृतियों का अवलोकन और सराहना करने पर केंद्रित है। पर्यटन के इन रूपों के बीच अंतर को समझना उन अनुभवों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है जो विविध पर्यटक हितों और प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समुदायों के हितों की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमूर्त सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा और बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करके, समुदाय न केवल अपनी विरासत को संरक्षित कर सकते हैं, बल्कि आर्थिक अवसर भी पैदा कर सकते हैं। मौखिक परंपराओं, प्रदर्शन कलाओं और पारंपरिक शिल्प कौशल जैसी पहल आय सृजन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए अवसर प्रदान करती है, जिससे सतत विकास और शांति में योगदान मिलता है। एक समुदाय-आधारित दृष्टिकोण एक व्यापक दृष्टिकोण है जो एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की उत्पत्ति से परे फैला हुआ है, जो बाहरी सुविधाओं की मौजूदा प्रक्रियाओं को बाधित किए बिना खुद को स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है, साथ ही मौलिकता की रक्षा करता है। यह दृष्टिकोण समुदायों और जटिल वास्तविकताओं पर आधारित है जिसके भीतर एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तत्व मौजूद हैं। यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तत्व को पहचानने और स्थायी रूप से संरक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इस हेतु कोई एकल मॉडल नहीं होने के कारण , यह आवश्यक है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए व्यवहार्य तौर-तरीकों को खोजने के लिए विभिन्न समुदायों, समूहों और व्यक्तियों के साथ जुड़ा जाये ।

निष्कर्ष

आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में जीवित विरासत का संरक्षण और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना आवश्यक है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाकर, स्थानीय समुदायों में निवेश करके और सहायक नीतियों को लागू करके, प्रवासन को कम करना और सीमावर्ती क्षेत्रों की पूरी क्षमता को उजागर करना संभव है। सरकार, समुदायों और हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां सांस्कृतिक विविधता पनपेगी और सतत विकास फलेगा-फूलेगा।

“सुचेतगढ़: जम्मू का एक महत्वपूर्ण प्रथम गाँव”

राजेश्वर सिंह ‘राजू’

हिंदी, डोगरी और अंग्रेजी भाषाओं
के वरिष्ठ लेखक

जम्मू और कश्मीर को भारत का मणि मुकुट कहा जाता है । सन 1947 में भारत स्वतंत्र तो हुआ लेकिन द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर चलते हुए दो भागों में विभाजित कर दिया गया। उस समय जम्मू व कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था । पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सेना को कबायलियों के भेष में भेज कर जम्मू व कश्मीर पर कब्जा करने के लिए आक्रमण कर दिया। तब विकट परिस्थितियों में भारत सरकार ने अपनी सेना भेजकर जम्मू व कश्मीर को उनसे बचाया। 26 अक्तूबर 1947 को जम्मू व कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने यहां के निवासियों की भावनाओं का मान रखते हुए भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के विलय के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करके इसे भारत का अभिन्न अंग बनाया।

इस केंद्र शासित प्रदेश की अधिकतर सीमा पाकिस्तान से लगती है । इसका मुख्य कारण यह है कि जम्मू और कश्मीर एक बड़ी रियासत थी जो 1947 में पाकिस्तानी आक्रमण के चलते दो भागों में विभाजित हो गई और बहुत सारा भाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया जिसे पाक अधिकृत जम्मू व कश्मीर कहा जाता है। हालांकि इस भाग में पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त करके भारत में विलय होने के लिए वहां के नागरिकों का निरंतर संघर्ष जारी है। भारत के विभाजन और जम्मू व कश्मीर के कुछ भाग पर पाकिस्तान के कब्जे के कारण यहां पर एक तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है तो दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एल ओ सी है । सीमावर्ती स्थानों पर रहने वाले लोगों को दोनों देशों के बीच में

परस्पर संबंध अच्छे नहीं होने के कारण बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, विशेषकर पाकिस्तान की तरफ से निरंतर भड़काने वाली गतिविधियां की जाती हैं जिससे भारत में अस्थिरता पैदा हो तथा आतंकवाद पनपे ।

भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान न केवल यहां पर रहने वाले असामाजिक तत्वों को शह देता है, धार्मिक कार्ड खेलता है बल्कि इसके लिए वहां की सरकार पाकिस्तानी रेंजरों के संरक्षण में इन सीमाओं के रास्ते आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करवाती है और इस गतिविधि को समुचित रूप में सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए सीमावर्ती गाँवों में गोलीबारी करके कवर फायर देकर उनकी सहायता की जाती है। भारतीय सेना को गोलीबारी में उलझा कर आतंकवादियों को सीमा पार करवाई जाती रही है। लेकिन जिस तरह अतीत में यह बड़े सुगम तरीके से हो जाता था, अब असंभव है । इसके पीछे वर्तमान भारत सरकार की इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और सीमा पर तैनात फौजियों को हर संभव उपकरण उपलब्ध करवाना भी मुख्य कारण है। सीमावर्ती गाँवों में आ रहे बदलाव को एक गाँव के उदाहरण से समझा जा सकता है।

केंद्र शासित जम्मू व कश्मीर के जम्मू संभाग में जम्मू शहर से सुचेतगढ़ लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर रणवीर सिंह पुरा यानी आरएस पुरा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित एक छोटा सीमावर्ती गाँव है। इस गाँव की जनसंख्या लगभग 500 होगी। यहां से पाकिस्तान का सियालकोट शहर लगभग 11 किलोमीटर तथा लाहौर 141 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गाँव की भूमि काफी उपजाऊ है और यहां पर ज्यादातर गेहूं और उम्दा किस्म की बासमती की खेती की जाती है। यह बासमती विश्व भर में प्रसिद्ध है।

एक सीमावर्ती गाँव होने के कारण यहां रहने वालों का जीवन कष्टों भरा रहा है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आता और अक्सर कोई ना कोई ऐसी हरकत सीमा पर करता रहता है जिसका परिणाम सीमा के इस तरफ रहने वाले लोगों विशेषकर किसानों को भुगतना पड़ता है। एक तो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता और दूसरा वहां की सरकार की बदनीयत दोनों देशों के बीच परस्पर अच्छे संबंध रहने ही नहीं देती । किसी न किसी कारण द्वेष और दुश्मनी के संकेत देने के लिए पाकिस्तान रेंजर आतंकवादियों की भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने के लिए सहायक साबित होते हैं । इस सबसे बचाव के लिए हमारी सेना को विशेष चौकसी बरतनी पड़ती है जिस कारण चेकिंग अधिक करनी पड़ती है जो कहीं ना कहीं आम नागरिकों के लिए भी परेशानी का कारण बनता है। यह सत्य है कि आतंकवाद पनपने से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बनिस्बत अच्छे होने के चलते दोनों तरफ के सीमावर्ती गाँवों के बहुत से लोग अवैध धंधों में संलिप्त रहते थे। दोनों और से स्मगलिंग का धंधा जोरों पर था। लेकिन जब से आतंकवाद ने सिर उठाना शुरू किया और पड़ोसी देश आतंकवादियों को पनाह देने लगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई तो इन लोगों पर नकेल कसी गई तथा सीमा पार आना- जाना असंभव हो गया। फिर भी पड़ोसी देश अक्सर किसी न किसी तरह आतंकवादियों को सीमा पार करवाने के लिए अपने रेंजरों का सहारा लिया करता है।

जब कभी भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अधिक कड़वाहट ले बैठते हैं तो सीमा पार से होने वाली गोलीबारी से यहां के नागरिकों को भारी नुकसान तो पहुंचता ही है साथ ही उनकी फसलों को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है जिससे आर्थिक तौर पर उनका जीवन यापन और भी कठिन हो जाता है। सीमा से सटे गाँव से लोगों को पीछे की तरफ हटना पड़ता है तथा अस्थाई रूप में किसी और स्थान पर स्थानांतरित होकर परिस्थितियों के बदलने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

जम्मू व कश्मीर का यह क्षेत्र क्योंकि काफी उपजाऊ

क्षेत्र है, दुश्मन देश भारत के किसानों को हानि पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है। यह सत्य है कि जब भी सीमा पार से गोलीबारी की जाती है तो यहां के निवासियों को अपना जीवन बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है । इसी के मद्देनजर यहां पर सीमा पार की नापाक हरकतों से यहां के निवासियों को बचाने के लिए पक्के बंकर भी बनाए गए । अतीत में इन बंकरों के अभाव में यहां के लोगों को काफी नुकसान भुगतना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने पक्के बंकर बनवाकर यहां के निवासियों को काफी राहत दी है।

जिस तरह से वाघा बॉर्डर अमृतसर में 'बीटिंग दी रिट्रीट' समारोह किया जाता है, इसी तर्ज पर सुचेतगढ़ में भी अब सप्ताह में चार बार 'बीटिंग दी रिट्रीट' कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के सैनिक भाग नहीं लेते हैं । यह दोनों देशों के बीच में संबंधों को सुधारने का एक प्रयास है, इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से संबंधों में कहीं भी आत्मीयता नज़र नहीं आती। जब संबंधों में कड़वाहट अधिक आ जाती है तो अक्सर यहां पर होने वाला यह कार्यक्रम स्थगित भी करना पड़ता है, जो वाघा बॉर्डर अमृतसर में बहुत कम देखने को मिलता है।

वेटलैंड घराना

सुचेतगढ़ गाँव के पास ही विश्व प्रसिद्ध वेटलैंड घराना है जहां पर दुनिया भर से पक्षी प्रवास करने के लिए आते हैं । इन प्रवासी पक्षियों के कारण घराना गाँव का वेटलैंड विश्व के मानचित्र पर अपनी उपस्थिति अंकित करवाता है। अभी हाल ही में वन्यजीव विभाग ने लगभग 400 कनाल भूमि का अधिग्रहण किया है, जिससे वेटलैंड में पानी के स्तर में काफी सुधार आया है , जिस कारण सर्दियों में प्रवासी पक्षियों की संख्या में और भी बढ़ोतरी होगी। वन्यजीव विभाग द्वारा इस अधिगृहित भूमि पर जियो टैग स्तंभ लगाकर भविष्य में किसी भी ऐसे प्रयास कि इस भूमि पर अतिक्रमण किया जा सके, को विफल करने की यह एक प्रशंसनीय पहल है।

यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कई वर्षों से घराना वेटलैंड कई कारणों के चलते सिकुड़ रहा था, जिसमें आसपास के घरों से वेटलैंड में गंदे पानी का निकास तथा संबंधित विभाग की

The Hindustan Times

KASHMIR ACCEDES TO INDIA

PLEBISCITE SOON ON RULER'S DECISION

SHEIKH ABDULLA TO FORM INTERIM GOVT.

लापरवाही भी काफी हद तक उत्तरदायी थी। देर आए, दुरुस्त आए, अब इस दिशा में प्रशासन काफी सराहनीय कार्य कर रहा है ।

यह उल्लेखनीय है कि विश्व के कई देशों से विभिन्न प्रजातियों के अप्रवासी पक्षी यहां पर आते हैं जिनमें साइबेरिया से आने वाले पक्षियों की तादाद अधिक रहती है। जब मौसम अपने यौवन पर रहता है तो उस दौरान घराना वेटलैंड मध्य एशिया से हजारों प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है जिन में मंगोलिया, रूस, चीन आदि देश प्रमुख हैं। इन पक्षियों को देखने के लिए यहां पर पर्यटकों की काफी भीड़ रहती है, विशेषकर बच्चे इन्हें देखकर बहुत आनंदित होते हैं। उस दौरान यहां पर एक मेले जैसा वातावरण रहता है । इसी को भुनाने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से सुचेतगढ़ और घराना वेटलैंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं, जिसे 'बॉर्डर टूरिज्म' या 'सीमा

पर्यटन' का नाम दिया गया है। इसके आकर्षण का एक मुख्य कारण यह है कि सीमा से सटा यह क्षेत्र जहां अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण सभी का मन मोह लेता है वहीं दुनिया भर से आने वाले विभिन्न प्रजातियों के पक्षी भी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहते हैं। सीमा से सटे हुए गाँव के निवासियों के जीवन को खंगाला जाए तो यह सत्य है कि पड़ोसी देश की तरफ से फैलाई जाने वाली दहशत के चलते ऐसे हालातो में जीवन यापन करना कोई आसान बात नहीं है । कभी भी माहौल खराब हो सकता है और फिर दुश्मन देश कब क्या कदम उठा ले , यह भी अपने आप में परेशानी का कारण है । इसीलिए भारत सरकार की तरफ से सीमावर्ती गाँवों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं । भारत सरकार ने जब 05 अगस्त 2019 को जम्मू व कश्मीर को धारा 370 से निजात दिलाई तभी से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में विकास नई ऊंचाइयां छू रहा है और सीमावर्ती गाँव सुचेतगढ़ या साथ लगते क्षेत्र भी इस बदलाव से अछूते नहीं हैं। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना पर भी शीघ्र ही काम होने के संभावना है। जो गाँव दशकों से यातायात संबंधी परेशानियों से जूझता रहा, वहां पर नई सुबह की गवाही देती सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं है। ऐसा लगता है कि गाँव का कायाकल्प हो गया हो, हालांकि भविष्य में भी कई योजनाओं पर बढ़-चढ़कर कार्य होने की संभावनाए हैं।

यह सत्य है कि सीमावर्ती गाँव में रहने वाले लोग भी सीमा प्रहरी ही हुआ करते हैं। सीमा पार से होने वाली हर गतिविधि का पहला संकेत इन्हें मिलता है। सीमा पर तैनात फौजियों के साथ इनका मेल मिलाप और अक्सर सूचनाओं का आदान-प्रदान भी सीमा की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर यह कहा जाए कि यहां एक तरफ फौजी वर्दी में तैनात रहते हैं वहीँ सीमा पर रहने वाले लोग बिना वर्दी के प्रहरी का ही कार्य करते हैं। भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर का प्रशासन इस बात से भली भांति परिचित है। इन सीमा प्रहरियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं और यह बदलाव धरातल पर देखा भी जा सकता है।

हुसैनीवाला: ऐतिहासिक महत्व वाला पंजाब का प्रथम गाँव

ब्रिगेडियर संसार वर्मा (सेवानिवृत्त)

यूपीएससी में डीआइजी, कॉर्पोरेट ऑफिस में वीपी, वीसी व पूर्व इंटरव्यूइंग ऑफिसर

आजादी के बाद हमने यह विजन रखा था कि भारत का विकास गाँवों से शुरू होना चाहिए लेकिन इसके विपरीत यह देखा गया है कि जहां बड़े शहरों और कस्बों का तेज गति से विकास हुआ, वहीं खासकर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास वाले गाँव हर क्षेत्र में उपेक्षित रहे। गाँवों की लगभग 75% पुरुष आबादी केवल कृषि और संबन्धित गतिविधियों में लगी हुई है। लोग स्वच्छ पानी, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इसलिए, हमारे गाँवों को भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में लाना बहुत महत्वपूर्ण है। हालाँकि, यह देखकर अच्छा लगता है कि अब वर्तमान सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य , कृषि आय, सड़क और रेल संचार, पर्यावरण, संस्कृति और कृषि-आधारित उद्योग के क्षेत्र में गाँवों के विकास को आवश्यक प्राथमिकता दे रही है।

इसी उद्देश्य से पंजाब के सीमावर्ती गाँवों में से एक गाँव का विभाजन से पहले और बाद का एक महान इतिहास है, जो लोगों, विशेषकर छात्रों को इस सीमावर्ती गाँव का दौरा करने और जिन शहीदों ने हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही, गाँवों का अध्ययन और अंतर्दृष्टि छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां उन्हें गाँवों की प्रत्यक्ष जानकारी मिल सकती है। यहाँ

का जीवन सरल है, पर्यावरण अच्छा है, लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं, परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं तथा माता-पिता/बुजुर्गों की अधिक देखभाल होती है।

हुसैनीवाला गाँव पाकिस्तान से लगी पंजाब सीमा का 'पहला गाँव' है। पाकिस्तान के गाँव गंडा सिंह वाला के सामने जीरो पॉइंट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। इसका नाम एक मुस्लिम पीर बाबा गुलाम हुसैनीवाला के नाम पर रखा गया है, जिनकी कब्र बीएसएफ परिसर में है। गाँव के आस-पास छोटे गाँवों के कुछ समूह भी हैं। यह फिरोजपुर शहर से लगभग 11 किमी दूर सतलुज नदी के तट पर स्थित है।

इस गाँव का विशेष ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसमें महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा इसमें एक और महान देशभक्त बटुकेश्वरदत्त की भी मूर्ति है। याद रखना चाहिए कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली में ग्रेनेड फेंका था और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालाँकि, स्थितियाँ बिगड़ने की आशंका से तीनों राष्ट्रवादियों को निश्चित तिथि से एक दिन पहले फाँसी दे दी गई। बाद में बड़े सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन तीन देशभक्त युवाओं के बलिदान के कारण ही भारत ने 1931 में अपना राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाया। ऐतिहासिक रूप से पेशावर को मुंबई से जोड़ने वाली रेलवे लाइन 1885 में बनाई गई थी, जो हुसैनीवाला से होकर गुजरती थी। विभाजन से पहले के दिनों में मुंबई, दिल्ली, फ़िरोज़पुर, लाहौर और पेशावर शहरों को जोड़ने वाली पंजाब मेल हुसैनीवाला गाँव से होकर गुजरती थी। विभाजन के दौरान सीमा सतलज नदी के साथ खींची गई और हुसैनीवाला गाँव से होकर गुजरी। यह गाँव भारत और पाकिस्तान के बीच दो बड़े खूनी युद्ध देख चुका है।

गाँव की कुल जनसंख्या लगभग 15000 है और लगभग 7000 मतदाता हैं। अधिकतर आबादी राय सिख समुदाय की है, जो सिख धर्म का पालन करते हैं। दुर्भाग्य से कुछ गाँवीण सिख धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। जो एक अनुचित प्रथा है और इसकी जाँच की जानी चाहिए। इस क्षेत्र में एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च माध्यमिक विद्यालय और आठ प्राथमिक विद्यालय हैं। यहां कोई उद्योग नहीं है और गाँवीणों का व्यवसाय केवल खेती और मजदूरी करना है।

उपलब्धियां

- श्री अमनदीप सिंह ने रोइंग में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है।
- श्री साहिब सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स का प्रतिनिधित्व किया है।
- इस गाँव की चार लड़कियों (अंजू, लखविंदर कौर, गगनदीप और पूजा) ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीते।
- गाँव में एक "राधा स्वामी सत्संगघर" है जहाँ नशेड़ी लोगों को सुधार कर मुख्य धारा में लाया जा रहा है।

हुसैनीवाला में भारत-पाक युद्ध 1965

1965 के दौरान, टैंकों के साथ इन्फैंट्री ब्रिगेड के अचानक हमले के खिलाफ एक मराठा इन्फैंट्री बटालियन ने हुसैनीवाला (भारत की ओर से सतलज नदी के पीछे एक परिक्षेत्र) की रक्षा की। शुरुआत में कुछ क्षेत्रों को खोने के बाद भारतीय सेना ने पाक सेना पर हमला किया और उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। गाँव वालों ने सैन्य बलों को ताजा भोजन और घायल सैनिकों को निकालने में सहायता की। स्थानीय लोगों ने हमारी सेना को दुश्मन की अहम जानकारियां भी मुहैया कराईं।

हुसैनीवाला में भारत-पाक युद्ध 1971

हुसैनीवाला गाँव बिल्कुल बॉर्डर पर है। इसका गाँवीण इलाका नदी के तट पर है और सुरक्षात्मक रूप से बांधों से घिरा हुआ है। यह गाँव आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गंग नहर प्रणाली को पोषित करने वा ले

हुसैनीवाला हेडवर्क का एक हिस्सा है। राजनीतिक दृष्टि से यह शहीद स्मारक के कारण महत्वपूर्ण है। सैन्य दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र हेडवर्क और सड़क पुल को गहराई प्रदान करता है। 1971 के युद्ध के दौरान इस गाँव पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। हालाँकि, बाद में पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र को खाली कर दिया था। हुसैनीवाला गाँव के पीछे एक नदी होने के कारण इस क्षेत्र में घुस सकने वाले सैनिकों और टैंकों की ताकत को सीमित करता है। यह भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है ।

राष्ट्रीय शहीद स्मारक

इस स्मारक का भारत के लिए बहुत बड़ा राष्ट्रीय और भावनात्मक महत्व है। क्योंकि 23 मार्च 1931 को यहां महान देशभक्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार किया गया था। यह बटुकेश्वरदत्त का अंतिम संस्कार स्थल भी है, जो केंद्रीय विधान सभा पर बमबारी में भी शामिल थे। यह स्मारक इन तीन राष्ट्रीय शहीदों की क्रांतिकारी भावना को दर्शाता है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए शहादत देकर स्वतंत्रता की शाश्वत लौ जलाई। जब भारत आजाद हुआ तो हुसैनीवाला गाँव पाकिस्तान में चला गया। हालाँकि, भारत हुसैनीवाला गाँव को उसके महत्व के कारण वापस चाहता था, और इसे पाने के लिए, भारत को जनवरी 1961 में फाजिल्का के पास पाकिस्तान को 12 गाँव देने पड़े। इन महान देशभक्तों की याद में हर साल 23 मार्च को स्मारक पर एक वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है।

घूमने के लिए आसपास के महत्वपूर्ण स्थान

- **बीएसएफ द्वारा फ्लैग बीटिंग रिट्रीट समारोह-**

हुसैनीवाला सीमा पर, बीएसएफ द्वारा हर दिन शाम 6 बजे एक फ्लैग बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाता है। यह एक पर्यटक आकर्षण के रूप में जनता के लिए खुला है। यह वैसा ही है जैसा अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर हो रहा है। यहां समारोह में भाग लेने वाले भारतीय और पाकिस्तानी लोग अक्सर मुस्कुराते हैं और एक-दूसरे की ओर हाथ हिलाते हैं। यहां तक कि समारोह आयोजित करते समय एक-दूसरे के गार्डों की जय-जयकार भी करते हैं। अटारी सीमा पर तनावपूर्ण माहौल के विपरीत यह देखने लायक समारोह है।

- **सारागढ़ी स्मारक-**

इसका निर्माण 31 सिख रेजिमेंट के 21 सिख सैनिकों की याद में किया गया था, जो 1887 में वजीरिस्तान

में सारागढ़ी किले की रक्षा करते हुए दस हजार पठानों के हमले के खिलाफ वीरतापूर्वक शहीद हो गए थे। मेमोरियल गुरुद्वारा इन बहादुर सैनिकों के सम्मान में सेना अधिकारियों द्वारा बनाया गया था। हर साल 12 सितंबर को इन बहादुर सैनिकों की याद में स्मारक में एक धार्मिक सभा आयोजित की जाती है।

- **हरिके वन्य-जीवन अभयारण्य-**

हरिके न केवल पंजाब बल्कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण वन्य-जीवन अभयारण्यों में से एक है। यह फिरोजपुर के निकट ब्यास और सतलुज नदियों के संगम पर स्थित है। इसे 1990 में यूएनडीपी के तहत इंटरनेशनल बॉडी ऑफ वेटलैंड्स द्वारा मान्यता दी गई है। यह बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों के लिए एक शरणस्थली है।

- **आंग्ल-सिख युद्ध स्मारक-**

कोई भी देश उन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूल सकता, जिन्होंने हम सभी को आजादी दिलाने के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। फ़िरोज़शाह, मुदकी, अलीवाल और सबराँव की आंग्ल-सिख लड़ाई का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। ये छोटी लेकिन बहुत तीखी लड़ाइयाँ थीं जिनमें अंग्रेजों को भारत में पिछले किसी भी अवसर की तुलना में अधिक भयंकर आमने-सामने की लड़ाई का अनुभव हुआ। यह लड़ाई 1845 में सिखों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच हुई थी। 54 अधिकारियों सहित 745 ब्रिटिश सैनिक मारे गए और 1625 घायल हुए। स्मारक में इन ऐतिहासिक युद्धों से संबंधित पेंटिंग और कलाकृतियाँ भी हैं।

- **बर्की स्मारक-**

बर्की स्मारक का निर्माण 1969 में उन सैनिकों की स्मृति को बनाए रखने के लिए किया गया था जिन्होंने 1965 में युद्ध के मैदान पर सर्वोच्च बलिदान दिया था और लाहौर से लगभग 22 किमी दक्षिण पूर्व की दूरी पर स्थित बर्की शहर के विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। यह स्मारक अब सारागढ़ी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है जिसके केंद्र में एक स्तंभ, एक पैटन टैंक और एक बर्की मील का पत्थर है स्मारक में ढलाई और नक्काशी शास्त्रीय भारतीय स्थापत्य शैली में है।

- **गुरुद्वारा श्री जमनी साहिब-**

यह फिरोजपुर में शहर से लगभग 8 किमी दूर स्थित है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मुक्तसर साहिब की लड़ाई के बाद यहां आये थे। ऐसा माना जाता है कि एक जाट किसान ने गुरु साहिब की गारंटी पर एक ब्राह्मण से कुछ पैसे उधार लिए थे। लेकिन उसने पैसे नहीं लौटाए और उसकी मौत हो गई। अपने दूसरे जन्म में वह तीतर (कबूतर) बन गया और ब्राह्मण बाज़ (बाज़) बन गया। जब गुरु साहिब यहाँ आये तो उन्होंने बाज़ से तीतर को मरवा दिया और उस मामले में जो गारंटी दी थी, उससे उसे मुक्त करवा लिया।

निष्कर्ष

किसी राष्ट्र, क्षेत्र, समुदाय या समूह की पहचान उसके अतीत में निहित होती है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, जो उस समाज के लिए अद्वितीय है और मानव जाति की समृद्ध और विविध रचनाओं को दर्शाती है। इतिहास हमारे गाँवीण इलाकों के अतीत से लेकर वर्तमान तक समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तनकारी प्रक्रिया को भी विस्तार से बताता है। हमारे गाँव, विशेषकर सीमाओं के पास, विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएँ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखते हैं। जो उनकी विशिष्ट पहचान और विशिष्टता बनाते हैं। ये ऐतिहासिक स्थान और स्मारक हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि गाँवों के अतीत की गतिविधियों के इतिहास और साक्ष्य को जानना मौलिक है जो लोगों को व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है। निस्संदेह, ऐतिहासिक विरासत, जिसमें युद्ध स्मारक और हुसैनीवाला जैसे गाँव शामिल हैं, का आंतरिक मूल्य है और यह हमें अपने इतिहास और परंपराओं को परखने में मदद करता है और हमें अपने बारे में जागरूकता विकसित करने में सक्षम बनाता है।

हिन्द-पाक सीमा प्रहरी: ठाकुर बलवंतसिंह बाखासर

पदम सिंह राठौड़

लेखक इतिहास के सहायक आचार्य हैं।

राजस्थान वीर प्रसूता भूमि है। आजादी से पहले यह क्षेत्र राजपूताना कहलाता था। यहाँ आजादी से पूर्व 19 रियासतें व 03 ठिकाने और अनेक जागीरें थी। 15 अगस्त 1947 में अखण्ड भारत के दो टुकड़े हो गये, भारत खंडित जो गया और सीमाओं में विभक्त हो गया। राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण हुआ। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्नताएं और विषमताएं पाई जाती हैं- यहाँ कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और मरूस्थलीय धोरे, बंजर रण, ऊँचे-ऊँचे टीब्बों से आच्छादित हैं । यहाँ तापान्तर दर सर्वाधिक है, वर्षादर न्यूनतम है, मौसम में प्रतिकूलताएँ है। मरूस्थलीय भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक 60 प्रतिशत है। राजस्थान, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की पाकिस्तान से 1070 किमी. सीमा लगती हैं। जिसमें बाड़मेर,जैसलमेर,बीकानेर,गंगानगर जिले हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले की सीमा पर हिन्द-पाक सीमा 1993 से पहले खुली थी जहां पर समय-समयान्तर पाकिस्ताान के घुसपैठियों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता था। घुसपैठिये, चोर, डाकू, तस्कर, आतंकवादी के रूप में अवांछित गतिविधियों में संलग्न रहते थे। सीमावर्ती

लोगों का जीवन दुष्कर कर दिया। वे उनके माल-मवेशी और धन की चोरी करते थे। वे छद्म युद्ध करते रहते थे। सीमावर्ती इलाकों में अवैध प्रवेश कर घुसपैठ को अंजाम देते थे, जान-माल का खतरा रहता था ।

सीमावर्ती लोग उनके काले कारनामों से और अन्याय से दुःखी थे। हमारी भारत की सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं थी। भौगोलिक प्रतिकूलता, विषमता और विभिन्न विविधता के कारण सीमाओं की चौकसी करना दुष्कर था। फिर भी सीमावर्ती गाँवों के बाशिंदों द्वारा सेना को भरपूर सहयोग दिया जाता रहा। पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर जिले के गाँवो में अनेक सीमावर्ती व्यक्तियों ने इस सीमावर्ती सामरिक परिस्थिति में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। जिसमें हेम सिंहजी चैहटन, शौयचक्र विजेता चुतर सिंह भोपा, केसरसिंह भोपा, इजताराम भील, सांगाराम भील , लख सिंह धोनिया , चंदन सिंह देदूसर और ठाकुर बलवंतसिंह बाखासर अग्रगण्य हैं।

नाडोला चैहान शाखा में ठाकुर बलवंतसिंह बाखासर का जन्म 23 दिसम्बर 1925 को हुआ । इनके पिता का नाम राण सिंह था। इनका विवाह कच्छ के विजयासर जाड़ेजा ठिकाने में अमर कवंर व हेत कंवर के साथ हुआ। इनके पुत्र सरदार सिंह थे व एक पुत्री चंन्द्र कवंर जी जोधपुर में विराजमान हैं- वर्तमान ठाकुर रतन सिंह बाखासर जनहितार्थ तत्पर रहते हैं । इनका ननिहाल आला का पार छाछरो (पाकिस्तान) में था। जहां आने -जाने के कारण आप पाकिस्तान के सिंध प्रान्त से चिर-परिचित थे।

एक बार की बात है कि इनकी जागीरी के 52 गांव थे, उनमें से कुछ गाँवों के लोग इनके पास आए और अरदास की कि मीठी के मुसलमान उनकी 100 गायों को जबरदस्ती ले जा रहे है । लोगों के प्रतिरोध करने के उपरांत नही माने, इतने पर ठाकुर बलवंतसिंह ने आव-देखा न ताव अपने पंचकल्याणी घोड़े पर सवार होकर गायों को लेकर अपने दल-बल के साथ निकल पड़े। काफी दूरी तय करने के बाद कुख्यात नामी चोर घोड़ो के आगे गायों को तीव्र गति से दौड़ाने लगे। बहुत सारी गायें हांफकर गिरने लगी और धराशायी हो गई। इस पर ठाकुर बलवंतसिंह का गुस्सा सांतवे आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने चोर-डाकुओं पर दनादन गोलियां दागनी शुरू की। जिससे 8 चोर जमींदोज होकर मारे गये। गायों को हेरकर वापस लाया गया जिससे ठाकुर बलवंतसिंह की वीरता और उदारता के चर्चे चारों ओर फैल गये तथा उनकी लोकप्रियता चारों दिशाओं में फैलने लगी। वे बचपन से ही वीर-धीर-गंभीर व्यक्तित्व के धनी थे। वे हिन्द-पाक सीमावर्ती क्षेत्र में तत्कालीन भारत के एक महान् हिंद स्तंभ के रूप में साबित हो रहे थे।

1965 व 1971 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने देश धर्मी की भूमिका अदा की। जब 1971 का भारत-पाक युद्ध हो रहा था, तत्कालीन ब्रिगेडियर पूर्व महाराजा भवानीसिंह जयपुर के नेतृत्व में सेना भेजी गई पर वे इस क्षेत्र की परिस्थितियों से अपरिचित थे। ऐसे में उन्हें ठाकुर बलवंतसिंह की याद आई, वे भी सीमा पर दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तनाबुद करने की फिराक में थे। ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने उन्हें एक जोंगा जीप सुपुर्द की और एक टास्क दिया। ठाकुर बलवंतसिंह ने अपनी कुशलता, कुटनीति व दूरदर्शिता से जोंगा जीप का चैलेचंर खुलवा दिया और जीपों का काफिला भंयकर गर्जना के साथ दुश्मन की सरजमीं पर चल पड़ा। भारत-पाक सीमा से 40 कोस दूर पाकिस्तान के छाछरो चौकी को फतह कर झंडा गाड़ दिया। इस जीत का जश्न समूचे भारत में मनाया जाने लगा। ठाकुर बलवंतसिंह की लोकप्रियता समूचे भारत में फैल गई। उनकी वीरता, सैनिक कुशलता के किस्से समाचार-पत्रों, दूरदर्शन और रेडियों पर सुनने को मिले। इस 1971 युद्ध के बाद ठाकुर बलवंतसिंह का नाम विशेषकर सीमावर्ती इलाकों में, पूरे मारवाड़ गुजरात और पाकिस्तान में गर्व के साथ लिया जाने लगा।

भारत सरकार ने युद्ध का हीरो सम्मान से नवाजा

और वे मारवाड़ के रॉबिनहुड के किरदार में जनमानस के मस्तिष्क में उभर कर आए। वे जीवनपर्यंत सच्चे देशभक्त के रूप में हिन्द-पाक सीमा पर सजगता, दूरदर्शिता से राष्ट्र सेवा में अग्रण्य रहे। वे वास्तव में प्रजावत्सल, गौवत्सल और राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने शत्रु राष्ट्र के चोरों से धन-माल लूट कर अपने गांवो के लोगों को बांटकर सांमत होने की मान्यता को साबित किया। अनेक युद्ध लड़ने के कारण वे कई बार चोटिल भी हुए लेकिन उन्होंने अपने जख्मों की भी परवाह नहीं की । अन्तिम समय में जख्मों के कारण वे बीमार पड़ गए तो भारतीय सेना के चिकित्सकों ने उनका उपचार भी किया, पर 27 दिसम्बर 1992 के दिन उन्होंने अंतिम श्वास ली और सेना ने "गार्ड ऑफ ऑनर" हिन्द-पाक सीमा का सच्चा प्रहरी सम्मान दिया ।

देशहित में जूझता-लड़ता हमसे विदा हो गया है। आजाद भारत के गौरवमयी जाज्वल्यमान इतिहास में उनके अद्वितीय योगदान के सोरठे, गीत, कविता, छंदो में गाये हैं।उनके जीवन से सम्बधित पुस्तकें "बलवंत बावनी" व "बलवंत सुजस" प्रत्येक सीमावर्ती क्षेत्र के जनमानस में प्रेरणा देती रहेगी। ऐसे महान वीर योद्धा, राष्ट्रभक्त, कुशल सैनिक नेतृत्वकर्ता को हार्दिक शताधिक बार वन्दन, प्रणाम।।

जय हिन्द

प्रथम गाँव नादाबेट: गुजरात का वाघा

डॉ. नीरजा अरुण गुप्ता

कुलपति गुजरात विश्वविद्यालय

गुजरात का पश्चिमी भाग पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके कई जिलों के अंतिम गाँव इस सीमा क्षेत्र में आते हैं। मुख्य जिले हैं: बनासकांठा, कच्छ, रापर, भुज, लखपत तथा भचाऊ। इनमें से बनासकांठा में वाव तालुका के चंदनगढ़, छतरपुर, जालोवा, कुण्डलिया, मेघ्पुर्पदन, राधा नेसडा, रादोसन, रापर तालुका के बालासर, बेला, धब्दा, लोडरानी; भुज तालुका के भिरंदियारा, भीतारा मोटा, ध्रोबना, दिनारा, गोरेवाली, होड़का, खावड़ा, लुडीया, लूना, मिथाडी, उध्मो; लखपत तालुका में अतड़ो, छेर नानी, छेर मोटी, गुहार मोटी, जरा, कैयारी, कपुरासी, खाटियुं, लखपत, मूधान, नारायण सरोवर, पिपार, पुनराजपर, रोड़ासर लक्की, शिनापर, सियोत; तथा भचाऊ तालुका में बम्भानका, धोलावीरा, गढ़ाड़ा, गनेश्पार, जानन, कल्यान्पर, खरोड़ा एवं रतनपर प्रथम गाँव की श्रेणी में आते हैं।

नादाबेट कच्छ रण का अंतिम गाँव है जिसके बाद कच्छ का रेगिस्तान तथा समुद्र आरम्भ हो जाता है। यह पश्चिम भारत की वाघा सीमा की ही भांति है। कच्छ का रण अपनी सफेद नमकीन रेगिस्तानी रेत के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान माना जाता है।

कच्छ का रण

कच्छ का रण पश्चिमी गुजरात के कच्छ जिले में थार रेगिस्तान में एक नमक दलदली भूमि है। यह भारत में गुजरात और पाकिस्तान में सिंध प्रांत के बीच स्थित है। इसमें लगभग 30,000 वर्ग किमी भूमि शामिल है जिसमें कच्छ का महान रण, कच्छ का छोटा रण और बन्नी घास का मैदान शामिल हैं।

कच्छ का रण अपनी सफेद नमकीन रेगिस्तानी रेत के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान माना जाता है। 'रण' का हिंदी में अर्थ रेगिस्तान है जो बदले में संस्कृत शब्द 'इरिना' से लिया गया है जिसका अर्थ रेगिस्तान भी है। कच्छ के निवासियों को कच्छी कहा जाता है और इसी नाम से उनकी अपनी

भाषा भी है। कच्छ के रण में अधिकांश आबादी हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिखों की है।

खावड़ा गाँव के उत्तर में, कालो डूंगर (ब्लैक हिल) कच्छ का सबसे ऊंचा स्थान (462 मीटर) है, जहां से ग्रेट रण साल्ट फ़्लैट (या यदि आप मानसून के दौरान यात्रा कर रहे हैं तो अंतर्देशीय समुद्र) के उल्लेखनीय दृश्य दिखाई देते हैं। यह पहाड़ी भगवान दत्तात्रेय को समर्पित 400 साल पुराने मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। आप पहाड़ी के किनारे पर चलते हैं और विशाल धुंधले परिदृश्य को देखते हैं जो दिन चढ़ने के साथ-साथ रंग बदलता है और सूरज पहाड़ों के पीछे डूब जाता है।

किंवदंतियों का कहना है कि भगवान दत्तात्रेय यहां विश्राम करने के लिए रुके थे वहां उन्हें भूखे सियारों का एक समूह मिला। उन्होंने खाने के लिए अपना शरीर दिया और जैसे ही उन्होंने खाया, उनका शरीर लगातार अपने आप पुनर्जीवित हो गया। पिछली चार शताब्दियों से मंदिर के पुजारी देर शाम भोजन के लिए आने वाले सियारों के लिए पके हुए चावल तैयार करते हैं।

नादाबेट के निवासियों के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। एक समय यह एक शांत क्षेत्र था, अब यह सांस्कृतिक प्रदर्शनों, कार्यशालाओं और उत्सव कार्यक्रमों की गूँज से गूंजता है जो भारत के सांस्कृतिक सार को प्रदर्शित करता है।

कच्छ के रण का पारिस्थितिक महत्व

कच्छ क्षेत्र का रण राजहंस और जंगली गधे जैसे पारिस्थितिक रूप से समृद्ध वन्यजीवों का भी घर है, जिन्हें अक्सर रेगिस्तान के आसपास देखा जा सकता है। रण कुछ अभयारण्यों का भी हिस्सा है। जैसे कि भारतीय जंगली गधा अभयारण्य, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य आदि। यह वन्यजीव फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग सा है।

सफेद रेगिस्तान का विरोधाभासी परिदृश्य भारत में अद्वितीय है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए फिल्मांकन स्थान होने के अलावा कच्छ के सफेद रेगिस्तान की कड़ी जांच की जाती है। क्योंकि यह उत्तरी भारत-पाक सीमा पर स्थित है। सफ़ेद रेगिस्तान को वन्य जीवन, पुष्प और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कई अभयारण्यों के साथ उद्धृत किया जाता है।

सिंधु नदी के लिए एक बेसिन, कच्छ का सफेद रेगिस्तान नवंबर और फरवरी के बीच वाष्पित हो जाता है जिससे इसकी व्यापक नमक-पूरित भूमि को रास्ता मिल जाता है। इसी अवधि के दौरान प्रसिद्ध रण उत्सव कच्छ के इस सफेद रेगिस्तान पर आयोजित किया जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक है।

नादाबेट कच्छ के विशाल रण में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित एक द्वीप है। वानियासर एक ऐतिहासिक तालाब है जिसका आकाश जैसा झलकता फ़िरोज़ा पानी, भारत-पाक सीमा पर स्थित गाँव सुइगाम के शुष्क परिदृश्य में आसानी से किसी का भी ध्यान खींच लेता है। नादाबेट बॉर्डर, 1971 भारत-पाकिस्तान युद्ध का लुभावनी स्थल हैं। यह द्वीप 2016 से वाघा सीमा की तर्ज पर सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में आया। गुजरात सरकार की सीमा दर्शन परियोजना का भी यह एक प्रमुख स्थल है। यह गाँव पाकिस्तान से लगभग 50 किमी दूर है। कच्छ क्षेत्र के रण में स्थित, यह ऐसा आकर्षण है, जिसे 'गुजरात का वाघा' भी कहा जाता है। यह एक संकीर्ण कोलतार सड़क से जुड़ा हुआ है जो मिट्टी के मैदानों से गुजरती है। तथा उच्च ज्वार के दौरान यह मैदान जलमग्न हो जाते हैं।

गेट से लेकर 25 किमी अंदर स्थित भारत-पाक सीमा तक यह एक रोमांचकारी अनुभव कराता है। जहां प्रवेश करने वाला हर आगंतुक एक देशभक्त बन जाएगा। सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (10 अप्रैल) को अहमदाबाद से लगभग 188 किलोमीटर दूर गुजरात के नादाबेट में एक भारत-पाकिस्तान सीमा देखने के बिंदु का उद्घाटन किया।

1971 के युद्ध में भारत पाक सीमा बिंदु की भूमिका

जलोया और सुईगाम नादाबेट भारत-पाक सीमा से निकटतम गाँव हैं। 1965 के युद्ध के परिणामस्वरूप, जब सीमा सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल बनाया गया, तब भारत-पाक सीमा बीएसएफ की निगरानी में थी। 1971 के युद्ध ने एक राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के जन्म और पाकिस्तान के शासन से उसकी मुक्ति को चिह्नित किया। 16 दिसंबर, 1971 को ढाका के पतन और पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इस दिन को भारत में 'विजय दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह नादाबेट बीओपी 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध (मार्च 1971 से) तीसरे भारत-पाकिस्तान युद्ध (दिसंबर 1971 से) में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। प्रारंभ में सीमा की रक्षा के लिए बीएसएफ की अग्रिम पंक्ति की रक्षा नादाबेट बीओपी पर कार्रवाई में थी।बीएसएफ द्वारा पश्चिम से आक्रमण करने की कोशिश कर रहे दुश्मन को रोकने के लिए नादाबेट का इस्तेमाल किया गया और उन्हें दुश्मन के 15 बिंदुओं पर कब्जा करने में मदद मिली। मानचित्र युद्ध के दौरान दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा करने वाली बीएसएफ बटालियनों की गतिविधियों को दर्शाते हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तान की 1,038 वर्ग किमी जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसे बाद में शिमला समझौते में वापस कर दिया गया।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद अमित्र पड़ोसियों से हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए की गई थी। तब तक हितों की रक्षा करना स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी थी। युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के समय स्थानीय पुलिस

(काली डूंगर भगवान दत्तात्रेय मंदिर, नादाबेट)

की कमजोरियों को उजागर कर दिया और गुजरात की नादाबेट सीमा सहित हजारों किलोमीटर लंबी भारत-पाकिस्तान सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र सशस्त्र पुलिस बल की आवश्यकता महसूस की गई।यह अच्छा था कि बीएसएफ का जन्म हुआ। क्योंकि उन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो बांग्लादेश को जन्म देने में सहायक थी। जिसे उस समय तक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था।

नादाबेट क्षेत्र में, बीएसएफ ने न केवल दुश्मन के सभी अपराधों को रोका, बल्कि पाकिस्तान की 1000 वर्ग किमी से अधिक भूमि पर कब्जा करने में भी कामयाब रही और इसे शिमला समझौते तक अपने पास रखा, जिसके बाद कब्जा किए गए क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। बीएसएफ के साहस और वीरता की कहानियों को फिर से याद करने और सुनने के लिए, गुजरात सरकार और बीएसएफ ने बीएसएफ और उनके जवानों के जीवन और विरासत की स्मृति में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया।

1971 में नादाबेट सीमा युद्ध की कहानी

मार्च 1971 में जब पूर्वी बंगाल (बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान) ने स्वतंत्रता की घोषणा की तो यह स्पष्ट था कि पाकिस्तान न केवल बांग्लादेश पर बल्कि भारत पर भी आक्रमण करेगा। क्योंकि भारत बांग्लादेश के मुद्दे का समर्थन कर रहा था। अक्टूबर तक खुफिया रिपोर्टों के आधार पर भारत युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था और सेना को बीएसएफ के साथ काम पर लाया गया था। जिसमें गुजरात के भुज-कच्छ सीमा क्षेत्र भी शामिल थे। नवंबर 1971 के अंत तक एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध अपरिहार्य था। लेकिन फिर भी भारत ने पहले गोलाबारी न करने का निर्णय लिया। जैसा कि 3 दिसंबर 1971 को हुआ था, पाकिस्तान एयरफोर्स (पीएएफ) ने सीमित सफलता के साथ 12 अग्रिम हवाई अड्डों और राडार को नष्ट करने के उद्देश्य से भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी। यह भारत को अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक ट्रिगर मात्र था। जब भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही थी, तब पालनपुर गुजरात में बीएसएफ की 3 बटालियनें भुज-कच्छ सीमा की ओर बढ़ीं। इसे अब नादाबेट भारत-पाक सीमा कहा जाता है।

दूसरी बटालियन धीरे-धीरे लेकिन लगातार कच्छ के रण (नमक रेगिस्तान) में आगे बढ़ी और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के नगरपारका, धनगाँव, विरावाह जैसे प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। कुल मिलाकर, बीएसएफ पालनपुर बेस ने पाकिस्तान के 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।

सीमा दर्शन

बीएसएफ और गुजरात पर्यटन ने हमें वीरता और असाधारण साहस की कहानी जीने के लिए एक पूर्ण अनुभवात्मक गंतव्य बनाया है, जिसे गार्जियंस एट द एज कहा जाता है। यहां बंदूकें, मिसाइल और टैंक सहित 8 युद्ध प्रदर्शनियां हैं। बच्चों सहित हर किसी को इन उपकरणों की खोज में अत्यधिक आनंद आता है। टी55 टैंक वाले हार्ड स्टॉप पर अवश्य रुकना चाहिए। क्योंकि वहां एक लंबा अवलोकन टावर है जहां से कोई भी नादाबेट के रण का 360 डिग्री का अप्रतिबंधित दृश्य देख सकता है।

शून्य बिंदु: नादाबेट सीमा नादेश्वरी माता मंदिर, सुई गाँव के पास एक अन्य आगंतुक अनुभव परिसर से लगभग 25 किमी दूर है, जिसे अब टी-जंक्शन कहा जाता है। कांटेदार तार की बाड़ की परतों और साथ में एक सड़क के कारण ज़ीरो पॉइंट सीमा के सबसे करीब है, जो भुज से लेकर कश्मीर तक भारत-पाक सीमा के साथ-साथ चलती है।

इसकी भी एक पुरातन कहानी है और वह यह है कि इस मंदिर का निर्माण बीएसएफ द्वारा किया गया था और सैनिक अक्सर स्थानीय रबारी पशुपालकों की

मदद लेकर कठिन और जोखिम भरे रेगिस्तान में यात्रा करने से पहले यहां पूजा करते हैं। सड़क बिल्कुल नई है और रेगिस्तान पर बनी सिंगल लेन सड़क अपने आप में एक आश्चर्य है। इस सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए बीएसएफ की अनुमति लेनी पड़ती है। एक बार जब गंतव्य का आधिकारिक उद्घाटन हो जाएगा, तो केवल आधिकारिक वातानुकूलित बसों को ही आगंतुकों के लिए जाने की अनुमति दी जाएगी।

यह सीमा दर्शन नागरिकों को पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा देखने की सुविधा प्रदान करता है। गुजरात के बनासकांठा जिले में इन चौकियों की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा की जाती है। यह राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर की एक संयुक्त पहल है। फोकस इन क्षेत्रों में सीमा पर्यटन विकसित करने पर है जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं और जहां अतिरिक्त आबादी है।

इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और सीमा पार के गाँवों से भारत की ओर प्रवास को कम करना है। पाकिस्तान नादाबेट में सीमा स्तंभ 960 से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक एमएल गराफ ने बताया कि बीएसएफ अमृतसर में अटारी-वाघा सीमा पर होने वाली परेड की तरह परेड आयोजित करेगी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई परेड नहीं होगी। परेड शाम को सीमा से 30 किलोमीटर दूर एक खुले सभागार में आयोजित की जाएगी, जिसमें 5,000 लोग बैठ सकते हैं।

नादाबेट सीमा पर पहुँचना

सुइगाम से बीएसएफ द्वारा संरक्षित सड़क के माध्यम से ही नादाबेट पहुंचा जा सकता है। 125 करोड़ रुपये की सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किए गए अधिकांश आकर्षण टी-जंक्शन पर हैं। लेकिन आगंतुक टी-जंक्शन के उत्तर में लगभग 25 किमी आगे सीमा देखने के लिए विशेष अनुमति ले सकते हैं। ज़ीरो पॉइंट पर एक ऊंचा वॉचटावर बनाया गया है जो आगंतुकों को पाकिस्तानी क्षेत्र का दृश्य देता है। जो पर्यटक निजी वाहन नहीं ले सकते, उनके लिए बस सुविधा उपलब्ध कराई गई है।।

यह स्थान आगे चलकर राइफल शूटिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, जिपलाइन और अन्य गतिविधियों जैसे रोमांच की पेशकश करेगा। इसमें एक देखने वाली गैलरी और एक संग्रहालय होगा जिसमें एमआईजी -27, विमान और अन्य युद्ध हथियारों जैसे प्रदर्शन होंगे।

ज़ीरो पॉइंट के रास्ते में कठिन बिंदु

चूंकि सड़क का 25 किमी का हिस्सा एक लेन है, इसलिए हर कुछ सौ मीटर पर ऐसे स्थान होते हैं जहां सड़क थोड़ी चौड़ी होती है। ताकि वाहनों, यहां तक कि बसों को भी एक-दूसरे को पार करना संभव हो सके।

विविधता को अपनाना: नादाबेट का सांस्कृतिक ताना बाना

नादाबेट भारत-पाक सीमा, गुजरात का एक उभरता हुआ पर्यटन स्थल, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत चित्रपट है। भारत की बहुमुखी संस्कृति से प्रेरित कार्यक्रम और उत्सव पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं। ये आयोजन न केवल आगंतुकों के लिए एक शानदार दृश्य प्रदान करते हैं, बल्कि निवासियों की शिक्षा और जागरूकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिससे नादाबेट भारत-पाक सीमा गुजरात में घूमने के लिए अद्वितीय स्थानों में से एक बन जाती है।

नादाबेट के निवासियों के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। एक समय यह एक शांत क्षेत्र था। अब यह सांस्कृतिक प्रदर्शनों, कार्यशालाओं और उत्सव कार्यक्रमों की गूँज से गूंजता है जो भारत के सांस्कृतिक सार को प्रदर्शित करते हैं। मनोरंजन से अधिक, ये आयोजन स्थानीय समुदायों के उत्थान के लिए मंच

के रूप में भी काम करते हैं। वे निवासियों को समुदाय और गौरव की मजबूत भावना को बढ़ावा देते हुए इन समारोहों में शामिल होने, सीखने और यहां तक कि योगदान करने का अवसर प्रदान करते हैं।

आगंतुकों के लिए नादाबेट ऐतिहासिक तल्लीनता और सांस्कृतिक अन्वेषण का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। जबकि यह बहादुरी की कहानियों से गूंजता है। यह भारत की विविधता में एकता को भी प्रदर्शित करता है। प्रत्येक आगंतुक के लिए एक समृद्ध और अविस्मरणीय यात्रा की पेशकश करता है, जिससे गुजरात में पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होती है।

स्थानीय समुदायों पर गहरा प्रभाव डालने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों को आकार देने वाले व्यापक सरकारी दृष्टिकोण को पहचानना महत्वपूर्ण है।

- **सरकार का दृष्टिकोण: नागरिकों और राष्ट्र के रक्षकों को जोड़ना**

नादाबेट भारत-पाक सीमा जैसे रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्र हमेशा कई सरकारी पहलों के केंद्र में रहे हैं। सीमा नीतियों और विकास प्रयासों से परे, एक गहन भावना है: राष्ट्रीय एकता और गौरव का पोषण।

इन क्षेत्रों में परियोजनाओं का लक्ष्य भारत के हृदय को उसकी परिधियों से जोड़ना है। इस तरह की पहल के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नागरिकों को बीएसएफ जवानों के जीवन के बारे में करीब से जानकारी प्रदान करना है। उनकी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, अथक कर्तव्यों और अटूट देशभक्ति का प्रदर्शन करके सरकार उनके बलिदानों के लिए गहरी प्रशंसा और सम्मान पैदा करने का प्रयास करती है। गुजरात के इस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर ये प्रयास राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाते हैं और राष्ट्र और उसके रक्षकों के प्रति जिम्मेदारी की साझा भावना को बढ़ावा देते हैं।

सरकार के दृष्टिकोण के साथ, नादाबेट भारत की दृढ़ भावना के प्रतीक के रूप में चमकता है। आकाश को गौरवान्वित कर रहे तिरंगे और राष्ट्रगान की भावपूर्ण प्रस्तुति से पूरा क्षेत्र गूंज उठता है, जिससे माहौल देशभक्ति से ओत-प्रोत हो जाता है। नादाबेट में ये दो महत्वपूर्ण तिथियां जीवंत अवसरों में बदल जाती हैं, जो सभी कोनों से आगंतुकों को एक विशिष्ट देशभक्ति अनुभव का हिस्सा बनने के लिए आकर्षित करती हैं। वे न केवल एक कैलेंडर पर चिन्हित अवसर के रूप में काम करते हैं, बल्कि भारत की अथक भावना, पिछली चुनौतियों, विजयी क्षणों और आगे के उज्ज्वल पथ के जीवंत स्मरणोत्सव के रूप में भी काम करते हैं। नादाबेट में इन समारोहों को देखकर कोई भी वास्तव में भारत के समृद्ध इतिहास और इसके भविष्य के प्रति इसके अटूट समर्पण का सार समझ सकता है।

गुजरात के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नादाबेट के आकर्षण, मार्मिक रिट्रीट समारोह से लेकर 'नाम नमक निशान' की विचारोत्तेजक कलाकृतियों तक इतिहास और संस्कृति की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रस्तुत करते हैं। अपने ऐतिहासिक महत्व से परे, नादाबेट एड्रेनालाईन-पंपिंग साहसिक गतिविधियों का वादा करता है, जो आगंतुकों को इस अद्वितीय सीमा में श्रद्धा और रोमांच दोनों का अनुभव सुनिश्चित करता है।

संक्षेप में, नादाबेट जैसे सीमावर्ती क्षेत्र सिर्फ प्रवेश द्वार या सीमाओं से कहीं अधिक हैं; वे एक राष्ट्र के दिल की धड़कन हैं, जो उसके इतिहास, उसकी विविधता और उसकी अदम्य भावना को समेटे हुए हैं। नादाबेट, अपने असंख्य अनुभवों के साथ, हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किए गए बलिदानों और उनके भीतर पनपने वाली जीवंत संस्कृति की मार्मिक याद दिलाता है, जो इसे गुजरात में घूमने के स्थानों में एक आवश्यक गंतव्य बनाता है।

कमान्डेंट (रि.)
आर. सी. शर्मा

बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स
से अवकाश प्राप्त

सीमा प्रबंधन के मुख्य घटकः भारत के प्रथम गाँव

दो देशों को भौतिक रूप से विभाजित करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, सीमा क्षेत्र, सीमा जनसंख्या और ये तीनों भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनाते हैं। ये सीमा प्रबंधन ग्रिड का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। शब्दकोश में सीमा प्रबंधन ग्रिड का अर्थ है राष्ट्रीय सीमाओं का सुरक्षा शासन ताकि देश की राजसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित हो सके। गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन का उद्देश्य "देश के हित के खिलाफ, रुचियों के खिलाफ खड़ी शक्तियों से देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और ऐसे तंत्रों को स्थापित करना जो ऐसे तत्वों को रोक सकते हैं, जो वैध व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाने की क्षमता रखते हैं। यह सीमा प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक हैं।" इसमें सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए रणनीति पर जोर दिया गया है। सीमा क्षेत्रों में बुनियादी संरचना बनाने के लिए और उसके बारे में शुरू की गई पहलों का विवरण दिया गया है, उसके बाड़, सीमा आउट पोस्ट/कंपनी संचालन आधार और विभिन्न सीमाओं के साथ सड़कों का निर्माण।

भारत के पास 17 राज्यों में फैले 15,106.70 किमी की भूमि सीमाएं हैं। हमें समझने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों को मुख्यरूप से सीमा रेखा के सामने होने वाले राज्यों में शामिल किया जा सकता है। देश को यह भी समझने की आवश्यकता है कि सीमा संरक्षण बाड़, बाढ़, प्रकाश, सीमा सड़क जैसे सीमाओं में संरचनाओं का विकास या बाहरी संघर्ष में आर्थिक सुधार का मतलब नहीं है। सीमाओं के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार, जैसे कि स्कूल, अस्पताल, साफ

पीने का पानी, परिवहन, अविराम बिजली आपूर्ति और सड़कों का नेटवर्क, कनेक्टिविटी पहल और सीमा जनसंख्या को अनुमति देने के लिए एक प्रायोजक वातावरण सीमा प्रबंधन का विस्तारशील दृष्टिकोण होता है। यह केवल सीमा सुरक्षा से सीमित नहीं है और सीमा सुरक्षा में भूमिका निभाने वाले और सीमा क्षेत्रों के विकास में भूमिका निभाने वाले शासन के विभिन्न तत्वों को समावेश करता है। यह विभिन्न हितधारकों को शामिल करता है जिनके सहयोग के बिना सीमा संरक्षण

सीमा
प्रबंधन का विस्तारशील दृष्टिकोण होता है, यह केवल सीमा सुरक्षा से सीमित नहीं है, और सीमा सुरक्षा में भूमिका निभाने वाले और सीमा क्षेत्रों के विकास में भूमिका निभाने वाले शासन के विभिन्न तत्वों को समावेश करता है।

बल सक्षम नहीं होंगे अथवा सीमा सुरक्षा और सीमा रक्षा को सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि एकीकृत हितधारकों के बिना सीमा प्रबंधन केवल विलक्षण नामकरण है। यह केवल सीमा संरक्षण का एक विस्तार है जिसके पास केवल एक संपत्ति है यानी सीमा संरक्षण बल, जो निश्चित रूप से एकमात्र हितधारक के रूप में सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। हालांकि, एकमात्र दृष्टिकोण सीमा संरक्षण बलों के लिए पहले से ही कठिन, अशांत और भारी काम को और अधिक कठिन बना देगा।

सवाल उठता है कि सीमा सुरक्षा को अभेद्य और पूर्ण निर्भय कैसे बनाया जाए? क्या सीमा रक्षा संरचना का विकास करके और सीमा संरक्षण की आधुनिकीकरण करके ही यह संभव है? उत्तर हाँ और नहीं दोनों है। सीमा रक्षा संरचना और सीमा संरक्षण बलों की आधुनिकीकरण मजबूत सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; हालांकि, यह प्रभावशीलता को बिना हितधारकों के सक्रिय सहयोग के साथ प्राप्त किये जाने पर वास्तविक रूप से आवश्यक अवस्था तक पहुँच नहीं पाता। जो मुख्यत: सीमा प्रबंधन के प्रमुख घटक के रूप में शामिल किये जाने चाहिए।

मुख्य हितधारक कौन होते हैं सीमा प्रबंधन में? हितधारक सीमा संरक्षा बल, सीमा जनसंख्या और स्थानीय प्रशासन होते हैं। ये तीनों एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है और सक्रिय सीमा सुरक्षा के लिए उनमें सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक आवश्यक पूर्वावलोकन है। किसी विशेष सीमा पर तैनात सीमा संरक्षा बल की राष्ट्रीय हित में सभी इन हितधारकों के साथ समन्वय करना सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है।

सीमा जनसंख्या सीमा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि सीमा सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को सरकार और क्रियान्वयन संगठन, यानी सीमा संरक्षा बल द्वारा मान्यता दिया जाना चाहिए। सीमा जनसंख्या सीमाओं पर केवल स्थायी तत्व है। यह अपनी ओर के न केवल गहरा ज्ञान रखती है बल्कि उपसागरी ओर भी अच्छी तरह से परिपूर्ण है और सीमांकन रेखा और सीमा क्षेत्र के साथ अच्छे से जानकार है। इतना ही नहीं, यह कहना गलत नहीं होगा सीमा के लोग जब पूछे जाते हैं तो सीमा संरक्षा में विभिन्न पहलुओं में सीमा व्यक्ति को मार्गदर्शन करते हैं। सीमा संरक्षा बल और जिला प्रशासन नियमित अवधि के बाद बदलते हैं और स्थायी नहीं कहे जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ स्थायी हितधारक और प्रमुख संपत्ति, जिनकी भागीदारी के बिना सीमा प्रबंधन अधूरा होता है, वह सीमा जनसंख्या है। इसलिए, सीमा जनसंख्या को सीमा प्रबंधन के मुख्य स्तंभों में से एक के रूप में

मान्यता देना बहुत महत्वपूर्ण है।

सत्य है कि सीमा जनसंख्या और सीमा संरक्षा बलों के बीच संबंध हमेशा सम-विषम रहे हैं। यह सभी सीमाओं के लिए सच है। सम-विषम संबंध का कारण यह है कि सीमा जनसंख्या सीमा संरक्षा बलों को अपनी आम कृषि गतिविधियों में बाधा के रूप में देखती है। जैसे की बुआई और कटाई, खासकर बाड़ लगे सीमाओं पर। जबकि सीमा संरक्षा बल को सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और कुछ निर्देशों का पालन करना होता है, जो नि:शुल्क आवागमन को बाधित करते हैं। इस सम-विषम संबंध को सुधारने की जिम्मेदारी सीमा संरक्षा बल पर है, क्योंकि यह सम-विषम संबंध का मुख्य स्रोत माना जाता है। किसानों को बुआई, सिंचाई और अपने फसलों की कटाई के लिए बाड़ों के आगे जाना पड़ता है। दोनों गर्मियों और सर्दियों के समय द्वारों को खोलने और बंद करने के लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) होते हैं। द्वारों के अंदर और बाहर आने वाले पुरुषों, महिलाओं और उपकरणों की जांच के लिए प्रोटोकॉल और प्रक्रिया होती है। किसान भंडारण और जाँच में शारीरिक संरेखण में विरोध नहीं करते हैं, बल्कि अभ्यास में सहयोग करते हैं। बुआई और कटाई के मौसम में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सामान्यत: सीमा संरक्षा बल द्वारों का संचालन करने के लिए मानवशक्ति की कमी होती है और सीमा पर किसानों, श्रमिकों और ट्रैक्टर ट्रॉलीयों की भागदौड़ को संभालने में सीमित मानवशक्ति अक्षम होती है, जिससे द्वारों पर देरी होती है। यह किसानों में असहनीयता का कारण बनता है, जो उनके फील्ड में काम करने का सीमित समय द्वार पर बर्बाद हो जाता है। यह एक स्थायी समस्या है। कभी-कभी यह समस्याएँ झगड़ों और स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बनती हैं, जो सीमा व्यक्तियों को अत्यधिक तनाव में डालता है।

एक और कारण सम-विषम संबंध का यह है कि सभी को एक ही ब्रश से चित्रित करना। सत्य है कि सीमाओं पर तस्करी का खतरा होता है और स्थानीय लोग इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं। लेकिन सभी को एक ही ब्रश से चित्रित करना अनुचित है। इससे स्वाभिमानी नागरिकों में अलगाव की भावना पैदा होती है। सीमा संरक्षा बलों को इस पहलू पर अपने जनों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। क्योंकि यह दोनों हितधारकों के बीच संबंधों को खराब बनाता है। समय पर द्वार ना खोलने के कारण या किसी अन्य आंतरिक मानव संख्या की कमी के कारण भी कभी-कभी तनाव उत्पन्न होता है, जो समयबद्धता के प्रति शक्ति से लगातार पालन करके बचा जा सकता है। स्थानीय लोगों के साथ जमीनी स्तर पर व्यवहारिक विपरीतताओं की भी कभी-कभी अनपेक्षित तनाव पैदा होता है, जो त्यागने के लिए आवश्यक है और पुरुषों को सही व्यवहार के मुद्दे पर संवेदनशील किया जाना चाहिए जो कठोर हुए बिना हो सकता है।

विशेष रूप से कंपनी कमांडरों के स्तर पर सीमा जनसंख्या के साथ संयमित अन्तरक्रिया के लिए निर्धारित SOPs और प्रक्रियाएँ हैं, जो सही और सुसंगत रूप से कार्यान्वित की जानी चाहिए। स्थानीय लोगों की शिकायतों को संवेदनशीलता से विचार किया जाना चाहिए। जैसे कि सैनिकों के व्यवहार, द्वारों का खुलना और बंद होना और अतिरिक्त द्वारों को कार्यात्मक बनाने के संदर्भ में। स्थानीय लोगों के साथ एकत्रित होकर और उनसे बातचीत करने की आवश्यकता है ताकि वे सीमा सुरक्षाकर्मी की कठिनाइयों को समझें और निश्चित रूप से सामग्री अंतरक्रिया समस्याओं को हल करने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक हो। एक और पहलू, जिस पर कंपनी कमांडरों को ध्यान देना चाहिए यह है कि स्थानीय सीमा प्रबंधन संबंधित मुद्दों को हल करने में विलम्ब न करें जो सीमा जनसंख्या को प्रभावित करते हैं स्थानीय लोगों को न उनके आगे के दरवाजे पर इंतजार करने के लिए कहें और फिर उन्हें इंतजार कराने और उन्हें उनके अगले दिन आने का आदेश देने के माध्यम से परेशान और अपमानित

करें। यह बटालियन कमांडरों और उच्च अधिकारियों के स्तर पर भी लागू होता है। कई बार होता है कि सीमाओं के किसान बटालियन और उच्च मुख्यालयों में अपार समय तक द्वारों पर इंतजार कराए जाते हैं और फिर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। उनकी समस्याओं को समझना और उनसे बातचीत करने की बजाय उन्हें टालने की आवश्यकता है। यह संयुक्त अविश्वास को उत्पन्न करता है, जो सीमा सुरक्षा के हित में खिलाफ जाता है।

सीमा जनसंख्या को सीमा प्रबंधन में शामिल कैसे किया जाए? सरकार और सीमा संरक्षा बलों को पहले यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि सीमा प्रबंधन ग्रिड में सीमा जनसंख्या का समावेश महत्वपूर्ण है ताकि सीमा सुरक्षा में प्रभावी हो सके। इसे स्थिर सीमाओं के लिए सीमा प्रबंधन चक्र में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखा जाना चाहिए। सीमा संरक्षा बलों को सीमा जनसंख्या और सीमा संरक्षा बल के बीच द्वंद्वात्मक संबंध के कारणों का गहन विश्लेषण करना चाहिए और उन्हें हल करने की आवश्यकता है। फेंस लगी सीमाओं के मामले में, द्वार प्रबंधन ड्रिल और प्रक्रियाओं की पुनः समीक्षा की जरूरत है और खासकर अधिकांश बुआई और कटाई के मौसम में द्वारों पर मानवशक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। यह ख़राब संबंधों को समाप्त करेगा और सीमा संरक्षा को मजबूत करेगा और सीमा संरक्षा में गैप को कम करके सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा।

एक प्रभावी द्वार प्रबंधन प्रोटोकॉल संभवतः वहाँ भी फेंसिंग की समस्या को हल कर सकता है। जैसे कि भारत-म्यांमार सीमा पर, जहां स्थानीय लोग और कुछ सरकारें अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कारण फेंसिंग के खिलाफ हैं। यदि इसे ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाए तो द्वारों के माध्यम से चलन को विनियमित करके मुफ्त आव्रजन व्यवस्था (FMR) को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे स्थानीय चिंताओं का समाधान किया जा सकता है। यह क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने में योगदान करेगा।

सीमा संरक्षा बलों को स्थानीय सरकार और स्थानीय प्रशासन को प्रभावित करके सीमा क्षेत्रों के तेजी से विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भी आवश्यकता है, ताकि सीमा जनसंख्या के आर्थिक लाभ को सुधारकर उन्हें तस्करी और अन्य राष्ट्रीय दुराचारी गतिविधियों से दूर रखा जा सके।

सीमा जनसंख्या को सीमा प्रबंधन ग्रिड का महत्वपूर्ण घटक मानना और सरकार और सीमा संरक्षा बल दोनों द्वारा उसका सम्मान किया जाना चाहिए। कोष की रिपोर्टों में स्थानीय अधिकारियों का योगदान शामिल किया जाना चाहिए। जो वर्तमान में सीमा सुरक्षा को ही देखने के लिए प्रतिबिंबित होते हैं। सीमा संरक्षा के लिए प्रभावी रणनीति के लिए सभी हितधारकों को समाहित करने वाले सीमा संरक्षा डॉक्ट्रिन का विकास भी आवश्यक है। आइए उम्मीद करें कि सीमा जनसंख्या को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में महत्वपूर्ण घटक के रूप में माना जाएगा और उसे सीमा प्रबंधन ग्रिड में शामिल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। जिससे सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी।

इंटीग्रेशन सुनिश्चित करने के लिए कौन से सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, इसे विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है और इंटीग्रेशन संभव है।

पी.के.साबू

भूविज्ञान में स्नातकोत्तर और पर्यावरण अध्ययन में डॉक्टरेट

वर्कला: भारतीय तट का एक धरोहर

एक मिथक के अनुसार, नारद मुनि ने अपना पेड़ की छाल का वस्त्र (वल्कल) आकाश से फेंका था। यह भारत के दक्षिणी भाग में एक तटीय क्षेत्र में गिर गया। जिस स्थान पर नारद जी के वल्कल ने पृथ्वी को स्पर्श किया उसका नाम 'वर्कला' पड़ा। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है। 20 अगस्त 2023 को भारत के माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द वर्कला पहुंचे। इसका संबंध नारद के पौराणिक नारायण से नहीं, बल्कि आधुनिक समय के नारायण से था। उन्होंने केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान की उपस्थिति में नारायण गुरुकुल के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। अब, 2024 के 'पद्म श्री' पुरस्कार विजेताओं की क्रम संख्या 98 के रूप में सूचीबद्ध नाम, स्वामी मुनि नारायण प्रसाद भी वर्कला से हैं। वे नारायण गुरुकुल के वर्तमान प्रमुख और गुरु भी हैं।

ब्रह्मा से ब्रह्म तक

नारद मुनि की कहानी और वर्कला से इसका संबंध भारत के आध्यात्मिक/पौराणिक क्षेत्र से संबंधित है। ब्रह्मा इस प्राचीन परंपरा के केंद्रीय व्यक्तियों में से एक हैं। सदियों की अवधि में, केंद्रीय अवधारणाओं में से एक के रूप में ब्राह्मण या 'पूर्ण' के साथ एक और परंपरा विकसित हुई। यह भारत की ज्ञान परंपरा है और, कहा जा सकता है कि इस परंपरा ने वेदांत में परिपक्वता प्राप्त की है। सदियों से शंकर, रामानुज, माधव और अन्य प्रतिभाशाली संत-विद्वानों ने वेदांत की अलग-अलग तरीकों से व्याख्या की है। दार्शनिक-कवि गुरु नारायण वेदांत प्रसिद्ध प्रतिपादकों के इस वर्ग से संबंधित हैं। गुरु नारायण के अनुसार, वेदांत,

"भारत के ज्ञान के पेड़ पर सबसे अच्छे फल" जैसा है। प्राचीन ज्ञान के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्कथन के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वेदांत का सबसे उल्लेखनीय अनुप्रयोग है। इस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया कि वेदांत एक जीवित दर्शन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फ्रांसीसी दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रोमां रोलां ने उन्हें "कर्म का ज्ञानी" कहा था।

नारायण गुरुकुल

गुरु नारायण के पास मठवासी और सामान्य दोनों तरह के समर्पित शिष्यों की एक श्रृंखला थी, जो उनके उद्देश्य के लिए जीते थे। 'गुरु पर्वत' से विभिन्न धाराओं की उत्पत्ति हुई है और प्रत्येक शिष्य प्रमुख रूप से किसी एक धारा में स्थित हो सकता है। ये धाराएँ भक्ति, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक हैं। प्रत्येक धारा का अपना प्रतिनिधि शिष्य होता है, पी.नटराजन दार्शनिक धारा के हैं। नारायण गुरु ने इस शिष्य को अपने दर्शन के सूक्ष्म पहलुओं पर पाठ पढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने उसे उच्च अध्ययन के लिए पश्चिम भी भेजा। नटराजन को डी.लिट् की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1932 में पेरिस विश्वविद्यालय (सोरबोन) से डिग्री प्राप्त की और डॉ. नटराजन बन गये। बाद में उन्होंने लंदन से एमआरएसटी (रॉयल सोसाइटी ऑफ टीचेज के सदस्य) की उपाधि प्राप्त की। नारायण गुरुकुल की स्थापना 8 जून 1923 को गुरु नारायण के इस शिष्य ने की थी। यह भारतीय (हिंदू) परंपरा के अनुसार एक गुरु-शिष्य फाउंडेशन है और कानून में इसका दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1), 25 और 26 से प्राप्त होता है। यह एक गैर-लाभकारी, धर्मार्थ और सार्वजनिक फाउंडेशन है जो नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, लिंग या पंथ आदि के भेदभाव के बिना उन सभी के लिए खुला है जो सजीव शब्दों में पूर्ण ज्ञान (ब्रह्म-विद्या) की खोज करते हैं जिसके गुरु नारायण (1854 -1928) एक आदर्श और अनुकरणीय व्यक्तित्व है। इसके शताब्दी वर्ष का उद्घाटन 2023 में किया गया था और उपर्युक्त पद्म श्री पुरस्कार विजेता इस फाउंडेशन के वर्तमान प्रमुख हैं।

> प्रथम गाँव का विकास और यह निर्धारित करने के लिए कि इन ग्रामों से कोई भी पलायन न हो, तो इसके लिए सभी स्तर पर लगन, प्रतिबद्धता और परिश्रम की जरूरत है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है, और इसलिए एक अहम विषय है।

वर्कला में ब्रह्मविद्यामंदिर

नारायण गुरुकुलम द्वारा परिकल्पित ब्रह्म विद्या अद्वैत वेदांत का एक आधुनिक संस्करण है जहां इस प्राचीन ज्ञान को चेतना के विज्ञान, विज्ञान के विज्ञान, निरपेक्ष या इकाई अनुभूति के विज्ञान के रूप में देखा जाता है। दुनिया भर में इस ज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक संस्थागत साधन के रूप में, निरपेक्ष विज्ञान संस्थान (ब्रह्मविद्यामंदिर) भी हैं। नटराज गुरु, उनके उत्तराधिकारी नित्य चैतन्य यति और वर्तमान प्रमुख एवं मुख्य लेखक हैं।

अद्वैत एकात्मक समझ के रूप में

गुरु नारायण द्वारा वेदांत में जोड़े गए मूल्य का उल्लेख खंड 1 में किया गया है। इस तरह के मूल्यवर्धन ने उनके शिष्य के लिए आधुनिक समय में वेदांत को सभी विज्ञानों के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना संभव बना दिया। यह विज्ञानों का विज्ञान है, क्योंकि उसी चेतना से सभी विज्ञानों की उत्पत्ति होती है और वेदांत को चेतना के अध्ययन के रूप में देखा जा सकता है। वेदांत, विशेषकर अद्वैत को इस परिप्रेक्ष्य से देखने और इसे सार्वभौमिक दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए अंग्रेजी में उचित शब्दावली की आवश्यकता है। आमतौर

पर अद्वैत का अनुवाद अद्वैतवाद के रूप में किया जाता है। लेकिन, नटराज गुरु के अनुसार, अद्वैत मात्र एकता से अधिक का अर्थ है और इसलिए सामान्य अनुवाद अद्वैत की भारतीय अवधारणा के समकक्ष अभिव्यक्ति नहीं हैं। इसलिए उन्होंने इसमें निहित अद्वितीय गुण को व्यक्त करने के लिए 'यूनिटिव अंडरस्टैंडिंग' शब्द गढ़ा। यूनिटिव अंडरस्टैंडिंग के विचार की कल्पना केवल शैक्षणिक अनुशासन के रूप में नहीं की गई है और न ही इसका दायरा बौद्धिक अभ्यास के क्षेत्र तक सीमित है। इसके अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है और यह जीवन के सभी विषयों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का एक तरीका है - जिसे भारत में पारंपरिक रूप से अद्वैत के रूप में माना जाता है। लेकिन यह व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, यह दिखाता है कि कैसे सामाजिक मुद्दों को मानव और प्रकृति, प्राचीन और आधुनिक और पूर्व और पश्चिम को एकीकृत करके समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से हल किया जा सकता है। नटराज गुरु ने इस एकीकरण को संभव बनाने के आधार के रूप में एक 'संरचनावाद' विकसित किया। कोई भी इस संरचनावाद में चतुष्पाद (मांडुक्य उपनिषद के श्लोक दो में संदर्भित) की प्राचीन भारतीय धारणा, चार गुना योजना और आधुनिक 'कार्टेशियन सहसंबंध' के संलयन को समझ सकता है।

वर्कला से एझिमाला तक

पारंपरिक ज्ञान के पुनर्मूल्यांकन और उसमें नए आयाम जोड़ने में नारायण गुरुकुल का योगदान केवल सैद्धांतिक विस्तार तक सीमित नहीं है। दुनिया में शांति लाने के लिए अद्वैत, एकात्मक समझ की क्षमता दिखाने के लिए नटराज गुरु द्वारा सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। ये 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में थे। इस श्रृंखला को 'यूनाइटिव अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से विश्व शांति' नाम दिया गया था और यह केरल के कन्नूर जिले के एक तटीय गाँव एझिमाला में आयोजित की गई थी। विश्व शांति के प्रतीक के रूप में, 1970 के सम्मेलन के लिए चुना गया दिन 11 नवंबर प्रातः 11.11 बजे था। यह युद्धविराम दिवस मनाने के लिए था, जिस दिन प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता आयोजित की गई थी - 11 नवंबर 1918, 11.11 बजे इस सम्मेलन का झंडा नटराज गुरु के शिष्य फ्रेडी वान डेर बोर्गट ने फहराया जो एझिमाला में नारायण गुरुकुलम के प्रभारी थे। 1971 में फील्ड मार्शल के.एम. करिअप्पा ने झंडा फहराया था जो भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ थे। इसका उद्घाटन पोरबंदर के महाराजा परम पूज्य नटवरसिंह जी ने किया था। सम्मेलनों की अवधि भी ग्यारह दिन की थी। इन श्रृंखला में चर्चा किए गए विषय धर्म, विश्व सरकार, विश्व कानून, योग, नैतिकता, सौंदर्यशास्त्र, शिक्षा, अर्थशास्त्र और एकीकृत विज्ञान थे। अलग-अलग विषयों की यह सूची एक नई दुनिया लाने के लिए एकजुट समझ के अनुप्रयोगों या भारतीय दर्शन की क्षमता को दर्शाती है। भारत और विदेश, विशेष रूप से बेल्जियम और फ्रांस के विशेषज्ञों ने विषय प्रस्तुत किए। कुरेन ए.डी ब्रुलर, मार्क अल्बर्ट, फ्रेडी वान डेर बोरघट, पैट्रिक मिशन और ब्रिगिट लैचर्ट नटराज गुरु के विदेशी शिष्य थे जिन्होंने इस अवसर पर बात की। वर्कला की तरह, एझिमाला में भी एक स्थानीय मिथक है जो इसे महाकाव्य रामायण से जोड़ता है। इस पौराणिक संबंध का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व क्षेत्र की एक छोटी पहाड़ी आंजनेय या अंजनी गिरि और वहां स्थापित भगवान हनुमान की 41 फीट ऊंची मूर्ति है।

वर्कला (8° 43' 59.88" उत्तर; 76° 43' 0.12" पूर्व) दक्षिण केरल का तटीय क्षेत्र है जहां भारत के प्राचीन ज्ञान का पुनर्मूल्यांकन हुआ और एझिमाला (12°01°06°N ;75°12°) 57°E) उत्तरी केरल का एक और तटीय गाँव है जहाँ से दुनिया ने 'संगठित समझ के माध्यम से विश्व शांति' का आह्वान सुना। एझिमाला को बाद में सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया अब यह स्थान भारतीय

नौसेना अकादमी का स्थान है।

शिवगिरी मठ और शारदा मंदिर:

जैसा कि खंड 2 में बताया गया है, नारायण गुरुकुल और भारतीय चिंतन में इसका अद्वितीय योगदान गुरु नारायण से उत्पन्न दार्शनिक धारा का प्रतिनिधित्व करता है। शिवगिरी मठ को गुरु नारायण परंपरा की भक्ति धारा का प्रतीक माना जा सकता है। गुरु नारायण का समाधि मंदिर शिवगिरि मठ में है। यह मठ भी वर्कला में है। शिवगिरि मठ के शारदा मंदिर को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है क्योंकि यह आधुनिक समय में गुरु नारायण के मंदिर की अवधारणा की अभिव्यक्ति है। देवी सरस्वती को समर्पित इस मंदिर को 1912 में गुरु द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। इसके विपरीत पारंपरिक मंदिरों का डिज़ाइन में खिड़कियां और वेंटिलेशन के साथ एक अष्टकोणीय आकार है। सरस्वती की मूर्ति कमल पर विराजमान है।

जनार्दनस्वामी मंदिर

अब नारद मुनि की प्रारंभिक कहानी पर वापस जा रहे हैं। उन्होंने अपना वल्कल आकाश से क्यों फेंका? एक किंवदंती के अनुसार, नारद से नौ प्रजापतियों ने मुलाकात की जिन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने पाप किया है। उन्होंने अपने वल्कल को पृथ्वी पर फेंक दिया और प्रजापतियों से कहा कि वे वहां जाएं और अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। तब से वह सुंदर गाँव जहाँ वल्कल गिरे थे, वर्कला नाम से पुकारा जाने लगा। नारद जी ने विष्णु जी से एक देवता बनाने का अनुरोध किया और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके ऐसा किया। ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने वहां विष्णु जी का एक मंदिर बनवाया और जनार्दन के रूप में उनकी पूजा की। इस प्रकार वर्कला का वर्तमान जनार्दनस्वामी मंदिर अस्तित्व में आया, जो महान भारतीय परंपरा की एक और विरासत है।

वर्कला चट्टान, समुद्र तट और पर्यटन

भौगोलिक दृष्टि से भी वर्कला को प्राकृतिक चमत्कार का वरदान प्राप्त है। समुद्र तट की ओर देखने वाली चट्टान वर्कला केरल तट पर एक अद्वितीय तलछटी भू-आकृति की संरचना है। ऐसी रिपोर्टें थीं जिनमें कहा गया था कि वर्कला भारत के पश्चिमी तट पर एकमात्र स्थान है जहां नियो-प्लियोसीन युग (13 लाख से 2.5 करोड़ साल पहले) के तलछट पाए गए हैं। इस स्थल को राष्ट्रीय भू-पार्क घोषित करने का प्रस्ताव है। समुद्र तट और समुद्री चट्टान ने मिलकर वर्कला को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर एक स्थान बना दिया है। आयुर्वेद की सुविधाओं के अलावा वर्कला में एक प्राकृतिक चिकित्सालय भी काम कर रहा है जो चिकित्सा क्षेत्र में दुर्लभ्य है। जनार्दन मंदिर के निकट होने के कारण वर्कला समुद्र तट का धार्मिक महत्व भी है। इस रेतीले मैदान को पितृ तर्पणम और अमावसी तर्पणम जैसे हिंदू अनुष्ठानों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है।

वर्कला - एक मल्टीपल जंक्शन

अनादि काल से उत्पन्न 'दार्शनिक सुपर हाईवे', 'यूनिटिव अंडरस्टैंडिंग' की अवधारणा के माध्यम से वर्कला को एक नया आयाम प्राप्त है। एक पौराणिक धारा भी इस स्थान से जुड़ी जो जनार्दनस्वामी मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हुई। भूगोल/भूविज्ञान के संदर्भ में भी वर्कला को पृथ्वी के इतिहास के पन्नों को संरक्षित करने के मामले में एक अद्वितीय पहचान प्राप्त है।

विवेक द्विवेदी

एसोसिएट प्रोफेसर,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

पुनर्निर्माण की बाट जोहता प्रथम गाँव धनुष्कोडी

तमिलनाडु का सीमावर्ती गाँव 'धनुष्कोडी' 'प्रथम गाँव' की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ यह गाँव आर्थिक रूप से सबल होने की असीम संभावनाएं समेटे हुए है।

हमारा भारतवर्ष अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। पर्वतीय पठार, घने जंगल, बीहड़ क्षेत्र, मैदानी इलाके, मोहक समुद्र तट और कालांतर से अपनी समृद्धि और आधुनिकता का साक्ष्य सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर है ये देश। हालांकि कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिनकी दुर्गमता के कारण उनका अहित भी हुआ।

तमिलनाडु का 'धनुष्कोडी' भी एक ऐसा ही स्थान है जो अपनी अनुकूलता और भौगोलिक प्रभुत्व के चरम पर आने से पहले ही प्रतिकूल परिस्थितियों का शिकार हो गया। उत्तर में 'बंगाल की खाड़ी' और दक्षिण में 'हिंद महासागर' से घिरे इस गाँव में पर्यटन के लिहाज से मनोरम स्थल बन जाने की सभी खूबियाँ उपस्थित हैं। 'पंबन द्वीप' के 'दक्षिण-पश्चिम' छोर पर यह गाँव छोटे से क्षेत्र में स्थित है। 'रामेश्वरम' से इसकी दूरी 18 किलोमीटर है।

तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में स्थित इस गाँव तक पहुँचने के लिए लोगों को रामनाथपुरम होकर जाना पड़ता है जो वर्तमान में संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि भी एक नये रेलवे ब्रिज का निर्माण, पुराने पुल के समानांतर चल रहा है, जिसका काम शीघ्र पूरा होने का अनुमान है।

इस क्षेत्र के अतीत में झांकें तो 1964 में आए चक्रवात ने यहाँ रातों-रात सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। उस साल 22 दिसंबर की दुखद रात को धनुष्कोडी में 1500 से 2000 लोगों के मृत्यु हुई थी। पंबन ब्रिज पर से गुजर रही ट्रेन में सवार सभी 110

यात्री और 5 रेलवे कर्मचारी चक्रवात का शिकार हो गए। स्थानीय निवासियों का मानना है कि ट्रेन में 200 से 400 लोग सवार थे। आज यह गाँव एक खंडहर बना बैठा है जो कभी 700-800 परिवारों का घर हुआ करता था।

धनुष्कोडी में मत्स्य व्यापार, स्थानीय कलाकृतियां, शंख और अन्य समुद्री व्यवसाय का बोल-बाला था। आज 6 दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका है और धनुष्कोडी में 300 से भी कम परिवार रह गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से कई परिवार रामेश्वरम, नटराजपुरम और पंबन जैसे नगरों की ओर चले गए। जो लोग आज भी धनुष्कोडी को छोड़कर नहीं गए वे लोग भी अपने बच्चों को पास के नगर में स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने भेजते हैं।

पुनर्निर्माण का कार्य आसान नहीं होगा, मगर एक सशक्त अर्थतंत्र को स्थापित करने के लिए, धनुष्कोडी के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर ठोस और दूरगामी कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।

1964 की दुर्घटना के बाद राज्य सरकार ने धनुष्कोडी को 'न रहने योग्य' करार देते हुए, एक तरह से इस क्षेत्र को देश की मुख्य भूमि की सुविधाओं और मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया था। अब तक केंद्र सरकारों का रुख भी धनुष्कोडी के प्रति ज्यादा सकारात्मक नहीं रहा है। उस वक्त पंबन ब्रिज का नवनिर्माण तो तत्काल प्रभाव से कर दिया गया, मगर धनुष्कोडी तक जा रही रेलवे लाइन, स्थानीय डाक घर और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र को हमेशा के लिए ठप छोड़ दिया।

आज इसके चलते धनुष्कोडी में सिर्फ जर्जर इमारत, खंडहर बने मंदिर-चर्च, पुराने टूटे पड़े रेलवे ट्रैक और टिन से ढके घर दिखाई देते हैं।

रामेश्वरम से केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर होने के बाद भी धनुष्कोडी में आजतक पुख्ता विकास, स्वास्थ्य सुविधा, संचार व्यवस्था, यात्रा परिचालन जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव है। इस वक्त की केंद्र सरकार ने रामेश्वरम के विकास और समृद्धि को ध्यान में रखकर कुछ कदम उठाए तो हैं मगर, धनुष्कोडी तक उसका लाभ पहुँचता नहीं दिखाई देता। जहां पंबन द्वीप में रेल और रोड यातायात को सुगम बनाने के कार्य प्रगति पर है, तो वहीं धनुष्कोडी के विकास के लिए अधिग्रहण के कार्यों में सरकार को कोरोना काल से ही देरी और अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान राज्य सरकार ने धनुष्कोडी के तटीय क्षेत्र को 'प्राकृतिक रूप से संवेदनशील' बताते हुए-रेलवे परियोजना के अंतर्गत जमीन अधिग्रहण के समझौते से हाथ पीछे खींच लिए हैं।

धनुष्कोडी की भौगोलिक स्थिति उसके लिए एक वरदान समान है। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो धनुष्कोडी में वह क्षमता है जो पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाये-वाणिज्यिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को सरकार बढ़ावा दे सकती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'लक्षद्वीप माला' में 19000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई अन्य परियोजनाओं की स्वीकृति दी। देश की जनता 'मालदीव' के विकल्प के तौर पर भारत के प्रतिभाशाली द्वीप समूहः लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और अन्य पर्यटन क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। देश की केंद्र सरकार और तमिलनाडु राज्य सरकार को धनुष्कोडी के पुनर्निर्माण कार्यों में निवेश और स्थानीय लोगों के पुनर्वास पर अपना जोर देना चाहिए। श्रीलंका से नजदीकी के कारण-तमिल भाषी लोगों का पलायन भी एक चिंता का विषय बना रहता है। सामरिक संबंधों के साथ-साथ देश की निजी

सुरक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

सांस्कृतिक रूप से भी धनुष्कोडी भारत के इतिहास का एक अभिन्न अंग रहा है। यह स्थल रामसेतु से बिल्कुल नजदीक है। ऐसे मे अपनी राष्ट्रीय धरोहर की उपेक्षा कर भविष्य की संभावनाओं को व्यर्थ करने से बेहतर है। दीर्घकालीन दृष्टि से इस क्षेत्र में विकास और पर्यटन पर अग्रसर होना चाहिए।

पुनर्विकास, पर्यटन से जुड़ी समस्या, उनका समाधान और व्यापार में वृद्धि की अपार संभावना

तमिलनाडु राज्य सरकार ने पिछले साल अप्रैल में धनुष्कोडी समेत 7 पर्यटन सथलों में 25 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार को भी भारत की आर्थिक आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए सार्थक कदम उठाने होंगे। व्यापार की दृष्टि से काम करते हुए केंद्र सरकार ने नए बन रहे पंबन ब्रिज को '22 डीग्री नेविगेश्नल क्लियरंस' के साथ पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊँचा बनवाया है।

स्थानीय निवासियों में हस्तकला से बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना' के अंतर्गत आने वाले प्रतिभाशाली लोगों को प्रक्षिशण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। स्थानीय भोजन और लोकगीत के प्रचार-प्रसार को मुख्य भूमि और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी प्रयास होना चाहिए।

पुनर्निर्माण का कार्य आसान नहीं होगा, मगर एक सशक्त अर्थतंत्र को स्थापित करने के लिए धनुष्कोडी का जीर्णोद्धार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर ठोस और दूरगामी कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 1964 के चक्रवात से पहले धनुष्कोडी में कोई बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रवास नहीं था। मगर वहाँ एक फलता-फूलता अर्थतंत्र था। एक समृद्ध आबादी थी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रणाली थी। आधुनिक परिचालन सुविधा नहीं थी, मगर श्रद्धालुओं का तीर्थाटन था। आज भी धनुष्कोडी में पुनर्विकास, पर्यटन और व्यापार में वृद्धि की अपार संभावनाएँ हैं।

ओडिशा तट : एक अवलोकन

निहार आर. नायक

मनोहर पर्रीकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान [IDSA] नई दिल्ली में अध्येता

ओडिशा विविध भू-भौतिकीय और भू-आर्थिक विशेषताओं से युक्त 487 किलोमीटर लंबी तटरेखा का दावा करता है । इस क्षेत्र के अंतर्गत सात तटीय जिले आते हैं जिनमें कुल 3,878 मछली पकड़ने वाले गाँव हैं इनमें 813 समुद्री और 3,065 अंतर्देशीय गाँव शामिल हैं। इन गाँवों की आजीविका का प्राथमिक स्रोत मछली पकड़ने और धान की खेती करने के आस-पास घूमता है । हालाँकि बंगाल की खाड़ी से लगातार चक्रवातों और मानसूनी बाढ़ से आने से पूरे समुद्र तट की संवेदनशीलता के कारण राज्य के अन्य गाँवों की तुलना में इन गाँवों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है । आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे का अभाव इन समुदायों की आर्थिक गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है ।

तटीय सुरक्षा प्रबंधन

वर्तमान में ओडिशा के अंतर्गत केवल 18 समुद्री पुलिस स्टेशन हैं जो महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं – जैसे कि रक्षा संगठन और प्रमुख/छोटी बंदरगाह जो इसके तटीय क्षेत्रों से जुड़े हैं और इसके तटीय पर्यावरण के संरक्षण पर स्थित हैं। ओडिशा पुलिस सुरक्षा परिदृश्य का नियमित और अवधि के अनुसार मूल्यांकन करती है। जिसका काम अवैध प्रवास का पता लगाने और समुद्र के असामाजिक तत्वों के प्रवेश को रोकने पर केंद्रित है।

समुद्र और जमीन दोनों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, समुद्री पुलिस स्टेशनों (एम.पी.एस.) द्वारा नियमित गश्त के लिए फास्ट इंटरसेप्टर नौकाओं और वाहनों को तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त तटीय क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय को

सूचित और सतर्क रखने के प्रयास किए जाते हैं। उन्हें खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और किसी भी प्रकार की चिंताजनक सूचना तुरंत अधिकारियों को बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मछली पकड़ने वाले समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए मासिक रूप से एक तटीय सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय तटरक्षक बल की सहायता से "सजग" नामक एक मासिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस ड्रिल के अंतर्गत नौकाओं की व्यापक जाँच और समुद्र में चलने वाली मछली पकड़ने वाली सभी नौकाओं के दस्तावेजों का सत्यापन शामिल है, जिससे तटीय सुरक्षा उपायों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

ये तीन गाँव ही क्यों?

इस अध्ययन में तीन तटीय गाँवों- खरसाहापुर, धिनकिया और अराखाकुडा को समुद्र से उनकी निकटता, रणनीतिक स्थानों और विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं के कारण 'प्रथम ओडिशा गाँव' के रूप में नामित किया गया है।

खरशाहपुर - बालासोर जिला

खरशाहपुर गाँव उप-जिला मुख्यालय, सोरो (तहसीलदार कार्यालय) से 45 किमी दूर और जिला मुख्यालय, बालासोर से अन्य 45 किमी दूर स्थित है। 7,051 लोगों की कुल आबादी के साथ, खरशाहपुर में लगभग 1,758 घर हैं। रणनीतिक रूप से, यह गाँव चाँदीपुर मिसाइल परीक्षण सुविधा, व्हीलर द्वीप और प्रसिद्ध खिरचोरा गोपीनाथ मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक सुंदर समुद्री तट भी है। पड़ोसी भद्रक जिले में धामरा समुद्री बंदरगाह भी गाँव से लगभग 50 कि.मी. दूर स्थित है।

ढिंकिया - जगतसिंहपुर जिला

ढिंकिया गाँव बंगाल की खाड़ी तट से लगभग दो किलोमीटर दूर स्थित है। निकटता में कैप्टिव बंदरगाह, जटाधारी, आयात और निर्यात गतिविधियों के लिए एक सुविधाकर्ता के रूप में काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त पारादीप बंदरगाह, भारत के शीर्ष 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक इस गाँव से लगभग 15 कि.मी. दूर स्थित है। ढिंकिया की भूमि के व्यापक हिस्से मुख्य रूप से पान या काजू के पौधों से आच्छादित हैं जबकि कुछ क्षेत्र स्थानीय ग्रामीणों द्वारा झींगा की खेती के लिए समर्पित हैं। राजधानी भुवनेश्वर को पारादीप से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी इस गाँव से मात्र 12 कि.मी. दूर है।

विशेष रूप से जे.एस.डब्ल्यू. स्टील ने हाल ही में उसी साइट पर 53,700 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कैप्टिव उपयोग के लिए 900 मेगावाट बिजली संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा की है, जहाँ पोस्को को शुरू में एक उद्योग स्थापित करने की उम्मीद थी।

अराखाकुडा- पुरी जिला

अराखाकुडा पुरी जिले के ब्रह्मगिरि ब्लॉक में स्थित एक मछली पकड़ने वाला गाँव है और इसके निवासी पीढ़ियों से चिल्का झील में मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। जो बात अराखाकुडा को विशेष बनाती है वह है; मगरमुख चैनल पर स्थित पहला गाँव होने का दर्जा, जो झील को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। नतीजतन ग्रामीणों को मानवीय हस्तक्षेप और प्राकृतिक प्रक्रियाओं दोनों के कारण झील प्रणाली में होने वाले परिवर्तनों का प्रत्यक्ष ज्ञान है। यहाँ के निवासी घटती लवणता, झील के उथले होने, मछली पकड़ने की गतिविधियों में वृद्धि अथवा मछली पकड़ने में गिरावट के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं।

52 पुरुषों और 226 महिलाओं सहित 478 व्यक्तियों की कुल आबादी के साथ अराखाकुडा की साक्षरता दर 50.63 प्रतिशत है। साक्षर आबादी में 55.56 प्रतिशत पुरुष और 45.13 प्रतिशत महिलाएँ हैं। इस गाँव में

लगभग 99 घर हैं और यह प्रसिद्ध कालीजाई मंदिर और आई.एन.एस. चिल्का से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित है।

चुनौतियाँ

इन गाँवों को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

1. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। जिसके परिणामस्वरूप 247 तटीय गाँवों से एक महत्त्वपूर्ण आबादी का विस्थापन हुआ है, जबकि 16 गाँव पहले से ही पानी में डूबे हुए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, चेन्नई के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 74 गाँव तटरेखा कटाव से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, जो देश की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है।

2. राज्य सरकार द्वारा एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित तटरेखा प्रबंधन योजना, बालासोर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी और गंजम जिलों में तटीय कटाव की संभावना को इंगित करता है। हाल ही में किये गए अध्ययन के अनुसार 487 किलोमीटर लंबी ओडिशा तटरेखा के 55.85 प्रतिशत हिस्से में वृद्धि का अनुभव होने का अनुमान है, जबकि 44.15 प्रतिशत हिस्से में क्षरण होने या वर्ष 2050 तक निरंतर प्रवृत्ति प्रदर्शित होने की उम्मीद है।

3. समुद्र तट की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई पहल स्वीकृत धन की कमी के कारण रुकी हुई है। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान समुद्र विशेष रूप से खतरनाक प्रतीत होता है, जिससे तटीय क्षेत्रों को नुकसान होता है। निकट भविष्य में एक एकड़ कृषि योग्य भूमि और पान के बेलों को पूरी तरह डूबने से रोकने के लिए सरकार द्वारा तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है।

4. इन गाँवों में व्यावसायिक चुनौतियाँ बरकरार हैं क्योंकि मछली पकड़ना अब केवल पारंपरिक मछली पकड़ने वाले समुदाय तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ ही मछुआरों को आधुनिक मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर और जाल के उपयोग को अपनाने तथा बाहरी लोगों से नई आर्थिक प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । ग्रामीणों को संपार्श्विक की अनुपस्थिति के कारण औपचारिक क्षेत्र से ऋण हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिससे अक्सर स्थानीय जमींदारों से भूमि प्राप्त करके मछली पकड़ने के उपकरण प्राप्त करते समय वे ऋण-जाल में फँस जाते हैं।

5. इसी तरह की दुर्दशा का सामना गैर-मछली पकड़ने वाले समुदायों को करना पड़ता है, विशेष रूप से किसान जो अपनी आजीविका के लिए पान के पत्ते, काजू, शहद, झींगा खेती और धान की खेती पर निर्भर हैं। ये किसान चक्रवात, बाढ़ और समुद्री लहरों से मिट्टी के कटाव के कारण फसल के नुकसान और भूमि क्षति की स्थिति में राज्य सरकार से वित्तीय सहायता और वैकल्पिक भूमि सहायता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। नतीजतन, इन ग्रामीणों की एक बड़ी संख्या ने खेती के लिए अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को अपनी जमीन पट्टे पर देने का सहारा लिया है।

6. अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, जलाऊ लकड़ी की खरीद तेजी से चुनौतीपूर्ण हो गई है, मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में हेंटल वनों या मैंग्रोव को अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या आरक्षित वन के रूप में नामित किए जाना इसका मुख्य कारण है। अराखाकुडा ग्रामीणों के मामले में, जंगल या तो गायब हो रहे हैं, या यदि वे मौजूद भी हैं, तो ग्रामीणों के लिए उन तक पहुँच प्रतिबंधित है। बड़े पैमाने पर लोग अब सारी लकड़ी निकालने के लिए ट्रैक्टरों का उपयोग करते हैं, जिससे ग्रामीणों के पास उनसे इसे खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है, भले ही उन्हें इसके लिए काफी कीमत चुकानी पड़ती है।

सत्रसाल : असम की सीमा के प्रथम गाँव का विहंगावलोकन

पार्थ प्रीतम

प्रसिद्ध संगठनों में 20 वर्षों से अधिक के मजबूत, निर्णायक कार्यकारी नेतृत्व का अनुभव

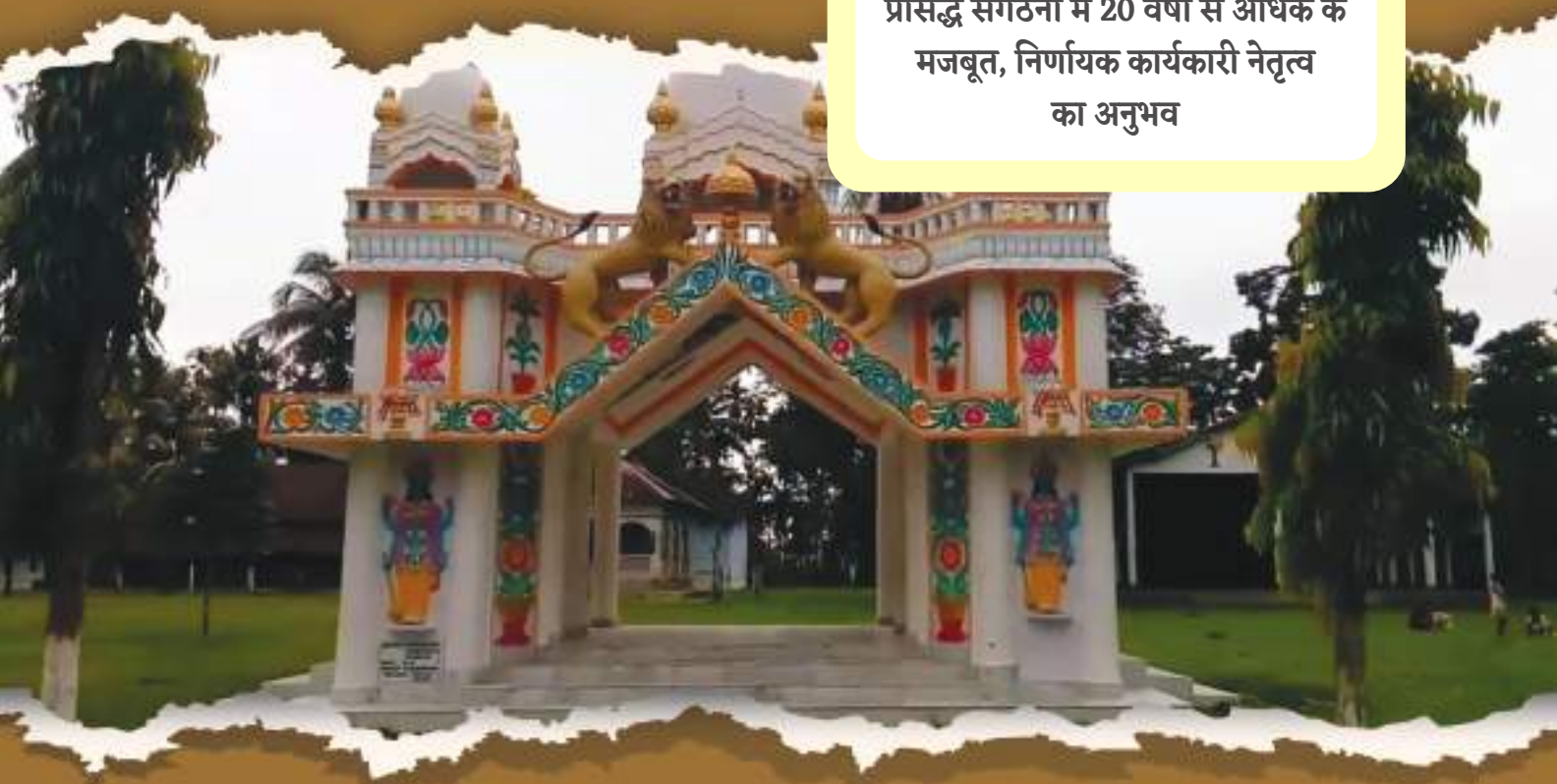

भूगोल

असम के धुबरी जिले की अगोमानी तहसील में बसा एक गाँव सत्रसाल इस सीमावर्ती क्षेत्र की विविध भौगोलिक विशेषताओं का साक्षी है। जिला मुख्यालय धुबरी से 33 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सत्रसाल रणनीतिक रूप से पश्चिम बंगाल की सीमा के पास स्थित है, जो समुद्र तल से 47 मीटर की ऊँचाई पर है। गौरंग और जलढाका नदियों से निकटता इस गाँव की विशेषता है जो इसके भौगोलिक आकर्षण को बढ़ाती है।

स्थानीय भौगोलिक चुनौतियाँ और समाधान

गाँव को ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र और जलवायु की विषमता सहित भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, सत्रसाल के कर्मठ निवासियों ने अपनी मातृभूमि के प्रति अनुकूलता और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए इन बाधाओं के निवारण हेतु सहज समाधान खोजे हैं।

ज्ञात और अल्पज्ञात पर्यटन स्थल:

अपने महत्त्व से परे सत्रसाल में पर्यटन स्थलों की

एक समृद्ध शृंखला है। चमत्कृत करते पर्वतीय दृश्यों से लगाकर शांत-सुरम्य नदी तटों तक, यह गाँव यात्रियों को अपने विविधता से भरे भू-दृश्यों के लिए आमंत्रित करता है। यह आलेख प्रसिद्ध और अल्पज्ञात, दोनों प्रकार के पर्यटन स्थलों पर प्रकाश डालता है, जिसमें क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता की लिए गहन पड़ताल को उभारता है।

रामरायकुटी सत्र

रामरायकुटी सत्र अपने गहन ऐतिहासिक महत्त्व के साथ एक पवित्र आध्यात्मिक स्थल के रूप में भारत-बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सीमा पर असम के धुबरी जिले के सत्रसाल में स्थित है। सीमाओं के करीब स्थित यह पवित्र स्थान न केवल अपने आध्यात्मिक महत्त्व के लिए बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाने के संदर्भ में भी एक अद्वितीय स्थान रखता है।

ऐतिहासिक महत्त्व

रामरायकुटी सत्र का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिसका कालखंड रामराय (श्री शंकरदेव के चचेरे भाई) की बेटी चिलाराई और भुवनेश्वरी के विवाह समारोह से जुड़ा हुआ है। पूज्य संत और सांस्कृतिक प्रतीक श्री शंकरदेव ने इसकी स्थापना इस क्षेत्र में सत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रचार-प्रसार करने के मूल उद्देश्य के साथ की थी। यह सत्र सांस्कृतिक सम्मिलन और ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, जिसने असम की सांस्कृतिक छवि को स्वरूप प्रदान किया।

सांस्कृतिक प्रचार और प्रसार

परमपूज्य गुरु श्री शंकरदेव द्वारा स्थापित रामरायकुटी सत्र सत्रीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए एक विशेष केंद्र के रूप में कार्य करता है। सत्रीय संस्कृति में विभिन्न कला-रूप, नृत्य, संगीत और अनुष्ठान शामिल हैं और सत्र इन परंपराओं को भविष्य की पीढ़ियों तक संरक्षित और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीमा पर शांतिपूर्ण स्थान सत्र की सांस्कृतिक जीवंतता में एक अनूठा आयाम जोड़ता है।

ऐतिहासिक रथ

रामरायकुटी सत्र की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक ऐतिहासिक पीतल निर्मित रथ का संरक्षण है। यह रथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व रखता है, जो अतीत से एक विशिष्ट कड़ी के रूप में भी जोड़ता है। कलात्मक तरीके से तैयार किया गया रथ त्योहारों और धार्मिक समारोहों का केंद्र बिंदु बन जाता है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

धार्मिक और आध्यात्मिक क्रिया-कलाप

रामरायकुटी सत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्तगण धार्मिक और आध्यात्मिक क्रिया-कलापों में सहभागिता करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सीमाओं के निकट शांत वातावरण सत्र में आने वाले लोगों की आध्यात्मिक गतिविधियों में शांति के भाव को जोड़ता है। अनुष्ठान, प्रार्थनाएँ और सांस्कृतिक प्रदर्शन जीवंत आध्यात्मिक वातावरण के निर्माण में योगदान करते हैं, जिससे अनुयायियों के बीच भक्तिभाव और सामुदायिक कार्य की भावना को बल मिलता है।

सांस्कृतिक विरासत संरक्षण

सत्र सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न प्रयासों-गतिविधियों के माध्यम से रामरायकुटी सत्र पारंपरिक कला रूपों, पांडुलिपियों और कलाकृतियों को संरक्षित करने का प्रयास करता है, जो असम के सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाते हैं। संरक्षण के प्रति यह प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि क्षेत्र की समृद्ध विरासत जीवित रहे और भावी पीढ़ियों के लिए सुलभ बनी रहे।

अंतर्धार्मिक सद्भाव

सीमा पर स्थित रामरायकुटी सत्र विभिन्न समुदायों और आस्थाओं के मानने वालों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। सत्र अंतर-धार्मिक सद्भाव के वातावरण को बढ़ावा देता है, जहाँ अलग-अलग मान्यताओं-पृष्ठभूमियों के लोग सहज भाव से एकत्र होते हैं और सामूहिक सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से एक सूत्र में बँधते हैं। यह समावेशी दृष्टिकोण विभिन्न मतानुयायियों के बीच सामाजिक एकजुटता और एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ाने में योगदान देता है।

पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान

भारत-बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित होने के कारण रामरायकुटी सत्र एक सांस्कृतिक केंद्र कहा जा सकता है। पड़ोसी क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने हेतु सत्र सक्रिय रूप से संलग्न है। जिससे साझा परंपराओं की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। यह आदान-प्रदान सांस्कृतिक विविधता को विस्तार देने में योगदान देता है और विविध समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करता है।

पर्यावरण संरक्षण पहल:

पर्यावरण प्रबंधन के महत्त्व को पहचानते हुए रामरायकुटी सत्र पर्यावरण संरक्षण के लिए भी पहल करता है। सीमाओं के पास शांत प्राकृतिक परिवेश को महत्त्व दिया जाता है और सत्र सक्रिय रूप से पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जो भक्तों और स्थानीय समुदाय दोनों को पर्यावरण के प्रति दायित्ववान और पर्यावरण का संरक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है।

पर्यटन और तीर्थयात्रा:

रामरायकुटी सत्र अपने ऐतिहासिक महत्त्व और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को समान रूप से आकर्षित करता है। सत्र आध्यात्मिक प्रतिपूर्ति, सांस्कृतिक संवर्धन और असम के इतिहास की झलक के आकांक्षी जनों के लिए एक तीर्थस्थल बन जाता है। आगंतुकों की निरंतर आमद स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देती है और क्षेत्र में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देती है।

जीवंत विरासत और भविष्य की आकांक्षाएँ:

चूँकि रामरायकुटी सत्र आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सांस्कृतिक संरक्षण की अपनी विरासत को जारी रखे हुए है, इसलिए बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने के प्रयास भी जारी हैं। संक्षेप में, रामरायकुटी सत्र न केवल एक भौतिक संरचना के रूप में, बल्कि आध्यात्मिकता और संस्कृति के अंतर्संबंध के एक जीवंत साक्ष्य के रूप में खड़ा है। सीमा पर इसकी सुदृढ़ उपस्थिति सांस्कृतिक विरासत की समेकित शक्ति एवं सीमाओं से परे यह असम और उससे आगे के लोगों के बीच साझा पहचान के भाव को विस्तार देती है।

पल्लबी गोगोई

सीनियर रिसर्च फेलो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

भैरबकुंड: इंडो-भूटान बॉर्डर का प्रथम गाँव

असम के उदलगुरी जिले के मध्य में बसा एक खूबसूरत गाँव है जिसका नाम है 'भैरबकुंड'। भारत-भूटान सीमा पर स्थित यह अपनी सुंदरता के कारण पहली नज़र में ही सभी को मंत्रमुग्ध कर देने वाले गाँवों में से एक है। अपने सहज प्राकृतिक आकर्षण के रूप में विद्यमान यह गाँव भूटान के पूर्वी प्रांत के प्रवेश द्वार के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नदियों के संगम और पवित्र शक्तिपीठ से आगंतुकों को आकर्षित करने वाले, भैरबकुंड का सांस्कृतिक महत्त्व गहराई से प्रतिध्वनित होता है। अपने पारिस्थितिक आश्चर्यों से परे भैरबकुंड एक सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में खड़ा है, जो भूटानी और बोडो परंपराओं की समृद्ध टेपेस्ट्री का अनावरण करता है। भैरबकुंड का वार्षिक पर्यटन महोत्सव, स्थानीय जीवंतता का उत्सव, मनमोहक लोक नृत्य, मनोरम पारंपरिक व्यंजन और जीवंत उत्सव दिखाता है, जो यहाँ आए विवेकी आगंतुकों को इसकी समृद्ध संस्कृति एवं पारिस्थितिक विविधता का गहन अनुभव तथा उसमें हिस्सा लेने के लिए लुभाता है।

भूटान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे

भाबेश हजारिका

पीएचडी, अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान

भारत-भूटान सीमा के रूप में जाना जाता है, 699 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह भूटान साम्राज्य को भारत गणराज्य से पृथक करती है। परस्पर खुली सीमा कई भारतीय राज्यों तक फैली हुई है। विशेष रूप से यह असम में 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 183 किलोमीटर और सिक्किम में 32 किलोमीटर तक सीमा विस्तार है। भूटान और असम के बीच की सीमा असम के चार जिलों में विभिन्न बिंदुओं को काटती है: कोकराझार जिले में सरलपारा, बक्सा जिले में दरंगा, उदलगुरी जिले में भैरबकुंड और चिरांग जिले में दादगिरी । इनमें से भैरबकुंड गाँव, भारत-भूटान सीमा पर उदलगुरी जिले का पहला गाँव है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है।

भूटान के पूर्वी प्रांत के लिए एक पारगमन बिंदु के रूप में भैरबकुंड उदलगुरी के जिला मुख्यालय से लगभग 22 कि.मी. उत्तर में और भूटानी शहर 'डेफाम' के करीब स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह गाँव 29.51 हेक्टेयर में फैला है और इसमें 273 व्यक्तियों की आबादी है, जिसमें 144 पुरुष और 129 महिलाएँ हैं। साक्षरता दर 69.23% है। जिसमें पुरुषों में 74.31% और महिलाओं में 63.57% है।

भैरबकुंड न केवल असम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश के बीच भौगोलिक सीमाओं बल्कि जिया धनसिरी, भैरवी और दाइफाम नदियों के लिए भी एक अभिसरण बिंदु के रूप में कार्य करता है। इन नदियों का संगम एक पवित्र 'कुंड' जैसा दिखता है, जो भगवान शिव को समर्पित एक पूजा स्थल की याद दिलाता है। यह अनूठी विशेषता संभवतः भैरबकुंड के नामकरण में योगदान करती है, जो इसके आध्यात्मिक और भौगोलिक महत्त्व को रेखांकित करती है। इस क्षेत्र का विन्यास शिव के निवास से जुड़े आध्यात्मिक महत्त्व को प्रतिध्वनित करता है। भूटान के दाइफाम में भैरबकुंड के पास शिव (भैरब बाबा) मंदिर को शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जो इसकी पवित्रता को अधिक महत्त्व देता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शक्तिपीठ पवित्र स्थल है जहाँ सती के जले हुए शरीर के हिस्सों को भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से बिखेर दिया था। प्रत्येक में शिव के भैरव स्वरूप को समर्पित एक मंदिर है। "मकर

संक्रांति" के दौरान भक्त इन तीन नदियों के संगम पर स्नान के अनुष्ठान के लिए आते हैं और शिव मंदिर में पूजा करते हैं। लोककथाओं के अनुसार यहाँ एक पवित्र कुंड मौजूद था जहाँ भक्त पूजा करते थे और मछलियाँ चावल का प्रसाद लेती थीं। ये मछलियाँ शांति हेतु पवित्र जल छिड़कती थीं। परंतु अशुद्ध व्यक्तियों से स्वयं को बचाने का प्रयास करती थी। एक अन्य कहानी में शिव उपासक भक्त बोडो, प्राचीन खेराई नृत्यों के माध्यम से प्रार्थना करते थे। भगवान भक्तों के बीच प्रकट हुए। उन्होंने एक उपासक के घर में सभी संगीत वाद्ययंत्रों को इकट्ठा किया, जो बाद में जल गए, जिससे वे गायब हो गए।

भैरबकुंड विशेष रूप से पिकनिक के शौकीनों के लिए एक आकर्षक स्थल है। धनसिरी नदी का पारदर्शी साफ़ पानी, चारों ओर फैली चट्टानें, विशाल खुले क्षेत्र और निकटवर्ती पहाड़ियाँ सामूहिक रूप से प्राकृतिक सुंदरता व्यापक रूप से सर्वत्र फैली हुई है। यह स्थान सबसे पसंदीदा पिकनिक स्थलों में से एक माना जाता है। यह देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को पिकनिक और अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए तथा एक शांत वातावरण की तलाश के लिए भी आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त भैरबकुंड को दाइफाम से जोड़ने के लिए स्टील केबलों से एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। पर्यटन स्थल और फोटोग्राफी के लिए एक सुरम्य स्थान के रूप में पहचाने जाने वाले डेफाम तक इस पुल के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है। पास का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल, द्विजिरी झरना, भैरबकुंड-उदलगुरी सड़क के किनारे स्थित है। पर्यटकों की बड़ी संख्या को आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष जनवरी में भैरबकुंड पर्यटन महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम धनसिरी नदी के किनारे और भैरबकुंड पर्यटन परिसर में आयोजित किया जाता है। यह त्योहार पड़ोसी भूटान और अरुणाचल प्रदेश सहित विभिन्न जातीय और भाषाई समूहों के बीच भाईचारे, एकता और सांस्कृतिक अखंडता के स्थाई बंधन को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

भैरबकुंड अपने विशाल 450-हेक्टेयर मानव निर्मित जंगल के साथ पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए एक उल्लेखनीय प्रमाण के रूप में प्रकट होता है जो उदलगुरी में संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जे.एफ.एम.सी) द्वारा संचालित एक सहयोगी पहल है। इस महत्त्वाकांक्षी वनीकरण परियोजना को शुरू में एक दुर्जेय चुनौती का सामना करना पड़ा जो थी एक विश्वसनीय जल स्रोत के बिना पौधों का पोषण करना। इस बाधा को दूर करने के लिए समुदाय ने अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली धनसिरी नदी का उपयोग करते हुए वहाँ से 4 किलोमीटर लंबे सिंचाई चैनल का निर्माण किया। इसे लागू करते हुए धनसिरी से दो अतिरिक्त सिंचाई चैनलों की सावधानीपूर्वक खुदाई की गई। जिससे नए लगाए गए पौधों को संभावित पानी की कमी से बचाया जा सका। इस ठोस प्रयास ने उदलगुरी सिविल उप-मंडल के भीतर पाँच विकास खंडों को फैलाया। अंततः इस परियोजना के अंतर्गत 41.683 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभांवित किया गया। इन संरक्षण प्रयासों की परिणति न केवल मजबूत पौधों की वृद्धि थी बल्कि एक विशिष्ट मानव निर्मित हरे आवरण में परिदृश्य का क्रमिक रूपांतर भी था जिसे अब गेथसेमेन मानव निर्मित वन (जी.एम.एम.एफ) के रूप में जाना जाता है। महज पाँच साल की अवधि में सपन गाँव में विस्मयकारी गेदसिमनी वन (जे.एफ.एम.सी.) उभरा। जिसने 5,500 बीघे बंजर रेतीली भूमि को एक सुरम्य परिदृश्य में बदल दिया।

व्यापक परिवर्तन में भूटान के निकट धनसिरी नदी के किनारे खोइर, गोमारी, सिमुल, शीशम जैसी मूल्यवान प्रजातियों को शामिल करते हुए 14,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। समय के साथ यह पुनर्जीवित जंगल विभिन्न प्रकार के पशुओं एवं पक्षियों की प्रजातियों के लिए एक अभयारण्य के रूप में विकसित हुआ है, जो

संरक्षण प्रयासों का एक शानदार उदाहरण पेश करता है। हरा-भरा विस्तार अब पारिस्थितिक विविधता के लिए स्वर्ग के रूप में कार्य करता है, जो इस पुनर्जीवित पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पतियों और जीवों के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का प्रतीक है।

अपने पारिस्थितिक महत्त्व से परे, भैरबकुंड भूटान के पूर्वी प्रांत के लिए एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है। अपने स्थानीय वाइन व्यापार के लिए विशेष रूप से पहचाना जाने वाला 'डेफ़ाम' वहाँ के सांस्कृतिक अनुभव में एक अनूठा स्वाद जोड़ता है। इसके अलावा, भैरबकुंड के पर्यटक बोडो संस्कृति की समृद्ध टेपेस्ट्री में तल्लीन हो सकते हैं, जो भारत के आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है। पिकनिक का माहौल धनसिरी नदी के किनारे एक जीवंत स्थानीय बाज़ार लाता है, जो विभिन्न स्वदेशी उत्पादों के साथ जुड़ने और उनका आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। भैरबकुंड पर्यटन महोत्सव, जनवरी में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है जो धनसिरी नदी के सुंदर तटों और भैरबकुंड पर्यटन परिसर में अपने जीवंत उत्सव का आयोजन करता है। अपने प्रदेश की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आयोजित यह उत्सव यहाँ की समृद्ध स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी रूपरेखा तैयार करता है। त्योहार के मुख्य आकर्षण में मनमोहक लोक नृत्य, मधुर संगीत, पारंपरिक व्यंजन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा भूटान के पारंपरिक परिधानों की प्रदर्शनियाँ शामिल हैं। उत्साह को बढ़ाते हुए उत्सव के दौरान उपस्थित लोग हाथी और जीप सफारी जैसी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जो सभी के लिए एक गहन और समृद्ध अनुभव प्रदान करता है। भैरबकुंड, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक समृद्धि और जीवंत उत्सवों के अपने अनूठे मिश्रण के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बहुमुखी रत्न के रूप में खड़ा है, जो यात्रियों और उत्साही लोगों को इसकी विविधता की शोध करने के लिए प्रेरित करता है।

प्रथम सूर्योदय का गाँव : किबिथू

डॉ. जजाति के. पटनायक

सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय - नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर

एक्ट ईस्ट पॉलिसी (एईपी), प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीमा नीति निर्माण में एक अत्यंत प्रभावी कार्य है। जिसने सीमा कल्पना को प्रतिबंधात्मक स्थान से सहभागी स्थान में परिवर्तित कर दिया है।

सहभागी स्थान में ध्यान का नवीनीकरण सम्मिलित है जो आर्थिक, जनसांख्यिकीय विकास और भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक पुनर्परिभाषा को जोड़ता है। यह पुनर्परिभाषित प्रक्रिया सीमा क्षेत्र को आवश्यक रूप से देश की सीमा के अंत के रूप में नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से इसके आरंभ के रूप में अवधारणाबद्ध करती है। यह नीतिगत परिवर्तन देश के सीमा क्षेत्र के महत्व को इंगित करता है। इस संबंध में किबिथू को 'भारत का प्रथम गाँव' घोषित करने का भारत सरकार का निर्णय गतिविधि, एकता और अंतर्संबंध के स्थान के रूप में सीमा के लिए इसके महत्व को व्यक्त करता है। यह एक नए भारत का दृष्टिकोण है जो हमारे देश के प्रत्येक इंच पर समान ध्यान देता है और परिसीमा और केंद्रीय द्वि-आधारी के चश्मे से मूल्यांकन नहीं करता है। स्वतंत्रता के पश्चात से पूर्वी हिमालय की सीमा पर जो उपेक्षा बरती गई, उसने एईपी में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण और नीतिगत पुनर्जीवन प्राप्त किया है। यह सुदृढ़ आधारभूत संरचना के विकास व संस्थागत क्षमता में पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है।

किबिथू का प्रकरण विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है।

डॉ. चंदन के. पांडा

राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर में अंग्रेजी विभाग में सहायक प्रोफेसर।

यह भारत का प्रथम हिमालयी गाँव है, जहां सूर्य का उदय होता है। किबिथू के सक्रिय होने के साथ भारत अस्तित्व में आता है। किबिथू समुद्र तल से 1305 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश के अन्जा जिले में स्थित है और लोहित नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है। इसकी मनमोहक सुंदरता इसकी विशिष्टता सुनिश्चित करती है। यह भारत और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) की सीमा पर स्थित प्रथम मंडल मुख्यालय है जो भारत और तिब्बती स्व्यतत्ता क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। तिब्बत में चीनी आक्रामकता और उसके परिणाम के कारण 1950 के दशक में तिब्बत पर चीन का अधिकार हो गया, जिसने क्षेत्र की भू-राजनीति को अस्त-व्यस्त कर दिया। 1962 में भारत-चीन युद्ध के पश्चात स्थिति और भी विकट हो गई। 1962 के युद्ध के पश्चात जीवंत व्यापार, सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्क और आदान-प्रदान सहसा बंद हो गया। तब से चीन ने कभी भी सहयोग का वातावरण विकसित नहीं किया। धीरे-धीरे भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए सलामी स्लाइसिंग (विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार हेतु सीमा पर छोटी सैन्य कार्यवाही) की स्थिति उत्पन्न हुई और सीमा क्षेत्र ने सीमांत चरित्र प्राप्त कर लिया और कोई विकासात्मक ध्यान नहीं दिया गया।

2014 में पूर्वोत्तर पर समर्पित भाव व निर्णायक रूप से ध्यान दिया गया और इसका परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहा है। इससे चीन अत्यधिक व्यग्र है। यह प्रयास भारत में क्षेत्रीय विस्तार के प्रति चीन की सनक को रोकता है। इसमें चीन के विस्तारवाद को उचित प्रतिक्रिया मिलती है। भारतीय पक्ष की ओर से अपेक्षित प्रतिरोध चीन को अनिश्चित स्थिति में रखता है। डोकलाम और तवांग में सीमा विवाद वांछित प्रगति नहीं होने की उसकी व्यग्रता को दर्शाता है। यह व्यग्रता स्थायी स्वरूप धारण कर लेगी क्योंकि भारत इतना दृढ़ है कि वह चीन को किसी भी क्षेत्रीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा। यह संकल्प धरातल पर दिख रहा है।

चीनी निराधार व अतार्किक दावों और उसके अवैध मानचित्रात्मक अभ्यास से अपनी अखंडता की रक्षा के लिए भारत ने पूर्वोत्तर, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में जो सैन्य तंत्र और प्रत्युत्तर कार्रवाई विकसित की है, वह चीनी अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। अरुणाचल प्रदेश के लिए चीन की स्थानिक भूख भारत को मात देना और पूर्वोत्तर में विकास प्राप्त करने में उसकी गति को सीमित करना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चीनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा में कोई निश्चित प्रगति नहीं होगी। उन्होंने भारत और इसकी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए संपर्क, राजमार्ग, हवाई अड्डे, रेलवे और सैन्य तंत्र सुनिश्चित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा प्रथम गाँव किबिथू का दौरा करने का आह्वान जुड़ाव के प्रयासों को बताता है, न कि ऐतिहासिक रूप से उपस्थित उदासीनता और उपेक्षा के व्यवहार को। किबिथू के मार्ग को अपर्याप्त और असुरक्षित मार्ग या अनामिकता के भय की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। यहीं से भारत का आरंभ होता है। आज किबिथू तक परिवहन और संचार की सुगमता प्रथम गाँव की कल्पना को यात्रा के लिए और अधिक आकर्षक बनाती है।

ऐतिहासिक रूप से किबिथू ने तिब्बत और भारत

के उत्तर-पूर्व सीमांत पथ के मध्य व्यापारिक गतिविधि देखी है, जैसा कि भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के समय जाना जाता था। वस्तु विनिमय प्रथा के अंतर्गत, ऊपरी लोहित क्षेत्र के मिश्मियों और ज़ायुल जिले के तिब्बतियों के मध्य सीमा व्यापार में सदियों से दोनों पक्षों से माल का आदान-प्रदान होता रहा है। सीमावर्ती समुदायों की व्यापारिक प्रवृत्ति के पीछे आर्थिक दृढ़ संकल्प ही एकमात्र प्रेरक शक्ति नहीं थी। इस आदान-प्रदान अभ्यास में संस्कृति, चिकित्सा, विचार और सामाजिक दृष्टिकोण भी अंतर्निहित हैं। इस संवाद परंपरा और बौद्ध धर्म ने राजनीतिक और सामाजिक सौहार्द के लिए एक आकर्षक प्रकरण बनाया। सदियों से एक उत्पादक स्थान के रूप में सीमा 1962 में भारत-चीन युद्ध के कारण सहसा बाधित हो गई थी। चीन की विस्तारवादी और हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति ने सीमावर्ती समुदायों के मध्य उत्पादकता और संवादात्मक परिधि को निलंबित कर दिया है। यद्यपि, तिब्बत पर चीनी अधिकार और चीन द्वारा इस क्षेत्र में अपनाई गई जटिल भू-राजनीति के कारण पुनरुद्धार की आशा जटिल लगती है। इस भू-राजनीतिक अनिवार्यता को देखते हुए भारत की ओर से सुदृढ़ आधारभूत संरचना सुनिश्चित करने की तात्कालिकता बनी हुई है। 2014 के पश्चात से इस तात्कालिकता को गहराई से अनुभव किया गया है और कठोर आधारभूत संरचना पर ध्यान बढ़ाया गया है। सीमावर्ती गाँवों पर व्यापक ध्यान देने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य अंतरराज्यीय संपर्क पर व्यवस्थित रूप से कार्य किया गया है। सादिया, पांडु, धुबुरी और ढोला-सादिया सड़क पुल और बोगीबील रेलमार्ग पुल से जुड़े जल मार्ग संयोजन, और अरुणाचल प्रदेश में तेजू, ह्युलियांग, वालोंग और किबिथू सहित संपर्क को बड़े स्तर पर मानचित्रित किया गया है और अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत के संपर्क प्रतिमान की गहनता को व्यक्त करने के लिए इस दिशा में बनाया गया। मैकमोहन रेखा के साथ प्रगति पर चल रहा सीमांत राजमार्ग तवांग में मागो थिम्बू से चांगलांग में विजयनगर तक लगभग 2000 किमी की दूरी तय करता है, जो इस राजमार्ग का विस्तार बनता है। चीन द्वारा अपनाई जा रही भू-राजनीतिक जटिलता को जानते हुए यह न केवल सीमा क्षेत्र पर अत्यधिक आवश्यक ध्यान देता है, बल्कि यह सीमावर्ती समुदायों को संबंध और एकीकरण की भावना भी देता है। अत: विकास का आरंभ अंतिम गाँव के स्थान पर भारत के प्रथम गाँव से होता है। धारणा में यह परिवर्तन नरेंद्र मोदी का नीति प्रतिमान की विशेषता है। जो व्यापक विकास, एकीकरण और साझा सफलता में विश्वास करता है।

भारत-बांग्लादेश के बीच 'सीमायें जुड़ रही हैं, दिल जुड़ रहे हैं' : डॉकी

भारत और बांग्लादेश की मित्रता ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक, अर्थव्यवस्था तथा सौहार्दपूर्ण संबंधों पर आधारित है। भारत-बांग्लादेश संधि और संबंधों को जन्म देने वाली प्रेरणाएँ अन्य दक्षिण एशियाई साझेदारों की तुलना में भिन्न हैं। बांग्लादेश और भारत के विभाजन के दुख की कहानियाँ और संप्रभुता पर संस्मरण, टैगोर की सार्वभौमिक मानवता, विकास की जरूरतें, माइक्रोफाइनेंस पर क्रॉस-कंट्री परियोजनाएं, विकास और प्रगति समान हैं। दोनों देशों के बीच स्वाभाविक मित्रता, मेघालय के डॉकीशहर में प्रसिद्ध उमंगोट नदी और भूमि बंदरगाह पर ध्यान आकृष्ट करती है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच प्राकृतिक सीमा है।

डॉकी में रहने वाले खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ी जनजातियों से संबंधित हैं और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अन्य जनजातियों के समान नहीं हैं। उनकी उत्पत्ति और चुनौतियाँ दूसरों से भिन्न रहती हैं। डॉकी और उसके निकट ये समुदाय स्थानीय व्यापार, मछली पकड़ने और

पारिस्थितिक पर्यटन में शामिल हैं।

समुदाय अपना अधिकांश समय शांति में बिताते हैं और कभी-कभी संघर्ष गाँव के सामुदायिक जीवन और सीमा सुरक्षाकर्मियों के साथ स्थितिजन्य झड़पों का हिस्सा रहा है। मेघालय अक्सर पड़ोसी राज्य असम के साथ संघर्ष में फँसा रहता है और अक्सर सड़क और व्यापार ठप रहता है। बहुत समय से ग्रामीण समुदाय और असम-मेघालय के सीमावर्ती निवासी सुरक्षा और सबसे बढ़कर विकास और स्थिरता की मांग कर रहे हैं।

सिलहट के जाफलोंग में स्थित भारत और बांग्लादेश में पियांग-उम्नगोट के नाम से जानी जाने वाली सीमा पार नदी अपने प्राचीन साफ पानी, पर्यटन और व्यापार के अवसरों को प्रोत्साहित करने वाले प्राकृतिक परिवेश दोनों के लिए प्रसिद्ध है। डॉकी में नदी तटीय समुदाय स्थायी आजीविका में संलग्न होना चाहते हैं। नदी के इस क्षेत्र में पाए जाने वाले स्टील ब्रिज के पास 0.32 किमी की चेनेज पर स्थित डॉकी फेरी घाट एक प्राथमिक नदी व्यापार मार्ग के रूप में उभरा है। इसमें न केवल मछली पकड़ने बल्कि खुले नदी तट के बीच छोटे व्यापार भी नियमित हो गए हैं। जिसके कारण लोगों और व्यापारियों के बीच बातचीत का मुक्त प्रवाह स्थापित हुआ है। नदी विभाजन खुला है लेकिन नदियों पर दोनों देशों के बीच कोई स्पष्ट भौतिक सीमांकन नहीं है और केवल सुरक्षा द्वारा पकड़ी गई रस्सी ही बाड़ लगाने के उद्देश्य को पूरा करती है। डॉकी में अक्सर शांति रहती है। हालांकि कई बार स्थानीय लोगों और सीमा सुरक्षा बलों (बीएसएफ) के बीच संघर्ष भी होते रहे हैं। भारतीय पक्ष में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा अवैध प्रवासियों को रोकने में लगी हुई है।

हालांकि पिछले वर्ष भारत के मेघालय के डॉकी में बांग्लादेश और भारत के बीच 10वें भूमि बंदरगाह का उद्घाटन 4 मई 2023 को भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय द्वारा किया गया था। डॉकी भूमि बंदरगाह भारत के शिलांग से लगभग 84 किलोमीटर

डॉ. अन्ना नाथ गांगुली

एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक

दूर है। नया भूमि बंदरगाह व्यापार को बढ़ावा देने, दोनों देशों के बीच आसान यात्रा, साझेदारी और व्यापार के अवसरों को खोलने पर ध्यान केंद्रित करेगा। बंदरगाह में यात्री और कार्गो टर्मिनल भवन, गोदाम, कैंटीन, निर्यात ड्राइवरों के लिए शौचालय ब्लॉक और सीवेज उपचार संयंत्र सहित अधिक सुविधाएं होंगी। डॉकी लंबे समय से एक प्रमुख आकर्षण स्थल रहा है, जिसके कारण मेघालय में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा कई बांग्लादेशी दाऊकी-तमाबिल सीमा पार करके भारत आते रहे हैं।

उमियांग झील

चित्र में यहाँ भूमि की पट्टी उमियांग झील पर भारत और बांग्लादेश को विभाजित करती है। अचार और खाद्य

पदार्थों का व्यापार अक्सर होता रहता है। आस-पास के गाँव में रहने वाले सैकड़ों परिवार खासी लोगों की युद्ध उप-जनजाति से संबंधित हैं। जिनमें से ज्यादातर ईसाई धर्म से संबंधित हैं। लेकिन कई उप-समूह पारंपरिक पहाड़ी जनजातियों से संबंधित हैं। कई जनजातियों के पूर्वजों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में भाग लिया था।

भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा हाट स्थानीय विकास और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पाँच साल पहले बांग्लादेश की सीमा से लगे मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के भोलागंज और रिंग्कु में दो 'सीमा हाट' चालू किए गए थे। 2022 में यह घोषणा की गई थी कि मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में रिंग्कु और बांग्लादेश के सुनामगंज जिले के दुआरा बाजार में बागान बारी के बीच 16 नए सीमा हाट स्थापित किए जाएंगे। मेघालय के दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स में नालिकाता और बांग्लादेश के सुनामगंज जिले के ताहिरपुर में सैयदाबाद के बीच हाट के भी खुलने की उम्मीद थी। 2023 में यह पुष्टि की गई कि भारत और बांग्लादेश के बीच 8 सीमा हाट चालू थे। सीमा हाट का विचार अनोखा है। क्योंकि सीमावर्ती बाजारों और स्थानीय वस्तुओं को व्यापारी और आजीविका का स्रोत मिल जाता है। डॉकी के आसपास के अधिकांश हाट छह वर्षों से अधिक समय से भारतीय टमाटर (सोहबैंगन), केरोसिन, नमक, भारतीय बीरिस और गांजा, भारतीय साबुन, शैम्पू और कुछ दवाओं के व्यापार में शामिल हैं।

डॉकी मछली पकड़ने वालों का निवास स्थान है और मछली पकड़ने वाला समुदाय नियमित व्यापार और उपभोग में शामिल है। भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए यह विशाल कैटफ़िश पकड़ने के लिए मछली पकड़ने का एक प्रमुख स्थान है। प्रतीकात्मक आवरण और जनजातीय पोशाक पहने पुरुष और महिलाएं दोनों ही भारत और बांग्लादेश में लोकप्रिय स्थानीय मछलियों को पकड़ने के लिए पानी में विशाल जाल के साथ मछली पकड़ते और नाव चलाते हुए दिखाई देते हैं।

सीमा पार व्यापार और कुशल सीमा पार को बढ़ावा देने के लिए डॉकी में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) का निर्माण किया गया है। लेकिन आम लोगों के लिए डॉकी बांग्लादेश को कोयला, चूना पत्थर, कच्ची खाल, बोल्डर पत्थर, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक फर्नीचर, जियोटेक्सटाइल शीट, टिशू पेपर, कपड़े धोने का साबुन, पीवीसी दरवाजा और फायर क्ले ईंट जैसे प्रमुख निर्यात गंतव्य रहा है। यहां तक कि सीमा सुरक्षा कर्मी (बीएसएफ) भी नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम में शामिल हैं। कंप्यूटर, स्कूल के सामान, छत के पंखे, पानी के डिस्पेंसर, कूड़ेदान आदि प्रदान करते हैं और विभिन्न स्कूलों के छात्रों और ग्रामीणों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, धार्मिक और पर्यटन के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए डॉकी सीमा पार करना चुनौती बनी हुई है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल डॉकी में भारतीयों से ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वैध आईडी की जांच करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति देता है या अस्वीकार करता है और यदि यह उपलब्ध नहीं है तो चौकियों पर दोबारा प्रवेश करने से

रोकता है।

किसी कवि ने सीमा पार करने पर लिखा था कि 'हर किसी ने एक समय या किसी अन्य पर एक शाब्दिक या आलंकारिक सीमा पार की है। ये क्रॉसिंग हमें एक ऐसी जगह से ले जाती, जहाँ हम एक नई जगह पर घर जैसा महसूस करते हैं'। डॉकी मेघालय के केंद्र में स्थित है और हर दिन रूट ब्रिज की भूमि में साफ पानी के आसपास कहानियाँ बुनती है।

डॉकी में एक दिन

डॉ. सरिता शर्मा

शिक्षाविद, लेखक,
अनुवादक एवं संपादक

वर्ष 2020 में सुखद शरद ऋतु का वह एक दिन था, जब कोविड ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और उसे पंगु बना दिया था, उससे ठीक पहले मैंने डॉवकी का दौरा किया। डॉवकी मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जनपद में स्थित एक सुंदर नगर है। यह मेघालय की राजधानी शिलाँग से सड़क मार्ग द्वारा लगभग सत्तर किलोमीटर दूर है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा पर स्थित यह पहला गाँव है, और भारत-बांग्लादेश के बीच कुछ सीमांत सड़कों में से एक है। यह भारत से बांग्लादेश को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है।

सीमाएँ झरोखा हैं, यह मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था। डॉवकी सीमा चेकपोस्ट पर खड़े होकर मैं लोगों को बेपरवाही से चलते हुए, फेरीवालों को गुजरते हुए, कुछ को तस्वीरों के लिए 'पोज़' देते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अगर हाथों में बंदूकें लिए सेना के कुछ जवान न होते, जो कभी-कभार लोगों को तमाबिल की ओर बहुत दूर जाने से रोक रहे होते, तो मुझे कभी अंदाज नहीं होता कि मैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर खड़ा हूँ। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा बताने वाले (सीमांकन करने वाले) कुछ पत्थर के खंभों के अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ज्यादा कुछ नहीं था। मैं कोई बाड़ नहीं देख सका, कोई भारी बख्तरबंद कर्मी नहीं थे या कर्मियों में बहुत अधिक तनाव नहीं था। दरअसल, बीएसएफ कर्मी अक्सर इसे मित्रवत् सीमा के रूप में इस सीमा का संदर्भ देते हैं। उमंगोट नदी, जो एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, चेक पोस्ट से थोड़ी ही दूरी पर है। स्थानीय लोग तंग थे, क्योंकि घुसपैठिए अक्सर अंदर आने के लिए नदियों को पार कर जाते थे। मीलों तक फैली खुली सीमा की निगरानी करने के लिए सेना सदैव सतर्क दिखाई देती थी।

मेरे बेटे ने पूछा, 'हमें सीमाओं की आवश्यकता क्यों है? क्या पशु-पक्षियों को भी 'चेकिंग गेट' से गुजरना पड़ता है?' यह बात मुझे सोचने के लिए विवश कर गई। सीमाओं और सीमांतक्षेत्र को पहचानना, यह जानना कि क्या हमारा है और क्या नहीं, शायद मानव होने के प्राथमिक गुणों में से एक है।

पश्चिम जयंतिया हिल्स जनपद में भारत बांग्लादेश सीमा पर डॉवकी पहला गाँव है। इसे 'बांग्लादेश का प्रवेश द्वार' भी कहा जाता है। एक स्त्रातिजिक व्यापारिक स्थान होने के कारण यह लंबे समय से दोनों देशों के लिए व्यापारिक केंद्र के रूप में काम करता रहा है। बांग्लादेश को कोयला और चूना पत्थर के निर्यात के लिए मुख्य रूप से डॉवकी को जाना जाता है। यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच आयात-निर्यात और लेन-देन का एक प्रमुख केंद्र है। प्रमुख व्यापारिक लेन-देन के अतिरिक्त छोटे व्यापारी और फेरीवाले भी इस ओर व्यापार करने के लिए डॉवकी में सीमा पार करते हैं। यह व्यापारिक आदान-प्रदान का केंद्र है। दोनों देशों के लोगों के बीच सौहार्द यहाँ दिखता है। यहाँ सीमा पार करके आना-जाना आसान है, और मेरा मानना है, कि वैवाहिक संबध भी आसान हैं।

डॉवकी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उमंगोट नदी बहती है, जो 'क्रिस्टल क्लियर' नदी है, जो प्रतिवर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। नदी इतनी साफ है कि कोई बारह से तेरह फीट नीचे तक इसका तल देख सकता है। नदी पर तैरती नावें ऐसी लगती हैं, मानों काँच पर तैर रहीं हों। जीवित जड़ों से बना पुल एक अन्य प्रमुख आकर्षण है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, डॉकी का पहला गाँव एक मैत्रीपूर्ण सीमा के रूप में देखा जाता है। यह बांग्लादेश का प्रवेश द्वार है और यहीं से होकर भारत से बांग्लादेश के लिए बस मार्ग गुजरता है। हालाँकि कुछ स्थानीय लोग घुसपैठियों से तंग हैं, लेकिन अधिकतर सीमा क्षेत्र के आसपास रहने वाले दोनों देशों के लोगों के बीच सौहार्द और भाईचारे की भावना देखी जा सकती है। व्यापार में सुगमता और सरलता है। सीमांत लोगों का आपस में बहुत भरोसा और अपनापन भी है। यहाँ संभवतः ऐसे परिवार भी हैं, जो विवाह के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हालाँकि, मुझे इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन सीमा की सहज स्थिति को देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार को अपनी निर्धारित पद्धति से कार्य करने के लिए सीमाओं की आवश्यकता होती है। प्रत्येक देश की अपनी शासन-प्रणाली, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राष्ट्रीयता की अवधारणा होती है। हालाँकि, कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि सहज सीमाओं (सॉफ्ट बार्डर्स) की अपनी चुनौतियाँ और सीमाएँ होती है, फिर भी यह देखकर तसल्ली होती है कि सीमाओं का मतलब आवश्यक नहीं कि युद्ध जैसे क्षेत्र हों, युद्ध जैसी स्थितियाँ हों। यह अनुभूत किया जा सकता है, कि मानव को अधिक सहज और मैत्रीपूर्ण सीमाओं की आवश्यकता है, ताकि घृणा और विरोध की भावना को मिटाया जा सके। देशों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शैक्षणिक आदान-प्रदान, विशेषज्ञता की साझेदारी होनी चाहिए। मानवता की सच्ची भावना के प्रतीक के रूप में सीमाओं को सदैव आदान-प्रदान का साक्षी बनना चाहिए। ये (सीमाएँ) झड़पों और युद्ध की स्थिति को उकसाने वाले क्षेत्र नहीं होने चाहिए।

अमृतांशु राय

लेखक, ब्राडकॉस्ट पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।

प्रथम गाँव चंपई: मिजोरम का धान का कटोरा

चंपई मिजोरम का धान का कटोरा है। यह म्यांमार भारत सीमा के सबसे नजदीक पहली बड़ी बस्ती है। म्यांमार और भारत (मिज़ोरम) के बीच की सीमा एक खुली सीमा है और बिना किसी बाड़ के बनी हुई है। क्योंकि भारतीय मिज़ोस के म्यांमार के साथ गहरे संबंध हैं। लेकिन इसके ख़त्म होने की संभावना है। क्योंकि भारत ने खुली सीमा के कारण होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। मैंने इन भागों का दौरा किया है और सीमा पार कर म्यांमार की प्रसिद्ध रिह दिल झील तक म्यांमार की तरफ भी गया हूँ।

मिज़ोरम शब्द का अर्थ मिज़ोस का घर है। भारतीय और म्यांमार दोनों तरफ के मिज़ो लोग सीमा के दोनों ओर अपने घर को एकजुट करने की आकांक्षा रखते हैं, जिसे वे ज़ोरम कहते हैं। जिसका अर्थ है बड़ा घर। बड़ी पहचान की यह आकांक्षा उनके राजनीतिक संघर्ष के मूल में है और स्थानीय राजनीतिक आंदोलनों को जन्म देती है। यही कारण है कि राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री लालदुहावमा ने म्यांमार के साथ मिजोरम सीमा के भारतीय हिस्से में बाड़ नहीं लगाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक अभ्यावेदन दिया।

चंपई का एक इतिहास है जो मिजोरम के व्यापक ऐतिहासिक आख्यान के साथ जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक संदर्भ को समझने से शहर के विकास और क्षेत्र की सांस्कृतिक पच्चीकारी में इसकी भूमिका के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। मिजोरम का इतिहास प्रवासन और क्षेत्रीय परिवर्तनों से चिह्नित है। मिज़ो लोग, जो मूल रूप से म्यांमार में चिन पहाड़ियों में रहते थे, सदियों से वर्तमान मिजोरम में चले गए। म्यांमार के निकट होने के कारण चंपई ने ऐतिहासिक घटनाओं के उतार-चढ़ाव को देखा है, जिन्होंने मिज़ो समुदाय की नियति को आकार दिया है।

भारत-म्यांमार सीमा, जो 1,600 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है, दोनों देशों के लिए विभिन्न

सुरक्षा चिंताएँ प्रस्तुत करती हैं। खुली सीमा की प्रकृति, कठिन भूभाग और ऐतिहासिक सीमा पार बातचीत एक जटिल सुरक्षा वातावरण में योगदान करती है।

पूर्वोत्तर भारत के विद्रोही समूह शरण और समर्थन की तलाश में ऐतिहासिक रूप से म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं। घने जंगल और पहाड़ी इलाके विद्रोही गतिविधियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) और अन्य जैसे विद्रोही समूहों ने कई बार म्यांमार में शिविर और ठिकाने स्थापित किए हैं। जिससे यह दोनों देशों के लिए एक सुरक्षा चुनौती बन गया है।

भारत-म्यांमार की खुली सीमा-प्रकृति उग्रवादियों, तस्करों और अवैध प्रवासियों सहित लोगों को आसान आवाजाही की अनुमति देती है। इससे दोनों तरफ की सीमा नियंत्रण और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। सांस्कृतिक, पारिवारिक और आर्थिक कारणों से लोगों की आवाजाही ऐतिहासिक कथा का एक हिस्सा है। लेकिन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।

सीमावर्ती क्षेत्र नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के लिए एक जाना-माना मार्ग है। गोल्डन ट्राएंगल, वह क्षेत्र जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं मिलती हैं, अवैध नशीली दवाओं के उत्पादन का एक कुख्यात स्रोत है और भारतीय सीमा की निकटता नशीली दवाओं की तस्करी के बारे में चिंता पैदा करती है। हथियारों की तस्करी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिसमें अवैध हथियार खुली सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं। इससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा है।

सीमा पर महिलाओं और बच्चों की तस्करी सहित मानव तस्करी एक चिंता का विषय है। आपराधिक नेटवर्क अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए खुली सीमा का फायदा उठाते हैं और मानव तस्करी मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

चुनौतीपूर्ण भूभाग, घने जंगल और उचित बुनियादी ढांचे की कमी प्रभावी सीमा निगरानी को कठिन बनाती है। अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सड़क, सीमा चौकियों और निगरानी प्रणालियों, जैसे सीमा पर बुनियादी ढांचे की स्थापना और रखरखाव महत्वपूर्ण है। दोनों देश सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए सीमा पर बुनियादी ढांचे और समन्वय को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।

सीमा पर अनियमित आवाजाही और गतिविधियाँ पर्यावरणीय क्षरण में योगदान कर सकती हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकती हैं। लकड़ी की कटाई और वन्यजीव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियाँ ऐसी चिंताएँ हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इन सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के प्रयासों में भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त गश्त और राजनयिक संवाद शामिल हैं। दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता और अपनी-अपनी आबादी की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सीमा को सुरक्षित करने के महत्व को पहचानते हैं।

चंपई मिज़ोरम के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह शहर सुरम्य पहाड़ियों में बसा हुआ है, जो हरे-भरे हरियाली और मनोरम परिदृश्यों से घिरा हुआ है। चंपई की भौगोलिक स्थिति न केवल इसे आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती है बल्कि इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व में भी भूमिका निभाती है। शहर की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से निकटता ने इसके इतिहास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रभावित किया है। पहाड़ियों और घाटियों की विशेषता वाला परिदृश्य चंपई के आकर्षण को बढ़ाता है और स्थानीय परंपराओं और

प्रथाओं के विकास के लिए एक अद्वितीय अनुकूलन प्रदान करता है।

कुल मिलाकर मिजोरम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और चंपई भी इसका अपवाद नहीं है। मिज़ो लोग, जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में निवास करते हैं, अपने पारंपरिक नृत्यों, संगीत और त्योहारों के कारण एक अलग पहचान रखते हैं। चंपई मिज़ो संस्कृति के सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करता है, जो पीढ़ियों से चले आ रहे रीति-रिवाजों और परंपराओं को दर्शाता है। चंपई में समुदाय विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, त्यौहार और कार्यक्रम उनकी कलात्मक और सांस्कृतिक कौशल की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

मिज़ो संस्कृति का एक उल्लेखनीय पहलू चेरॉ है, जो एक पारंपरिक बांस नृत्य है। जीवंत मिज़ो धुनों के साथ बांस के डंडों की लयबद्ध खड़खड़ाहट एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य पैदा करती है। चंपई अक्सर मिज़ो विरासत के उत्सव में स्थानीय लोगों और आगंतुकों को एक साथ लाते हुए चेराव प्रदर्शन की मेजबानी करते हैं। यह शहर अपने पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है। चंपई में कुशल कारीगर उत्कृष्ट हाथ से बुने हुए वस्त्र और जटिल बांस शिल्प का उत्पादन करते हैं। ये उत्पाद स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के स्रोत के रूप में काम करते हैं। हाल के वर्षों में आर्थिक चालक के रूप में पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चंपई की प्राकृतिक सुंदरता, इसकी सांस्कृतिक समृद्धि के साथ मिलकर, प्रामाणिक अनुभव चाहने वाले आगंतुकों को आकर्षित करती है। इको-पर्यटन को बढ़ावा देना एक और पहलू है जो शहर के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता से मेल खाता है। क्षेत्र की जैव विविधता को प्रदर्शित करने और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल चंपई के सतत विकास में योगदान करती है।

जबकि चंपई कई पहलुओं में फलता-फूलता है, उसे कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक परिदृश्य पेश करते हुए इस क्षेत्र को कुछ कमजोरियों के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। कनेक्टिविटी के मुद्दे, विशेषकर मानसून के दौरान परिवहन और संचार के लिए चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से ढांचागत विकास के साथ इन चुनौतियों का समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार स्थानीय समुदायों के सहयोग से स्थायी समाधानों की दिशा में काम कर रही है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करते हैं।

मिजोरम और म्यांमार के बीच संबंध केवल स्थलीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। म्यांमार से होकर बहने वाली कलादान नदी, मिज़ोरम को बंगाल की खाड़ी तक पहुँचने के लिए एक संभावित समुद्री मार्ग प्रदान करती है। इस कनेक्टिविटी में क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को बदलने, नए व्यापार मार्ग और अवसर खोलने की क्षमता है। कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी पहल का उद्देश्य मिजोरम और म्यांमार में सिटवे बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना, व्यापार और आर्थिक विकास में वृद्धि के रास्ते खोलना है। सीमा से लगे कस्बे, जैसे मिजोरम में चम्फाई और म्यांमार में फलम व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं।

डॉ. ज़ोकुशेयी राखो

पेक सरकारी कॉलेज, पेक,
नागालैंड में सहायक प्रोफ़ेसर

नागा पहाड़ियों में पहला आईएनए प्रशासित गाँव

सुभाष चंद्र बोस 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में पहुँचे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) को पुनर्जीवित किया गया। बोस और उनकी INA जापानी संगठन के साथ मिलकर भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के सपने में लग गए। 7 मार्च, 1944 को टोक्यो रेडियो ने सूचित किया कि भारत पर हमला जापानी 15वीं सेना द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कोड नाम यू-गो ऑपरेशन था। जिसकी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल रेन्या मुतागुची द्वारा की गई थी। जिसमें तीन डिवीजन्स थीं; 15वीं, 31वीं और 33वीं। प्रत्येक में 15,000 सैनिक थे।

नागा पहाड़ियों के रास्ते पर आगे बढ़ रही जापानी 31वीं डिवीजन, जिसका कमांड लेफ्टिनेंट जनरल कोटुकु सातो द्वारा किया गया था, इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के योद्धाओं के समूह भी उनके साथ आगे बढ़ रहे थे, अपनी ऐतिहासिक मार्च "दिल्ली की ओर" पर। जापानी सेनापतियों ने INA को कोहिमा की ओर अग्रसर करने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण प्रदान किया, उन्हें निर्देश दिए गए कि इम्फाल के गिरने के बाद "तेजी से आगे बढ़ें और ब्रह्मपुत्र को पार कर बंगाल के दिल में पहुंचें।"

रुजाझो गाँव का मनोहारी दृश्य

बर्मा से नागा पहाड़ियों तक के सभी ब्रिटिश

रुजाझो गाँव का मनोहारी दृश्य

(बाएं से दाएं) डॉ. पुरोबी राय (ICHR के सदस्य), तथागत रॉय (त्रिपुरा के राज्यपाल), पी.बी. आचार्य (नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल), संसाधन वक्ता और अन्य लोग दो-दिवसीय सेमिनार के दौरान Ruzazho गाँव में, जो नागा पहाड़ियों में पहला INA प्रशासित गाँव था।

आउटपोस्ट पार कर, भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) अप्रैल 1944 के पहले हिस्से में रुजाझो गाँव पहुँची। बोस की रिपोर्ट में बताया गया था कि वह कोहिमा से 75 किलोमीटर दूर स्थित रुजाझो गाँव में शिविर कर रहे थे। जहां एक दृष्टिगत साक्षी पोस्वुई स्वुरो (2017 में 96 वर्ष की आयु में मृत्यु) को बोस के लिए अनुवादक / डोबाशी के रूप में काम किया करते थे। जब बोस गाँव पहुंचे तो उन्होंने लोगों के साथ एक बैठक बुलवाई और यहाँ उन्होंने पहली आज़ाद हिंद प्रशासन की व्यवस्था की। जब उन्होंने 10 गाँव बुरा या गाँव के पुराने नेता नियुक्त किए और प्रशासनिक कार्यों के लिए डोबाशी / अनुवादकों को नियुक्त किया।

"असम का राजनीतिक इतिहास, भाग III, असम सरकार, दिसपुर, १९८०। रुजाझो के पोस्वुई स्वुरो के साक्षात्कार, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति और इस गाँव के पहले शिक्षित व्यक्ति में से एक थे, तारीख: २६ अप्रैल २०१७।"

गाँव वालों के अनुसार बोस एक अच्छे रूपवाले हैंडसम मनुष्य थे। जिनका अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व था। हरे रंग की वर्दी पहने हुए जिनके लम्बे बूट्स और कमरबंध में एक तलवार थी। वे अक्सर मजबूत सिख सैनिकों द्वारा घेरे या अनुरक्षित किए जाते थे। बोस लोगों से बात करते थे कि भारत को स्वतंत्र होते ही वे गाँव में पीने का पानी, सड़कें, स्कूल, अस्पताल आदि बनवाएंगे। और इसलिए उन्होंने लोगों से आईएनए का समर्थन करने के लिए कहा। प्रारंभ में बोस गाँव के पुजारी के घर में रहे जहां एक मजेदार घटना घटी कि एक सुबह जब वे जागे, तो पास में बांधे गए आईएनए के घोड़े ने उनके घर के छत का आधा भाग खा लिया था। लेकिन गाँव वाले गुस्से के बजाय हंसी में फूट पड़े। क्योंकि यह दृश्य अब काफी दिलचस्प हो गया था। बाद में उन्होंने गाँव के ऊपरी पहाड़ी पर शिविर स्थापित किया। एक और घटना भी हुई कि एक दिन जब बोस लोगों के साथ बैठक में बोल रहे थे, तो पीछे महिलाओं की गुदगुदाहट हो रही थी। जब बोस ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि यदि बोस जैसे एक हैंडसम आदमी की युद्ध में मौत हो जाए, तो यह बेइमानी होगी और पुरुषों ने मज़ाक किया कि

नागालैंड के रुजाझो गाँव में सुभाष चंद्र बोस की याद में एक प्लाक रखा गया

क्या वे बोस की आकर्षण में आ गईं हैं।

स्थानीय प्रतिनिधि विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए मैनपावर को जुटाते थे। जैसे राशन का संग्रह, मार्गदर्शन आदि। पोस्वुई स्वुरो के अनुसार जब वे आईएनए-जापानी कॉलम को रुजाझो से बहुत दूर स्थित साटाखा ले जा रहे थे, तब डुझालामी गाँव में ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। जहां शेयेपु गाँव के एक युवा मार्गदर्शक किहोये सेमा के साथ कुछ आईएनए / जापानी मर गए। बोस इस गाँव में 9 दिनों तक रुके जहां उनकी यादें आज भी गाँव की लोक कला और कथाओं में अमर हैं। यहाँ पर पहली प्रशासनिक यांत्रिकियाँ स्थापित की गई थीं। 2017 के 25 अप्रैल को तब के नागालैंड गवर्नर पी.बी. आचार्य और त्रिपुरा के गवर्नर तथागत रॉय ने नागा पहाड़ियों में पहले आईएनए प्रशासित गाँव के रूप में इस गाँव को समर्पित किया। म्यांमार से कोहिमा की ओर जाने वाले कई गाँवों में चेसेजू, थेनिजू, किक्रुमा आदि जैसी गाँवों में बोस के बारे में समान कहानियाँ हैं। कोहिमा से 10 किमी दूर किग्वेमा गाँव में बोस की बताई गई यह कहानी है कि बोस कोहिमा के युद्ध के दौरान इस गाँव में भी रुके थे। जहां विकेतु किसो (2017 में 94 वर्ष की उम्र में मृत्यु) ने कहा कि उन्होंने बोस के लिए अनुवादक के रूप में सेवा की। जहां से आईएनए-जापानी गुजरे, वहाँ स्थानीय लोगों के मौखिक इतिहास में समान कहानियाँ दर्ज हैं।

आईएनए की सबसे कठिनाई का चरण कोहिमा पर पहुँचते समय था। राशन और दवा पूरी तरह से खत्म हो गए थे और कोहिमा में जापानी जैसी ही हालत थी और इस वापसी पर भारी नुकसान हुए जहाँ सैनिक शिकायत करते थे कि जापानी द्वारा पोर्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाने का। इस वापसी के संदर्भ में शाह नवाज़ खान ने लिखा, "कोहिमा से यह वापसी शायद दुनिया की किसी भी सेना के लिए सबसे कठिन वापसी में से एक थी। जोरदार बारिश ने सभी रास्तों को धो डाला था, मनुष्य द्वारा बनाए गए ताजे रास्ते जल्द ही लगभग घुटनों तक रह गए। लोग चार दिनों के लिए घोड़ों के शवों को खा रहे थे, थकान, भूखमरी, बीमारी आदि के कारण रास्ते के दोनों ओर जापानी और भारतीय सैनिकों की मौत के शव लेटे थे।" आईएनए की सटीक संगठन और इसकी निश्चित सैन्य शक्ति के बारे में नहीं जाना जाता है। क्योंकि 1945 में रंगून कोमनवेल्थ फोर्सेज़ द्वारा फिर से जीत लिया गया था। इससे पहले इसके रिकॉर्ड आज़ाद हिंद सरकार द्वारा नष्ट किए गए थे।दुनिया या देश के शेष भाग से दूर, नागा हिल्स में द्वितीय विश्व युद्ध की एक भयानक घटना के रूप में 1944 में कोहिमा के युद्ध के रूप में एक तीव्र घटना थी। इस युद्ध को ब्रिटिश सेना के सभी इतिहास में 'सबसे महान युद्ध' के रूप में वोट किया गया है। दुनिया के एक ऐसे क्षेत्र में लड़ा गया, जो अत्यंत अनुकूलता रहित था। इस युद्ध ने मनुष्य और संसाधन के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई। जिसमें 1942 में बर्मा से भारत की वापसी के दौरान 80,000 शरणार्थियों और 13,000 ब्रिटिश सेना की मौत, इम्फाल और कोहिमा के युद्ध के दौरान 45,000 जापानी और 16,700 ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों की मौत शामिल है और भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) और नागाओं की गिनती नहीं की गई है। उत्तर पूर्व भारत की समुद्र-सीमावर्ती क्षेत्रों की समुदायों को युद्ध में खिचड़ी दी गई थी, जहां उन्होंने पोर्टर्स, अनुवादक, मार्गदर्शक, सैनिक आदि के रूप में दोनों पक्षों के साथ भाग लिया, और बहुत से सैनिक मर भी गए। जिन लोगों ने ब्रिटिश आर्मी के साथ सेवा की थी, उन्हें किसी हद तक सफलता प्राप्त हुई, वहीं जो आईएनए-जापानी के साथ सेवा करते थे, उन्हें छोड़ दिया और भुला दिया गया था।

उत्तराखंड में चीन सीमा से प्रवासन-चुनौतियाँ एवं समाधान

डॉ. संजय शर्मा

पाँडिचेरी विश्वविद्यालय, पद्दुचेरी में
सह - प्राध्यापक

दीपक सिंह धपोला

पीएचडी स्कॉलर पाँडिचेरी
विश्वविद्यालय, पद्दुचेरी

उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों से प्रवासन (स्थलांतर):

उत्तराखंड उत्तर में चीन और पूर्व में नेपाल के साथ 350 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तराखंड प्रवास आयोग के अनुसार 2008-2018 तक, 1,18,981 लोगों के स्थायी प्रवास के कारण उत्तराखंड में 3,946 ग्राम पंचायतें (वीपी) निर्जन हो गईं। चीन की सीमा से लगे तीन जिलों, अर्थात् उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में 868 वीपी निर्वासित हो गए और 26,899 लोग स्थायी रूप से प्रवासन कर गए। ये तीन जिले कुल निर्जन वीपी का 22% और राज्य से कुल स्थायी प्रवास का 22.6% बनाते हैं। चमोली छह जिलों से घिरा हुआ है और तिब्बत, चीन के साथ उत्तरी सीमा साझा करता है। यह अकेले 2008-2018 की अवधि के दौरान कुल वंचित ग्राम पंचायत का 9.45 प्रतिशत और राज्य से कुल स्थायी प्रवासन का 12 प्रतिशत है।

प्रवासन के कारण

उत्तराखंड में प्रवासन की घटना नई नहीं है। 11वीं शताब्दी से पहले पहाड़ी क्षेत्रों में संभवतः मुख्य रूप से खानाबदोश चरवाहे समुदाय के लोग रहते थे। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ (ग्रामीण विकास और प्रवासन रोकथाम आयोग, एन.डी.)। वर्तमान समय में इस प्रवासन प्रवृत्ति ने गति पकड़ ली है और प्रवासन का मुख्य कारण रोजगार, शिक्षा सुविधाओं और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी है।

मानव-पशु संघर्ष और फसल क्षति गाँवों के प्रवास को प्रेरित करने वाले अतिरिक्त कारक हैं। बंदर और जंगली सूअर फसलों को नष्ट कर देते हैं। जिससे कृषि पर निर्भर 47.2 प्रतिशत ग्राम पंचायतें हतोत्साहित हो जाती हैं। चमोली जिले में बाहरी प्रवासियों में युवा श्रमिकों की संख्या अधिक है।।

सीमावर्ती जिलों में गाँव जनसंख्या का सामरिक महत्व

जोखिम के स्वीकार्य स्तर के भीतर व्यापक उद्देश्यों, अवधारणाओं और संसाधन आवंटन को निर्धारित करने के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण को नियोजित करके, एक रणनीति का लक्ष्य, स्थिति को मौका या दूसरों के नियंत्रण में छोड़ने की तुलना में अधिक अनुकूल भविष्य के परिणाम उत्पन्न करना है (यार्गर, 2006, पी। 5). एक सीमा के पास आबादी का होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि भूगोल, भूभाग और जलवायु भी निवास स्थान को प्रभावित करते हैं। हालाँकि, कुछ मामलों में, जैसे कि भारत-चीन सीमा, सीमा के पास मानव बस्तियाँ सीमा को लागू करने और नियंत्रित करने, अवैध घुसपैठ को रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपयोगी होती हैं। स्थानीय लोग सीमा सुरक्षा बलों को जानकारी और सहायता प्रदान कर सकते हैं। तस्करों, अवैध अप्रवासियों और अतिक्रमणकारियों को रोक सकते हैं और रक्षा बलों की आंख और कान के रूप में कार्य कर सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में प्राकृतिक रूप से ढलने के कारण स्थानीय लोगों को सेना द्वारा कुली के रूप में नियुक्त किया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने रेजांग ला की लड़ाई (1962 भारत-चीन युद्ध) और 1999 के कारगिल युद्ध (रोशांगर, 2019; वांगचुक, 2020; यादव, 2021) के दौरान सेना को महत्वपूर्ण जानकारी और रसद सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस), जनरल विपिन रावत ने 2021 में उल्लेख किया था कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से प्रवासन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनुपयुक्त था और रिवर्स माइग्रेशन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है (द इंडियन एक्सप्रेस, 2021)।

सीमावर्ती जिलों के लिए भारत की नीतियां

फरवरी 2017 में, भारत सरकार के उप सचिव ने 17 सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिवों को 2015 के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) दिशानिर्देशों के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉडल गांव विकसित करने के बारे में लिखा था। सीमा पर आबादी का कम होना, कनेक्टिविटी की कमी, खाद्य सुरक्षा, बिजली आपूर्ति, दूरसंचार कनेक्टिविटी, नागरिक बुनियादी ढांचा, स्थायी आजीविका और रोजगार सृजन। एक आदर्श गाँव, उस गाँव और पड़ोसी क्षेत्रों में रहने वाले सभी व्यक्तियों को आर्थिक अवसर और रोजगार के विकल्प प्रदान करेगा। उत्तराखंड सरकार ने चीन और नेपाल की सीमा से लगे 11 ब्लॉकों, चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में लगभग 100 गांवों को मॉडल गाँवों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति घाटी में जाने के लिए इनर लाइन परमिट को हटा दिया गया है। बाह्य-प्रवासन और अविकसितता को संबोधित करने के लिए भारत ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी),

और वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) के माध्यम से अपनी सीमा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाई है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

गृह मंत्रालय के तहत सीमा प्रबंधन विभाग, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) लागू करता है। केंद्र सरकार द्वारा 1986-87 की अवधि के दौरान शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे में अंतराल को कम करके और राज्य योजना निधि के साथ अतिरिक्त वित्त पोषण के माध्यम से सुरक्षा बढ़ाकर सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है। बीएडीपी को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 117 सीमावर्ती जिलों के 457 सीमावर्ती ब्लॉकों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पहली बस्ती से 0-10 किमी के भीतर स्थित बस्तियों में लागू किया जाता है (बीएडीपी-) एमएचए, एन.डी.)। शुरुआत में यह एक स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वाहन के रूप में कार्य करता था। लेकिन 2020 के बाद के दिशानिर्देशों ने इसे एक व्यापक विकास कार्यक्रम (भारत सरकार, 2020) में बदल दिया। इसमें उत्तराखंड के 5 जिलों के 9 ब्लॉक शामिल हैं। जिनमें चीन की सीमा से लगे चमोली जिले का जोशीमठ ब्लॉक भी शामिल है।

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी)

अपने 2022-23 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नए वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) की घोषणा की। जिसमें गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करना और आजीविका उत्पादन का समर्थन करना शामिल होगा। (वित्त, 2022, पृष्ठ 10)। वीवीपी को फरवरी 2023 में मंजूरी दी गई थी और इसमें तिब्बत, चीन की सीमा से लगे 4 राज्यों और 01 केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों के 46 सीमावर्ती ब्लॉकों के 2967 गांव शामिल हैं। इन गांवों में से 662 को कवरेज के लिए प्राथमिकता के रूप में नामित किया गया है। जिसमें उत्तराखंड के 51 गांव भी शामिल हैं (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2023)।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)

बीआरओ का गठन मई 1960 में भारत के उत्तर और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए सीमा सड़क विकास बोर्ड के रूप में किया गया था। प्रारंभ में, प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में और रक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। बाद में इसे रक्षा मंत्रालय के तहत एक विभाग में बदल दिया गया, जिसमें गृह मंत्री बीआरओ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे।

संगठन के पास भारत को कवर करने वाली रणनीतिक महत्व की 18 परियोजनाएं हैं और भूटान और ताजिकिस्तान जैसे मित्र देशों में इसकी उपस्थिति है। पिछले छह दशकों में बीआरओ ने 60,000 किलोमीटर लंबी सड़कों, 693 पुलों और 19 हवाई क्षेत्रों का निर्माण किया है। वर्तमान में यह 6,000 किलोमीटर लंबी सड़कों, 257 पुलों, दो हवाई क्षेत्रों और चार सुरंगों (बीआरओ, 2021) के निर्माण में शामिल है।

सिफारिशें

उद्यमिता, कौशल विकास और वित्तीय प्रोत्साहन को बढ़ावा देने से स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

शिक्षा, कनेक्टिविटी, बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और दूरसंचार नेटवर्क जैसी ग्रामीण विकास योजनाओं में निवेश करने से जीवन की गुणवत्ता बढ़ सकती है और ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों से प्रवासन कम हो सकता है। सीमावर्ती जिलों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और जश्न मनाना पर्यटन और आर्थिक अवसरों को आकर्षित कर सकता है।

प्रथम गाँव मिलाम के लाल: महान अन्वेषक पंडित नैन सिंह रावत

भारत माता का ऐसा लाल जिसने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया।

19वीं शताब्दी के महान अन्वेषक पंडित नैन सिंह रावत ने भारत माता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अपनी जान को जोखिम में डालकर पंडित नैन सिंह रावत ने तिब्बत का सर्वे कर दुनिया को तिब्बत के बारे में जानने का अवसर दिया। पंडित नैन सिंह रावत के अन्वेषण तक तिब्बत के बारे में कोई भी बाहर वाला किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं रखता था। 21 अक्टूबर 1830 को पैदा हुए पंडित रावत ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। भारत सरकार ने पंडित के नाम पर डांक टिकट जारी कर उन्हें सम्मान दिया। इनके अन्वेषण की ख्याति को देखते हुए इन्हें "द पंडित" के नाम से संबोधित किया गया। परतंत्र भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे, जिन्हें भू- वैज्ञानिक कार्य के लिए रॉयल ज्योग्रेफिकल सोसाइटी द्वारा उन्हें प्रथम विक्टोरिया पदक से विभूषित भी किया गया।

विकासखंड मुनस्यारी के ग्राम पंचायत बसंतकोट के भटकूड़ा (मिलाम) गांव में 21 अक्टूबर 1830 को पंडित नैन सिंह रावत का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम लाटा था। पंडित नैन सिंह रावत के चचेरे भाई मान सिंह रावत ने भी इनके साथ अन्वेषण का कार्य किया। यूरोपीय जगत को तिब्बत में प्रवेश प्रतिबंधित होने के कारण मार्च 1865 को दोनों पंडित बंधुओ को नेपाल होते हुए लहासा के सर्वेक्षण हेतु भेजा गया। पंडित के चचेरे भाई मान सिंह रावत को मध्य में ही अपनी यात्रा स्थगित कर स्वदेश लौटना पड़ा, लेकिन पंडित नैन सिंह रावत ने एक लद्दाखी की वेश में दावा नमग्यल के नाम से नौकर बनकर तिब्बत में प्रवेश करने पर सफल हो गया।

पंडित नैन सिंह रावत ने अपनी इस यात्रा द्वारा काठमांडू-

ल्हास- मानसरोवर तक की 1200 मील लंबी दूरी का सर्वेक्षण तथा 21 स्थानों पर अक्षांश और 33 स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात कर विश्व के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। साथ ही उन क्षेत्रों की रोचक तथा ज्ञानवर्धक वर्णन अपनी डायरी में अंकित किया। संपूर्ण तथ्यों का सारांश कर्नल मान्टोगोमरी द्वारा सोसाइटी के जनरल में 38 वें खंड में किया गया है। इनकी इस महान यात्रा से प्राप्त उपलब्धियां के उपलक्ष में 1868 में सोसाइटी ने उन्हें एक स्वर्ण घड़ी घड़ी प्रदान की।

संकलनकर्ता-
जगत मर्तोलिया
मुनस्यारी

थारु संस्कृति का केंद्र : प्रथम गाँव जिगना

अमृतांशु राय

ब्राडकॉस्ट पत्रकार एवं स्तंभकार

जब कोई जिगना गांव में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले आप आवास की शैली में बदलाव देखते हैं। इस छोटे से गाँव के अधिकांश आवासों में डबल छतरी प्रकार के निर्माण की नेपाल शैली का स्थापत्य प्रभाव है। जो डबल स्टोरी है और सभी लकड़ी से बने हैं। घर के अंदर प्रवेश करने पर आप एक हॉल में प्रवेश करते हैं जो पारिवारिक क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। जिसमें खाने की जगह, खाना पकाने का क्षेत्र, आग का स्थान और दिन के समय करने की अन्य गतिविधियां शामिल हैं। इसमें एक लकड़ी की सीढ़ी भी है जो पहली मंजिल तक जाती है जो एक छत की तरह है। यह वह जगह है जिसका उपयोग रात में सोने के लिए किया जाता है। पूरी जगह सिर्फ लकड़ी और मिट्टी की है, मामूली और बहुत साफ-सुथरी।

जिगना भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ एक गांव है। यह बिहार के पश्चिम चम्पारण जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे दर्जनों पहले गांवों में से एक है। इस गांव तक पहुंचने के लिए नरकटियागंज पहुंचना पड़ता है जो निकटतम रेलवे स्टेशन है। नरकटियागंज से जिगना करीब 60 किमी दूर है। कुछ ही समय पहले ऐसा समय था जब यहां सड़क संपर्क, बिजली या सरकारी सहायता नहीं थी। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। गांव में प्रमुख जल निकासी व्यवस्था, गांव के अंदर कंक्रीट की सड़कें, पानी की आपूर्ति, बिजली और यहां तक कि एक प्राथमिक शिक्षा स्कूल भी है, अच्छी कनेक्टिविटी के साथ।

यह गांव वाल्मिकी राष्ट्रीय उद्यान के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। यह गांव पार्क से तीन तरफ से घिरा हुआ है और केवल एक तरफ कृषि योग्य भूमि है। गाँव में

ख़रीफ़ में धान और रबी सीज़न में गेहूँ उगाया जाता है। हाल ही में कुछ किसानों ने नकद पैदावार के रूप में गन्ना उगाना शुरू कर दिया है। यह गांव निजी भूमि पर बांस के सबसे बड़े बागान के लिए स्थानीय रूप से लोकप्रिय है।

चूँकि यह हिमालय की तलहटी में स्थित है इसलिए मानसून और मिट्टी का कटाव गाँव के लिए एक निरंतर चुनौती है। इसके अलावा जानवरों द्वारा फसल को नष्ट करना एक निरंतर समस्या है। जब आप उनके खेतों का दौरा करेंगे तो आपको परिदृश्य में छोटे-छोटे मचान दिखेंगे। ये मचान किसानों को जानवरों द्वारा उनकी फसलों को नष्ट करने से बचाने के लिए सुरक्षा चौकी के रूप में काम करते हैं। हाल ही में ग्रामीणों ने सस्ते तरीके से बैटरी से चलने वाले ध्वनि उपकरण तैयार किए हैं, जिन्हें छूते ही वो बजने लगते हैं। या तो भजन बजने लगता है या फिर कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगती है। कुछ दिवाली की रोशनी की तरह जगमगाते हैं।

ग्रामीण थारू जनजाति के हैं और सनातान धर्म की जीवनशैली का पालन करते हैं। यह एक मातृसत्तात्मक समाज है जहाँ परिवार की मुखिया एक महिला होती है। यह महिलाएँ ही हैं जो खेती करती हैं और वे सभी भूमिकाएँ निभाती हैं जो आम तौर पर पुरुषों द्वारा पूरी की जाती हैं। पुरुषों ने अब खेतों में काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ समय पहले ही वे खाना पकाने, सफाई और बच्चों की देखभाल और ऐसे घरेलू कामों में खुश थे। सीमा पार नेपाल में उनके बहुत करीबी रिश्ते हैं। एक समय उनकी आजीविका रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नेपाली कस्बों पर निर्भर थी। चाहे अपनी कृषि उपज बेचनी हो या किराने का सामान खरीदना हो, नेपाल में निकटवर्ती गाँव ही जाने का स्थान था। अब ग्रामीण भारत में विकास के कारण वे नेपाल पर इतने निर्भर नहीं हैं। कई परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी नेपाल के गांवों में की है, और नेपाल से भी कई बेटियाँ, बहु बनकर भारत आयी हैं।

थारू जनजातियों के गांव तेजी से बदल रहे हैं, सरकारी योजनाओं के तहत अधिकांश नेपाली प्रभाव वाले लकड़ी के घरों को आधुनिक कंक्रीट के घरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। थारुओं का अपना थारू महासंघ है जिस पर समुदाय के बुजुर्गों को गर्व है। थारुओं का नया लक्ष्य थारू आईएएस और आईपीएस अधिकारी तैयार करना है.

1980 के दशक में परिदृश्य बदलना शुरू हुआ जब शस्त्र सेना बल [एसएसबी] के नाम का सीमा सुरक्षा केंद्रीय बल बनाया गया और उसे भारत और नेपाल के बीच बिना बाधा वाली, मैत्रीपूर्ण सीमा की सुरक्षा और प्रबंधन सौंपा गया। उन्हें नेपाल जाने से कोई नहीं रोकता लेकिन जाने और वापस आने पर उनकी गतिविधि दर्ज की जाती है और उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। यह रुकावट तब तक चिड़चिड़ाहट का कारण बनी रही जब तक यह एक आदर्श नहीं बन गई और लोगों ने नई व्यवस्था को अपना नहीं लिया। साथ ही पास के एसएसबी शिविर को अब इन गांवों के समाज में एकीकृत किया जा रहा है। विशेष रूप से सीमा जागरण मंच बिहार द्वारा रक्षा बंधन के दिन स्थानीय गांव की लड़कियों द्वारा एसएसबी जवानों की कलाई पर राखी बांधने के अभियान के कारण।

ग्रामीण अपने भारतीय मूल के प्रति सचेत हैं, राष्ट्रवादी हैं और कई लोग एसएसबी के लगातार संपर्क में हैं और अगर उन्हें कुछ संदेह होता है तो तुरंत उन्हें सूचित करते हैं। हाल ही में ग्रामीण खुले तौर पर नेपाल की ओर से भारतीय गांवों में घुसपैठ करने वाले अल्पसंख्यक

समुदाय की गतिविधियों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। वे सीमा पर नेपाल में मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित होने वाले बड़े आयोजनों को लेकर भी चिंतित हैं, जो बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमानों को आकर्षित करते हैं।

थारूओं की उत्पत्ति के बारे में ओपन एआई का कहना है कि थारू लोगों की उत्पत्ति निश्चित रूप से स्थापित नहीं है और उनकी ऐतिहासिक जड़ों के बारे में विभिन्न सिद्धांत हैं। थारू समुदाय तराई क्षेत्र का मूल निवासी है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों सहित नेपाल और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। थारू लोगों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांतों और दृष्टिकोणों में कहा गया है कि थारू लोग तराई क्षेत्र के मूल निवासी होने का दावा करते हैं। उनका दावा है कि उनके पूर्वज पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। उनकी एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा और जीवनशैली है जो स्थानीय परिवेश से निकटता से जुड़ी हुई है। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि थारू लोग समय के साथ तराई क्षेत्र में चले गए होंगे। प्रवासन के कारणों में ऐतिहासिक घटनाएँ, पर्यावरणीय कारक या आर्थिक अवसर शामिल हो सकते हैं। भाषाई अध्ययन से पता चलता है कि थारू भाषा इंडो-आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। हालाँकि, विभिन्न उपसमूहों द्वारा बोली जाने वाली थारू की विभिन्न बोलियाँ हैं और थारू लोगों के बीच भाषाई विविधता एक जटिल इतिहास का सुझाव देती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने थारूओं को जनजातियों की सूची में शामिल किया। तब से उनके लिए अवसरों की दुनिया खुल गई। कई परिवारों में अब डॉक्टर और इंजीनियर हैं। कई और परिवारों ने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां खोली हैं और अब राजनीति की मुख्य धारा में हैं। हाल ही में इस समुदाय की लड़कियों को कौशल भारत योजना के तहत गुड़गांव में मोबाइल विनिर्माण कंपनियों में शामिल किया गया था।

इसके अलावा थारू जनजातियों के गांव तेजी से बदल रहे हैं। सरकारी योजनाओं के तहत अधिकांश नेपाली प्रभाव वाले लकड़ी के घरों को आधुनिक कंक्रीट के घरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। थारू समुदाय में एक पुरानी व्यवस्था है जहां लोग अपने गांव के बुजुर्ग को गुमास्ता के रूप में चुनते हैं। यह सामुदायिक चयन है और चुने जाने वाले मुखियाओं से अलग है। गुमास्ता की संस्था कमजोर हो सकती है लेकिन जहां भी वे मौजूद हैं, गांव के मुखिया की स्थिति गुमास्ता के बाद दूसरे स्थान पर है। थारूओं का बहुत अच्छा नेटवर्क है और उनका अपना थारू महासंघ है जिस पर समुदाय के बुजुर्गों को गर्व है। थारूओं का नया लक्ष्य थारू आईएएस और आईपीएस अधिकारी तैयार करना है।

सुरक्षित सीमा के लिए तटीय आबादी का मजबूत होना आवश्यक

शोधकर्ताओं के अनुसार किसी राष्ट्र का उत्थान और पतन प्रत्येक नागरिक के राष्ट्र निर्माण में भागीदारी पर निर्भर करता है । पाकिस्तान का भारत के खिलाफ छद्म युद्ध तथा उत्तर पूर्व में चीन की भारत विरोधी गतिविधियां से खतरा और बढ़ गया है और यह खतरा अब सिर्फ जमीनी सीमा तक ही सीमित नहीं रह गया है । देश की सशस्त्र सेना के द्वारा जमीनी सीमाओं पर समस्याओं से निपटने में पहले से कम समय लग रहा है। लेकिन यह असंभव है कि देश की सशस्त्र सेनाएं हर जगह हर परिस्थिति से निपटने में संभव हो पाए।

इस छद्म युद्ध का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए पूरे समाज को लड़ाई में शामिल होना होगा। सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसलिए नागरिक बल (टीए) के रूप में सशस्त्र बलों और समाज के बीच मौजूदा संबंध को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रादेशिक सेना को कुछ तटीय

ब्रिगेडियर (रि) हेमंत महाजन

YSM

आर्मी वॉर कॉलेज में हायर कमांड विंग के संकाय में डीएस के रूप में तीन साल तक विशिष्टता के साथ सेवा व लेखन में रूचि

सुरक्षा कर्तव्य सौंपे जाने चाहिए जिससे उन्हें खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी और सुरक्षा अभियानों में अधिक जिम्मेदारी संभालने की अनुमति मिल सके।

सदियों से भारत के मछुआरों ने तट के संरक्षक के रूप में कार्य किया है। जो हमारे जल में घुसपैठ करने

वाले विदेशी जहाजों सहित घुसपैठियों की पहचान करते हैं और उन्हें रोकते हैं। 26/11 की घटनाओं के बाद, सुरक्षा एजेंसियों ने विभिन्न लैंडिंग स्टेशनों पर स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय के साथ बातचीत शुरू की, जिसका उद्देश्य उनकी जागरूकता बढ़ाना और तटीय सुरक्षा को मजबूत करना था।

तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक हेल्पलाइन की स्थापना

2013 में बंदरगाह क्षेत्र के लिए 1093 नंबर के साथ एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू की गई थी। पुलिस नियंत्रण कक्ष से जुड़ी यह टोल-फ्री हेल्पलाइन एक आपातकालीन नंबर के रूप में कार्य करती है। इसे विशेष रूप से तटीय सुरक्षा, मछली पकड़ने वाले समुदाय और तटीय गाँवीणों की आवश्यकताओं से संबंधित शिकायतें और सूचनाएं प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया था।

> आम जनता को न केवल सतर्क रहने के बारे में, बल्कि हमले के बाद उचित प्रतिक्रिया के बारे में भी शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। आम जनता की सहायता के बिना आसपास के समाज में घुले-मिले गुमनाम अपराधियों, राष्ट्र-विरोधी, आतंकवादियों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

जब स्थानीय निवासी प्राथमिक आपातकालीन नंबर 100 तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं, तो वे सहायता के लिए 1093 पर संपर्क कर सकते हैं।

तटीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए पुलिस ने तट के किनारे रहने वाले कई मछुआरों को मोबाइल कनेक्शन प्रदान किए हैं। ये कनेक्शन पुलिस, नौसेना और भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) नियंत्रण कक्ष के साथ पंजीकृत हैं। जिससे मछुआरों को खुले समुद्र या तट पर किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करने में मदद मिलती है।

समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देश

मछुआरा समुदाय राज्यों और भारत के अन्य तटीय क्षेत्रों की समग्र तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मछुआरे तटीय सुरक्षा के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की आंख और कान के रूप में कार्य करते हैं।

मछुआरों को समुद्र में जाते समय अपना बायोमेट्रिक कार्ड साथ रखना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां उनके पास पहचान पत्र नहीं है, उनके स्थान पर स्थानीय पंचायत या अन्य अधिकारियों द्वारा जारी एक पत्र ले जाना चाहिए। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए मछुआरों को अपने मछली पकड़ने के जाल को सुरक्षित करने के लिए फ्लोटर बॉय का उपयोग करना चाहिए और जहाज पर चढ़ते समय लाइफ जैकेट पहनना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों और बड़े जहाजों के लिए मोटोरोला के मुक्त आवृत्ति संचार उपकरणों को ले जाना महत्वपूर्ण है।

रात के दौरान मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों को चालू लेकिन स्थिर रखना चाहिये जिससे सुरक्षा एजेंसियां बाहरी क्षेत्रों से घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधियों को रोक सकती हैं।

समुद्र में सुरक्षा के लिए समुद्री योग्यता सुनिश्चित करना

मछुआरों को अपनी नावों की समुद्र योग्यता

की व्यवस्थित जांच करनी चाहिए। उन्हें मौसम के पूर्वानुमानों से अपडेट रहना चाहिए, दूरी की चेतावनी देने वाले ट्रांसमीटर अपने साथ रखने चाहिए, रेडियो संचार उपकरण को व्यवस्थित बनाए रखने चाहिए, जीवन रक्षक उपकरण रखने चाहिए, आवश्यक नाव दस्तावेज, बायोमेट्रिक पहचान पत्र, अतिरिक्त मोबाइल फोन/बैटरी, अस्थायी मरम्मत किट, प्राथमिक चिकित्सा किट और अतिरिक्त ईंधन साथ रखना चाहिए। समुद्र में जाते समय राशन, अतिरिक्त बैटरी टॉर्च तथा आवश्यक दवाएं भी रखनी चाहिये। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जोड़े या समूहों में संचालित किया जाना चाहिए। मछली पकड़ने वाले जहाज मालिकों को अपने जहाजों की समुद्री योग्यता और कार्गो की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्हें जहाजों पर लगातार जांच करनी चाहिए, निर्धारित समय के अनुसार मशीनरी और प्रणोदन प्रणालियों का रख-रखाव करना चाहिए, और लंगरगाह पर जहाजों के लिए एक स्टैंडबाय के तौर पर दूसरा एंकर और चेन केबल रखना चाहिए।

तटीय पुलिस का समर्थन करना

वर्तमान परिस्थिति में पुलिस समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए पुलिस को चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए समुदाय को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। हालाँकि, समाज के भीतर कुछ व्यक्ति पुलिस को चुनौती देने का प्रयास करते हैं, उन पर कानून के उल्लंघन के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने का दबाव डालते हैं, अनावश्यक विरोध प्रदर्शन और हड़तालें आयोजित करते हैं। कभी-कभी वे कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने के दौरान पुलिस पर मनमानी का अनुचित आरोप लगाते हैं। इससे एक सुरक्षित एवं संरक्षित समाज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है।

तटीय सुरक्षा के लिए तटीय जनसंख्या का लाभ उठाना

आम जनता को न केवल सतर्क रहने के बारे में, बल्कि हमले के बाद उचित प्रतिक्रिया के बारे में भी शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। एकजुट आबादी सुरक्षा खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सरकार की सहायता कर सकती है। आम जनता की सहायता के बिना आसपास के समाज में घुले-मिले गुमनाम अपराधियों, राष्ट्र-विरोधी आतंकवादियों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

“आंख और कान” पहल जैसी योजनाओं को लागू करना सभी क्षेत्रों के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। यह संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने और सुरक्षा प्रयासों का समर्थन करने में तटीय जनता की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

तटीय सुरक्षा प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए मछली पकड़ने वाले समुदाय और तटीय आबादी को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है?

तटीय सुरक्षा प्रयासों में मछली पकड़ने वाले समुदाय और तटीय आबादी की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और सहयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यहां कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं:

जागरूकता अभियान

मछली पकड़ने वाले समुदाय और तटीय आबादी को तटीय सुरक्षा के महत्व, उनकी भूमिका और संभावित खतरों के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाना। इन अभियानों में कार्यशालाएं, सेमिनार और सामुदायिक बैठकें शामिल हो सकती हैं जो रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में तटीय समुदाय के महत्व को उजागर करती हैं और समुद्र तट

की सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी पर जोर देती हैं।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

मछुआरों को तटीय सुरक्षा से संबंधित आवश्यक ज्ञान और कौशल से युक्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। इसमें संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने, रिपोर्टिंग प्रक्रिया, बुनियादी निगरानी तकनीक और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। व्यापक प्रशिक्षण सत्र देने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को समुद्री विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना चाहिये ।

संचार चैनल स्थापित करना: मछली पकड़ने वाले समुदाय और सुरक्षा एजेंसियों के बीच प्रभावी संचार चैनल सुनिश्चित करें। उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधियों या घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें त्वरित और उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन दें।

मान्यता और प्रोत्साहन: तटीय सुरक्षा में मछली पकड़ने वाले समुदाय और तटीय आबादी के योगदान को पहचानें और उसकी सराहना करें। असाधारण सतर्कता प्रदर्शित करने वाले या सुरक्षा खतरों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्तियों या समूहों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, प्रमाणपत्र, सार्वजनिक स्वीकृतियां या सामुदायिक सम्मान जैसे पुरस्कार प्रणाली स्थापित करें। ये प्रोत्साहन प्रेरणा के रूप में काम कर सकते हैं तथा गर्व और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत कर सकते हैं।

सहयोगात्मक पहल: सुरक्षा एजेंसियों, स्थानीय अधिकारियों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के बीच साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना। मछुआरों को संयुक्त गश्त और निगरानी गतिविधियों में शामिल करें। जहां वे स्थानीय मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं और मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकते हैं। सूचनाओं के आदान-प्रदान, चिंताओं को दूर करने और संयुक्त रूप से सुरक्षा उपायों की योजना बनाने के लिए उन्हें नियमित बातचीत, कार्यशालाओं और बैठकों में शामिल करें। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण विभिन्न हितधारकों के बीच बंधन को मजबूत करता है। हितधारकों में विभिन्न विभाग और संगठन शामिल हैं; जैसे पोर्ट ट्रस्ट, छोटे बंदरगाहों के बंदरगाह अधिकारी, लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, आव्रजन ब्यूरो, समुद्री पर्यटन समुदाय, जिसमें चप्पू, पाल, मोटर, इंजन द्वारा संचालित नावों की एक आश्चर्यजनक विविधता शामिल है।

तकनीकी सहायता: मछली पकड़ने वाले समुदाय को प्रौद्योगिकी और उपकरणों तक पहुंच प्रदान करना जो उनके सुरक्षा प्रयासों में सहायता कर सकें। इन तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर प्रशिक्षण भी प्रदान करना चाहिये।

सामाजिक-आर्थिक लाभ: तटीय सुरक्षा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक लाभों को स्पष्ट करते हुए उस पर प्रकाश डालना चाहिये। इस बात पर जोर दें कि एक सुरक्षित तटरेखा पर्यटन को आकर्षित करती है, मछली पकड़ने की धारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देती है और तटीय समुदायों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करती है।

मछुआरा निगरानी परिषदों का गठन

मछुआरा निगरानी परिषदों की स्थापना करना आवश्यक है। तटीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रमुख व्यक्तियों को "सुरक्षा राजदूत" के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लोग सतर्क रहकर और पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करके मुखबिर, गवाह और बचावकर्ता के रूप में योगदान दे सकते हैं। आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए सामुदायिक सहमति के माध्यम से "पड़ोसी निगरानी समितियों" का गठन किया

जा सकता है। मछली पकड़ने वाले भारतीय समुदाय को स्थानीय पुलिस, आईसीजी और भारतीय नौसेना (आईएन) के साथ समुद्री और तटीय सुरक्षा प्रयासों में "कार्यकारी भागीदार" के रूप में शामिल किया जा सकता है जो सामाजिक संपत्ति विकसित कर रहे हैं और लोगों के अधिकारों का सम्मान कर रहे हैं। गवाह संरक्षण कानूनों को मजबूत करना और तट रेखा पर खतरे के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना। प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल का शिक्षण महत्वपूर्ण हैं।

तटीय सुरक्षा के लिए तटीय प्रादेशिक सेना (टीए) का उपयोग

देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तटीय प्रादेशिक सेना (टीए) रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तटीय सुरक्षा के लिए समर्पित एक बल तटीय जल में काम करने में सक्षम होना चाहिए और कानूनी मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। टीए को आईसीजी (इंडियन कोस्ट गार्ड), आईएन (इंडियन नेवी) या भारतीय सेना की कमान के तहत रखा जाना चाहिए। सुरक्षा और खुफिया कर्तव्यों के लिए टीए बटालियनों के साथ भारतीय सेना का परिचालन अनुभव मूल्यवान है।

टीए के पीछे का विचार अंशकालिक नागरिकों का एक बल रखना है, जिन्हें उच्च-खतरे की स्थितियों के दौरान आसानी से नियोजित किया जा सके तथा कम खतरे या शांतिकाल के दौरान इसकी लागत प्रभावी बनी रहे।

टीए के वर्तमान रोजगार में सड़क खोलना, तलाशी अभियान के दौरान घेराबंदी करना और सेना कमांड मुख्यालय की सुरक्षा करना जैसे रक्षात्मक कार्य शामिल हैं। टीए की व्यावसायिकता, लागत-प्रभावशीलता और नागरिक आबादी के साथ संबंध बनाए रखने की क्षमता इसे लाभप्रद बनाती है। तटीय सुरक्षा में अंशकालिक अवधारणा को मजबूत करना राष्ट्रीय हित में है क्योंकि "नागरिक सेना" पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करती है और विभिन्न खतरों से निपटने के लिए एक आरक्षित बल के रूप में काम कर सकती है।

निष्कर्ष

तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मछली पकड़ने वाले समुदाय, तटीय आबादी और सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास एक मजबूत रक्षा तंत्र बनाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि तट की सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। जिसके लिए समुद्र तट के किनारे की आबादी सहित प्रत्येक हितधारक की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है।

सिंधु तीरे का प्रथम गाँव चुलिचांग

मे. ज. डॉ. एस. के. सिंह

एनडीए और आईएमए के पूर्व छात्र एवं वर्तमान में लखनऊ में एक त्रिशक्ति डिफेंस इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं।

परिचय

1983-84 में मैं कारगिल में पदस्थापित था। सैन्य अधिकारी होने के नाते सभी चौकियों का दौरा करना पड़ता था। यह वर्ष 1983 का जून माह था, जब उन दिनों एक अत्यंत छोटे गाँव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जिसका नाम चुलिचांग था। मैं उस समय लेफ्टिनेंट था। आर्टिलरी रेजिमेंट में होने के कारण उस समय की मेरी रैंक पर मुझे इन क्षेत्रों में बंदूकों के साथ तैनात रहना होता था।

चुलिचांग सिंधु घाटी के एक संकीर्ण भाग में सिंधु नदी के बाएं किनारे पर है। जिसे ब्रोग यूल के नाम से जाना जाता है। यह भारत के केंद्र शासित राज्य लद्दाख का अंतिम गाँव है; बाएं किनारे पर अगला गाँव नटसारा, पाकिस्तान अधिकृत बल्तिस्तान में है। चुलिचांग का क्षेत्रफल 125.90 हेक्टेयर है (1.2590 वर्ग किमी) और इसमें पाँच उपगाँव सम्मिलित हैं: ग्रौंग ख्रिल, ग्रौंग स्टोड-१, ग्रौंग स्टोड-२, शारची और ग्रोंगजुक।

चुलिचांग दक्षिण की ओर शार्गोले खंड, पश्चिम की ओर द्रास खंड, पूर्व की ओर शकर-चिकतन खंड, दक्षिण की ओर ताइसुरु खंड से घिरा हुआ है।

स्थान और जनसंख्या

चुलिचांग अक्षांश 34.663323 डिग्री उत्तर, देशांतर 76.315108 डिग्री पूर्व पर अवस्थित है। 1983 में यहाँ की जनसंख्या लगभग 200 थी जो समय के साथ बढ़ी है और भारत की नवीनतम जनगणना (2011) के अनुसार, गाँव के 112 घरों में 912 निवासी हैं। महिला जनसंख्या 48.8% है। गाँव की पुरुष साक्षरता दर 58.4% और महिला साक्षरता दर 22.8% है। यह शिया ब्रोकपास और बाल्टिस द्वारा वासित है।

इतिहास

ऐतिहासिक रूप से चुलिचांग और आस-पास के क्षेत्र ब्रोक्पा लोगों द्वारा वासित थे। लोककथाओं के अनुसार वे गिलगित क्षेत्र से अपने वर्तमान निवास स्थान पर आए थे। ब्रोक्पा प्रमुखों ने स्कर्दू के माकपोन शासकों के प्रति नाममात्र की निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हुए इस क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त की थी। यद्यपि, सत्रहवीं शताब्दी

में लद्दाख के जामयांग नामग्याल के समय उक्त स्थिति में परिवर्तन हो गया। लद्दाख के जामयांग नामग्याल का स्कर्दू के अली शेर खान अंचन के साथ संघर्ष हुआ और उन्हें सिंधु नदी के विपरीत तट पर स्थित एक गाँव गुर्गुरधो को अपने क्षेत्रों की मध्य सीमा के रूप में स्वीकार करना पड़ा। परिणाम स्वरूप, चुलिचन और उसके उत्तर में स्थित गानोख और मरोल जैसे गाँव बल्तिस्तान का अंग बन गए और शिया इस्लाम से प्रभावित हो गए। जब रॉबर्ट बार्कले शॉ ने 1876 में गाँव का दौरा किया तो उसने बाल्टिस और ब्रोकपास में शिया मुस्लिमों को वहां रहते हुए पाया।

फिर भी चुलिचांग के ब्रोकपास ने ऐतिहासिक रूप से लद्दाख के दाह हनु क्षेत्र में अपने जातीय रिश्तेदारों के साथ विवाह किया। ऐसे संबंध केवल बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पश्चात ही समाप्त हुए। उन्नीसवीं सदी के अंत में प्रथम कश्मीर युद्ध (1947-1948) के पश्चात जब पाकिस्तान ने चूलीचांग के उत्तर के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, तो यह भारत का एकमात्र ब्रोक्पा गाँव बन गया जो मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा वासित था।

परिवहन और सुलभता

- **सड़क मार्ग द्वारा**

बटालिक, कारगिल और लेह में अन्य स्थानों से कारगिल-बटालिक-खलत्से सड़क के माध्यम से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, जो कारगिल और खलात्से के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से एक "घुमावदार मार्ग" बनाता है।

- **रेल**

बटालिक के निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन सोपोर रेलवे स्टेशन और श्रीनगर रेलवे स्टेशन हैं जो क्रमशः 271 और 277 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं।

- **वायु-मार्ग**

निकटतम हवाई अड्डा 60 किलोमीटर दूर कारगिल में है। किंतु यह वर्तमान में चालू नहीं है। अगला निकटतम हवाई अड्डा लेह है, जो 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

निकटतम भारतीय गाँव

निकटतम भारतीय गाँव बटालिक है, जो चुलिचांग के पूर्व में 4.3 किलोमीटर दूर है। वास्तव में चुलिचांग पहुंचने के लिए बटालिक गाँव से होकर गुजरना होगा। बटालिक गाँव एक शुद्ध आर्य गाँव है

ब्रोकपास जन

ब्रोकपास जन (जिन्हें मिनारो जनजाति के नाम से भी जाना जाता है) का एक समृद्ध और विविध इतिहास है और उनकी उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार वे सिकंदर की लुप्त हुई सेना के वंशज हैं। जबकि अन्य स्रोतों के अनुसार वे भारत में स्वदेशी आर्यों के एकमात्र जीवित वंशज हैं। इस क्षेत्र में ब्रोकपास नामक उपनाम के जन का निवास है। जिसका उपयोग लद्दाखियों (अर्थात पहाड़ी निवासियों) द्वारा किया जाता है। जो शिन जनों का एक उप-समूह हैं। उनके मौखिक इतिहास से यह आकलन लगाया जा सकता है कि दाह-हनु क्षेत्र पर प्रथम बार 10 वीं शताब्दी में प्रवासी शिनों के समूह द्वारा अधिकार किया गया था। जो बड़े स्तर पर जीववाद के प्राचीन दार्दिक धर्म का पालन करते थे और स्वयं की मिनारो जातीय पहचान का दावा करते थे। लगभग छह सौ वर्षो के पश्चात शिनास का एक और समूह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर दाह-हनु में चला गया। उनके मध्य एक संघर्ष उत्पन्न हुआ किंतु उन्होंने साथ रहना चुना। मैरील साम्राज्य में समाहित होने तक उनके प्रमुखों का क्षेत्र में नाममात्र का अधिकार था। अपने अधिकांश पड़ोसी शिनाओं के विपरीत दाह - हनु के ब्रोक्पा इस्लाम से विशेष रूप से अप्रभावित रहे, उन्होंने अद्वितीय संस्कृति बनाए रखी।

बटालिक- शुद्ध आर्य गाँव

बटालिक भारत के लद्दाख में एक गाँव और सैन्य अड्डा है, जो सिंधु नदी घाटी के एक संकीर्ण भाग में स्थित है, तथा पाकिस्तान अधिकृत बल्तिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा के निकट है। यह कारगिल, लेह और बल्तिस्तान के मध्य स्थित होने की अपनी सामरिक स्थिति के कारण 1999 के कारगिल युद्ध का केंद्र बिंदु था।

बटालिक कारगिल से 56 किमी दूर है और दाह हनु क्षेत्र में स्थित है। जिसे "आर्यन घाटी" भी कहा जाता है। जहां ब्रोकपा जन रहते हैं। प्रशासनिक रूप से इसे सिल्मो गाँव के एक उपगाँव के रूप में माना जाता है।

आर्यन घाटी

ऐतिहासिक रूप से आर्यन घाटी को दाह हनु घाटी या क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें चार गाँव सम्मिलित हैं - लेह जिले में दाह और हनु, और कारगिल जिले में गारकोन और दारचिक और भारत के मध्य लद्दाख में संबंधित उपगाँव। मैरील साम्राज्य में समाहित होने तक ब्रोक्पा प्रमुखों के पास इस क्षेत्र में नाममात्र की स्वायत्तता थी। वर्तमान नाम की उत्पत्ति पर्यटन उद्योग में 2010 में ब्रोकपास , ब्रोक्सकैट भाषा बोलने वाले अधिकांश वज्रयान बौद्ध स्थानीय निवासियों को आदिकालीन आर्यों के रूप में प्रचारित करने हेतु की गई। ब्रोक्पा जनों की शारीरिक विशेषताएं जैसे उनका लंबा कद, गोरा रंग, ऊंचे गाल और नीली-हरी आंखें यूरोपीय विशेषताओं से मिलती जुलती हैं।

आर्य संघ और नवशास्त्रवाद

1880 में एक ब्रिटिश प्राच्यविद् जी. डब्ल्यू. लीटनर ने ब्रोकपास को "एक प्राचीन और शुद्ध आर्य जाति के अवशेष" कहा था। इस रूपक को अन्य औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा प्रबलित किया गया और उन्हें प्रभावी रूप से विदेशी बना दिया गया। सिरैक्यूज़ विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई अध्ययन और मानवविज्ञान की प्रोफेसर मोना भान का कहना है कि भाषाई और सांस्कृतिक लक्षणों का ऐसा ऐतिहासिक नस्लीकरण ब्रोकपास पर आधुनिक नृवंशविज्ञान में भी बना हुआ है।

1980 में एच.पी.एस. अहलूवालिया ने तीन जर्मन नव-नाज़ी महिला पर्यटकों से मिलने की सूचना दी। जो ब्रोकपा उत्सव में सम्मिलित हुई थीं और उन्हें "शुद्ध आर्यों" द्वारा गर्भवती होने की आशा थी; ऐसे कल्पित

पर्यटक इस क्षेत्र में मीडिया कवरेज का प्रमुख अंग बन गए। समय के साथ, ब्रोकपास ने अलेक्जेंडर की सेना से वंश का पता लगाने की सीमा तक आर्य चरित्र-चित्रण को आत्मसात कर लिया। 2003 में कारगिल हिल काउंसिल के चुनावों के दौरान उन्होंने अन्य कारकों के अतिरिक्त, अपनी आर्य पहचान के आधार पर अल्पसंख्यक सीटों पर प्रतिनिधित्व का दावा किया। यद्यपि, यह स्व-प्रचार पश्चिम में "आर्यन" के सामान्य अर्थों से भिन्न था। ब्रोकपास के लिए उनकी आर्य पहचान सहस्राब्दी पुराने संघर्ष में निहित थी - विभिन्न शासकों द्वारा उत्पीड़न के सामने एक अद्वितीय पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष। जैसा कि लोक-कथाओं के माध्यम से बताया गया था और उनके घृणित सामाजिक-आर्थिक उपेक्षा में सुधार करने का एक उपकरण था।

2010 के आरंभ में जब सरकार इस क्षेत्र में पर्यटन को आकर्षित करने की इच्छा कर रही थी, तब स्थानीय पर्यटक अभिकर्ताओं ने वहां के निवासियों के आर्यत्व को प्रचारित करना आरंभ कर दिया। राज्य सरकार ने भी ब्रोक्पा जनों को 'आर्यन जाति के शुद्ध प्रतिरूप' के रूप में प्रस्तुत करके इस प्रवृत्ति को सुदृढ़ किया। कुछ ब्रोक्पाओं ने तो अपना उपनाम भी बदलकर "आर्यन" रख लिया। इसी चर्चा के अंतर्गत "आर्यन घाटी" नाम का सृजन हुआ। 2019 में स्थानीय लोगों ने मांग की कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए "आर्यन घाटी" को एक धरोहर गाँव घोषित किया जाए।

वनस्पति और जीव

यह क्षेत्र विभिन्न वनस्पतियों को प्रदर्शित करता है, जिनमें जड़ी-बूटियाँ, झाड़ियाँ, शुकपा, स्टैगपा, उम्बु, सेवा, स्काईरेपा, स्पेंमे, कांगटाकारी, अस्कुटा, गरमा, युलेद और कुमौट जैसी वनस्पतियाँ सम्मिलित हैं। चुनौतीपूर्ण जलवायु के बावजूद, यह क्षेत्र विविध पक्षियों और स्तनपायी प्रजातियों का घर है।

अवलोकनों में पलास डिपर, ब्लू व्हिसलिंग थ्रश, ब्राउन डिपर, ग्रीनिश लीफ, वॉर्ब्लर्स, कॉमन स्विफ्ट, यूरेशियन क्रैग मार्टिन, लार्ज-बिल्ड क्रो, माउंटेन शिफचैफ, ग्रे वैगटेल, ह्यूम्स लीफ, वार्बलर, रेड-मैन्टल्ड रोज़फिंच और रेड-फ्रंटेड सेरिन सम्मिलित है। हिमालयन आईबेक्स (पहाड़ी बकरी) छिटपुट रूप से परिदृश्य में दिखाई देती है। स्थानीय जनसंख्या, जिसे ब्रोकपा के नाम से जाना जाता है, चिलिगी देउहा नामक जुनिपर मंदिर में अनुष्ठान करती है।

निकोबार के प्रथम गाँव

डॉ. एन. लक्ष्मी

असिस्टेंट प्रोफेसर (हिंदी), महात्मा गांधी गवर्नमेंट कालेज मायाबंदर, मध्योत्तर अंडमान

चौरा, तेरेसा, कचाल आदि गाँव निकोबार के प्रथम गांवों में हैं। यह मूलत: अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व भाग में 6° से 14° उत्तरी अक्षांश तथा 92° से 94° पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण में अर्धचंद्राकार के जैसे बिखरे मोतियों के समान लगभग आठ सौ कि.मी. की लंबाई में ये द्वीप फैला हुआ है। द्वीपों के नक्शे को देखने पर हमें पता चलता है कि अंडमान तथा निकोबार दो अलग-अलग द्वीपसमूह हैं जिन्हें 10° चैनल विभाजित करता है। 10° चैनल के उत्तर में जो द्वीप है उसे अंडमान तथा दक्षिण में जो द्वीप है उसे निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में स्थित यह द्वीपसमूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। द्वीप समूह में 572 से भी अधिक द्वीप हैं जिनमें से 38 द्वीपों में लोग बसे हुए हैं। शेष वन आच्छादित हैं। द्वीपों का क्षेत्रफल लगभग 8249 वर्ग कि.मी है। अंडमान तथा निकोबार दो अलग-अलग द्वीप समूह होने पर भी प्रशासन एक है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 को अंडमान के रास द्वीप का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा। इसके साथ ही हैवलाक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया तथा नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के आधार पर किया।

भौगोलिक दृष्टि

भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में इन द्वीपों का विशेष महत्व है। भौगोलिक दृष्टि से अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है। निकोबार मूलत: म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों की सीमाओं से सटा हुआ है। इन देशों के साथ यह न केवल भू-सीमा बल्कि समुद्री सीमा भी साझा करता है। इंडोनेशिया के आचेह के उत्तर से मात्र 150 कि. मी पर यह स्थित है तथा अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार से अलग करता है। भौगोलिक दृष्टि से निकोबार द्वीप तीन भागों में विभाजित है। यथा- उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत कार

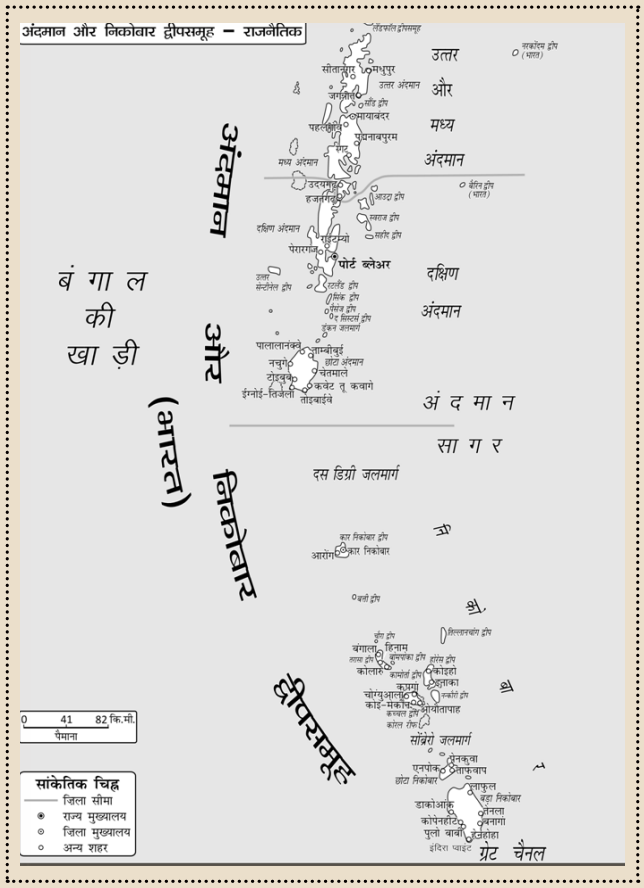

निकोबार और बाटीमालाव द्वीप आते हैं। मध्य क्षेत्र में चौरा, तेरेसा, कचाल, नानकौरी, कमोर्टा, टरिकेट, बंबूका और तेलंगचांग द्वीपों की गणना होती है। दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, पिलोमिलो, कोंडूल, कोबरा आदि द्वीप शामिल हैं। ग्रेट निकोबार का अंतिम छोर 'पिग्मेलियन प्वाइंट' है। जिसे इंदिरा बिंदु या इंदिरा प्वाइंट के नाम से जाना जाता है और यही भारत का अंतिम छोर है। पहले भारत की सीमा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहा जाता था। लेकिन आज भारत का विस्तार उत्तर में कश्मीर से सुदूर दक्षिण में इंदिरा बिंदु तक हुआ है जो निकोबार के कैम्बल बे में स्थित है।

नामकरण

निकोबार 'नक्कावरम' शब्द से बना है जिसका तात्पर्य है नंगे रहने वाले लोगों का देश। मार्कोपोलो ने इन द्वीपों को 'नेकूवरम' नाम दिया है। कर्नल मूले ने चीनी नाम –'नालो-कियो-चेन' नारिकेल द्वीप नाम दिया है। इसके अतिरिक्त इन द्वीपों को नागद्वीप भी कहा जाता है। कालांतर में नागद्वीप-नीकू द्वीप, निकू और निकोबार के रूप में अपना अस्तित्व पा गया, ऐसा विद्वानों का मानना है। सर एस. कृष्ण स्वामी अयंगार ने एक लेख में इस बात की पुष्टि की है कि चोलाधिपति राजेंद्र चोल के समय की ताम्र लिपियों में कार निकोबार द्वीप का नाम 'कार द्वीप' और ग्रेट निकोबार द्वीप का नाम 'नाप् द्वीप' उल्लेखित है। पूरा निकोबार नक्कावरम के नाम से जाना जाता था। द्वीपों के संबंध में कहा जाता है कि चोल वंश के राजाओं ने अपने राज्य को विस्तृत करने के उद्देश्य से अंडमान-निकोबार, बर्मा के आराकान तथा पिगू प्रदेश को जीता था। लेकिन चोलों ने यहाँ अपना स्थायी निवास बनाया, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। इन द्वीपों में एक द्वीप का नाम चौरा द्वीप है जिससे चोलों के इन द्वीपों में आगमन की सूचना मिलती है। इसके साथ ही इस द्वीप में प्राप्त कुछ कलाकृतियाँ भी उनके आगमन को पुष्ट करती हैं। निकोबार द्वीप समूह में छोटे-बड़े लगभग 62 द्वीप हैं। जिनमें से 19 प्रमुख द्वीप हैं तथा 12 में लोग वास करते हैं। निकोबार के मूल निवासियों को निकोबारी कहा जाता है। मूल रूप से निकोबारी मंगोली नस्ल के लगते हैं। गोरा बदन, सुदृढ़ शरीर तथा आकर्षक होने के साथ-साथ यह लोग खेल-कूद एवं मनोरंजन में विशेष रूचि रखते हैं। इनका भोजन मुख्यत: नारियल, मछली, मांस और पांडुनस पर आधारित है। इनका एक फल है जो कि इन द्वीपों में आमतौर पर पाया जाता है। यह फल अन्नानास की आकृति का होता है। इसका तना 30 -35 फुट ऊँचा होता है। आजकल निकोबारी चावल, आटा, दाल, चीनी, मसाले, नमक, चाय आदि का भी सेवन करने लगे हैं। वे बिना दूध की चाय पसंद करते हैं।

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 6 प्रकार के आदिवासी रहते हैं। निकोबारी उनमें से एक हैं। अन्य आदिवासियों की तुलना में निकोबारी सबसे पहले बाह्य संपर्क में आए थे। शायद यही कारण है कि निकोबारी आज ज्ञान-विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में विकास प्राप्त कर पा रहे हैं। किंतु यह भी ध्यातव्य है कि वे अपनी

मूल संस्कृति और परंपरा का भी अनुसरण कर रहे हैं। निकोबार के आदिवासी निकोबारी होने पर भी अलग-अलग गांव में बसे लोगों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे, कार-निकोबार के निवासी 'तारिक' हैं। जब-कि चौरा के 'समपाई', कचाल, कमोटा और त्रिंकेट के 'सैम-इटा' हैं। इस प्रकार अलग-अलग द्वीपों की बोलियों में काफी अंतर दिखाई देता है। बावजूद इसके, इनमें एकता है और ये लोग सामाजिक संस्कृतिक समारोहों में आपस में मिल जुलकर भाग लेते हैं। इनके लिए विस्तृत परिवार या 'टूहेट' एक महत्वपूर्ण सामाजिक समूह है। 'टूहेट' का प्रमुख कार्य अपने सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना होता है। नाव चलाना, बागवानी करना, शिकार खेलना, मछली पकड़ने में इनकी रुचि होती है।

वर्तमान में अधिकांश निकोबारी इसाई धर्म का अनुपालन कर रहे है। इसाई धर्म को अपनाने से पहले ये प्रकृति की पूजा करते थे। यह लोग जादू-टोना में विश्वास करते हैं। त्योहारों को अधिक महत्व दिया जाता है। त्योहारों के अवसर पर गाना-बजाना, खेल-कूद, नौका-दौड़, मल्लयुद्ध आदि अनेक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है। हर निकोबारी इन त्योहारों में बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं और हर्ष-उल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं।

उत्सव-त्योहार

ओत्यो: एक साधारण त्योहार है। इस अवसर पर लोग समुद्र के तात पर बने घरों के सामने नए डंडे गाड़ते हैं, जिसे खूब सजाया जाता है। सूअर की आवश्यकतानुसार बलि भी दी जाती है।

हा-नगोक-मत्ताई: जब कोई बीमार होता है तब इस त्योहार को मनाया जाता है। इस अवसर पर भोजन भी खिलाया जाता है। इनके अतिरिक्त जब नया मकान बनता है या पुराने मकान का जीर्णोद्धार किया जाता है तब भी त्योहार मनाते हैं। बच्चा पैदा होने पर, नामकरण पर, बिलगाव के अवसर पर, लम्बे समय के बाद किसी मित्र से भेंट होने पर भी उत्सव मनाया जाता है। मृतकों की पारंपरिक पूजा एवं भूत-प्रेतों को भगाने के लिए मन्त्र-तंत्र पर आज भी उनका अटूट विश्वास है। सूअर की बलि देकर उसके खून को शरीर पर लगाने की उनकी प्रथा पर इसाई धर्म का कोई असर नहीं पड़ा है। इस प्रकार वर्ष भर निकोबारी कोई-न-कोई उत्सव मनाते रहते हैं। इनके उत्सव सामाजिक एवं धार्मिक होते हैं। सामाजिक त्योहार हंसी-खुशी मनाया जाता है जबकि धार्मिक त्योहार भूत-पिशाचों को मनाने आदि से सम्बंधित होते है। "कानाहा" का त्योहार बारी-बारी से अलग-अलग गाँवों में मनाया जाता हहैं। इस त्यौहार के एक सप्ताह पूर्व दूसरे गाँवों को निमंत्रण भेजे जाते हैं। निमंत्रण स्वीकार करने वाले व्यक्ति को सूअर का गोश्त, शकरकंद, केला, पपीता, कुवेन (रोटी-फल की खीर) लानी होती है।

पारंपरिक पोशाक में निकोबारी

सूअर त्यौहार: साल में एक बार सूअर त्यौहार को मनाया जाता है। जब गाँव में सुअरों की संख्या अधिक होती है, उस समय इस त्योहार को मनाया जाता है। इस अवसर पर रिश्तेदारों को सूअर भेंट स्वरूप दिया जाता है। पूर्वजों की याद में इस त्योहार को मनाया जाता है। जिस स्थान पर त्योहार मनाया जाता है, उस स्थान के पास पहले ही दिन सूअरों को कैद रखा जाता है। नारियल की पत्तियों, कपड़ों से दो या तीन सूअरों को सजाया जाता है। साथ ही छोटे बच्चों का पारंपरिक पोशाक में श्रृंगार किया जाता है। हाथों में कंगन, पैरों में आकर्षक पायल पहनाया जाता है। फिर सूअर पर बच्चे को बिठाकर पूरे गाँव में जुलूस निकाला जाता है। इस अवसर पर लोग सूअर गीत गाते हैं। यह जुलूस लगभग मध्यरात्रि में समाप्त होता है। इसके बाद पारंपरिक नृत्य किया जाता है जो सामान्यत: सामूहिक नृत्य होता है। स्त्री-पुरुष दोनों ही इस नृत्य में बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। तीसरे दिन विशेष नृत्य प्रस्तुत करने के लिए विशेष लोगों को आमंत्रित किया जाता है। अगले दिन पूर्वजों के हड्डियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। कुछ निश्चित रिश्तेदार ही इस कार्य को करते हैं। ये त्योहार मुख्य रूप से सामाजिक –आर्थिक विकास पर आधारित होता है।

नौका त्योहार: इस त्योहार में निकोबारी सूअर को एक विशेष बाड़े के अन्दर एक महीने तक खूब खिला पिला कर मोटा करते हैं। त्योहार के दिन इन्हें बाहर निकाल कर इनकी आपस में लड़ाई कराई जाती है। इसके पश्चात उनकी बलि दी जाती है। देर रात तक सामूहिक नृत्य एवं गायन चलता है। इसके बाद डोंगी या नौका त्योहार प्रारम्भ होता है। बड़े पैमाने पर भोज की व्यवस्था भी की जाती है। इस अवसर पर डोंगी गीत भी गाए जाते हैं।

कृषि गीत: निकोबार में कृषि मौसम पर आधारित होती है। मानसून का प्रारम्भ मई से होता है अत: उससे पहले ही कृषि भूमि को खेती के योग्य बनाया जाता है। गर्मी के मौसम में धान को काटकर सूखे स्थान पर संभालकर रखा जाता है। सभी कार्य करते हुए वे कृषि गीत गाते हैं। निकोबारी गीत लोक गीत की परंपरा एवं लोक संस्कृति का वाहक है।

निकोबारी समाज स्वतंत्र समाज है। युवक-युवतियों को अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने की छूट दी जाती है।

यहाँ तक कि यह भी जरूरी नहीं कि विवाह के बाद लड़की ही ससुराल जाएं बल्कि लड़का घर जमाई बनकर रह सकता है। अपनी संस्कृति और परंपरा की रक्षा के साथ निकोबारी आदिवासी आधुनिकता की होड़ में कदम-से-कदम मिलाकर चल रहे हैं। शिक्षा, खेल, नृत्य तथा संगीत के क्षेत्र में ये निरंतर आगे हैं।

प्रशासनिक सेवा में, चिकित्सा विभाग में, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि के रूप में कार्यरत हैं।

डा. मंजू नायर

महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज
मायाबंदर, मध्योत्तर अंडमान में
हिंदी विभागाध्यक्ष

भारत के दक्षिणतम छोर पर स्थित प्रथम गाँव शास्त्री नगर

महान भारतवर्ष को हिमालय पर्वत से प्रारम्भ होकर हिन्द महासागर तक फैला हुआ माना जाता है। हिन्दुकुश पर्वत श्रृंखला से अपार सिन्धु (समुद्र) हिंदमहासागर तक 'जम्बू द्वीप' के नाम से प्रसिद्ध था। कालान्तर में एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश भारतवर्ष बना। जिसका प्रहरी हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार व हिन्दमहासागर तो इसे उर्वर मिट्टी सौंपते है। विशाल नदियाँ सींचती व विविध भाषा-भाषी लोग देश को दिव्य व भव्य बनाते जा रहें है। आज सीमान्त गाँव, भारत के दक्षिण सीमा हिन्द महासागर की एक प्रसिद्ध खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अन्डमान निकोबार द्वीपसमूह प्रतिबिंबित करती है। वैसे तो भारत देश की आक्षांशीय विस्तार 6 13° उत्तर व 92° 93° पूर्व है तो भूमध्य रेखा (0°) से उत्तर की ओर 6° उत्तरी अक्षांश से हमारे बृहत देश का विस्तार है और इसी 6° उत्तरी अक्षांश पर ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित है। इस द्वीप के सीमान्त गाँव का नाम शास्त्री नगर है। हमारा देश भारत गाँवों का देश रहा है। किंतु भूमंडलीकरण के इस दौर में बाजारवाद, आधुनिकतावाद, मशीनीकरण,

औधोगीकरण, उपभोक्तावाद व विकास की अपार संभावनाओं ने मनुष्य को आरामतलब एवं विकासशील भी बना दिया है। जिस कारण विश्व की 65% जनसंख्या शहरों में आवासित है। हाँ, कोविड जैसी महामारी की आपदा ने शहरवासियों को गाँवों की ओर पलायन करने को मजबूर किया। जिसमें अभूतपूर्व तरीके से विश्वभर के कामगार पैदल ही अपने गाँवों की ओर लौटे व आज गाँवों को पुनः बसते पाया है और बदलते वैश्विक विकसित परिवेश में गाँवो का शहरीकरण, रामबाण साबित हुआ है। जीवन को हरा-भरा करने में गाँव नगीने बनने लगे। संसाधित संसाधन सुचारू परिवहन, संचार, स्वास्थ्य इत्यादि अनगिनत सुविधाओं से गाँव जुड़ते जा रहे है और गाँव अपने बहुमूल्य माटी से जुड़े. मूल स्वरूपों व गुणों से प्रतिबिंबित हो आलोकित हो रहे हैं। तकनीकि क्रांति का यही जलवा है कि सुदूर बसे अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, यहां तक कि भारत के दक्षिणतम छोर पर स्थित ग्रेट निकोबार की धरती भी, जो जनजाति बंधुओं से पुष्ट है, आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है व ग्लोबल गांव की 'एक विश्व एक परिवार व एक भविष्य' की मान्यता को चरितार्थ करती जा रही है।

भारत के दक्षिणतम छोर को पिग्मिलीयन प्वाइंट के नाम से जाना जाता था। जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और 80 के दशक में जबकि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इन द्वीपों में पधारी व पिगमिलीयन प्वाइंट पर पहुँची तो उनके नाम पर पिगमिलीयन प्वाइंट के नाम को बदलकर इंदिरा प्वाइंट रख दिया गया और आज ग्रेट निकोबार के दक्षिणतम छोर पर स्थित दीपस्तम्भ व श्रीमती गांधी के नाम से बनी पार्क व उनकी तांबे की आदमकद मूरत देश की इस महिला प्रधानमंत्री के नाम से जानी जाती है और यह कोई अतिश्योक्ति नहीं यदि हम कहें "कश्मीर से इंदिरा प्वांइट तक हम एक हैं"। क्योंकि अब वो दिन लद गए जब हम कन्याकुमारी, जो भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर है, को दक्षिणतम बिन्दु के नाम से जानते थे। हमारी अनभिज्ञता थी कि भूमध्य रेखा से 6° 13' उत्तर पर स्थित ग्रेट निकोबार को भूला बैठे।

कालापानी

भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में द्वीपसमूहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सैल्युलर जेल व पराक्रमी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का इन द्वीपों में पदार्पण व तिरंगा फहराने की घटनाएँ भारतीयता को नई ऊँचाइयाँ प्रदान करती हैं। भले ही यह टापुओं का समूह विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक है। लेकिन उतना ही सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील भी है। रामायण काल से इन द्वीपों की ख्याति थी। कहते है 'ग्रेट निकोबार द्वीप अपनी मालायन प्रकृति के भू परिवेश, प्राकृतिक सम्पदाओं, वनों व अन्य जलवायु के परिदृश्य में मलय प्रायद्वीप से 145 किमी. की दूरी पर स्थित है, इस कारण समानता रखता है। न कि 1200 किमी दूर स्थित प्रान्त भारतीय प्रायद्वीप से, चोला साम्राज्य की समुद्री विस्तारवादी नीतियों के समय भी इन द्वीपों का खास योगदान उनके जलयानों को सुरक्षा देता रहा है। बड़े-बड़े जहाजी बेड़े मलाका की खाड़ी से पूर्व के देशों; जैसे मलाया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया से व्यापारी संबंध रखते थे। ग्रेट निकोबार द्वीप के बारे में यह भी मान्यता है कि संजीवनी बूटी की तलाश व द्रोणागिरी पर्वत को लंका ले जाते समय वानरराज हनुमान के हाथों से एक टुकड़ा जो द्रोणागिरी पर्वत का गिरा था, वही ग्रेट निकोबार द्वीप है और सत्य की कसौटी पर कसने के लिए भरपूर हरियाली से लदे इस द्वीप पर खूब वर्षा व भूमध्य रेखा से सटे होने के कारण तेज खुली धूप हरियाली की आभा द्वीप को ओढ़ाती तो है साथ ही बड़ी-बड़ी नदियाँ गालाथियाँ, डागमार, अलक्जेनड्रिया जैसे नदियाँ जल व ठंडक यानि आर्दता प्रदान कर टापू को आक्सीजन से भरपूर बना संजीवनी बूटी की ख्याति को बरकरार रखती है। यह एहसास अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के किसी भी द्वीप के वातावरण में नहीं जो ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह की जलवायु परिवेश माटी

पेड़ पौधे व भलेमानस शाम्पेन प्रागैइतिहासिक वनों में रहने वाले आदिवासी व निकोबारी बंधुओं को देखकर समझ सकते है। ऐसा खूबसूरत सा है हमारा भारत का दक्षिणतम छोर। जो उत्तर की ओर मुख्यभूमि भारत, जिसमें गारों खासी जयतियां की पहाड़ियाँ व हुगली नदी की डेल्टा पूर्व की ओर आरकान योमा की पहाड़ियाँ हैं तो दक्षिण की तरफ मलाका की खाड़ी है। इंडोनेशिया का उत्तरी छोर व सुमात्रा जैसे देश ग्रेट निकोबार के इंदिरा पांइट से मात्र 145 किमी. दूर पर अवस्थित है। और 45 मिनट की नौका विहार से आप इंडोनेशिया के भू-भाग पर पहुँच सकते है तथा अंर्तदेशीय जलयान मार्ग यही से होकर गुजरता है व इंदिरा प्वांइट का द्वीपस्तंभ, जो सौर्य उर्जा से चलती है सभी देशी-विदेशी मालवाहक पोतें व जहाजी बेड़ों का पथ प्रदर्शक होता है। यह मार्ग ऐसा है जो व्यापार व सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। इस कारण ग्रेट निकोबार विश्व के व्यापार मानचित्र पर पश्चिमी व पूर्व देशों के व्यापार मार्ग का एक केन्द्र बिन्दु बना है जो हिंद महासागर में अपनी अति महत्वपूर्ण अवस्थित के लिए पहचाना जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण द्वीप पर स्थित इंदिरा प्वांइट से उत्तर की ओर स्थित अंतिम गाँव शास्त्री नगर व संपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील है। जिसके बारे में सैल्युलर जेल में आए देशप्रेमी राजनैतिक बंदी, भविष्यदृष्टा वीर विनायक दामोदर जी ने जब पहली बार द्वीपों में कदम रखा था तो यही कहा था ये द्वीप भारत की जलशक्ति व सैन्य शक्ति का भविष्य में एक प्रमुख केन्द्र होगा। उनकी भविष्यवाणी अक्षरस: सत्य हुई। भारतीय सेना के तीनो अंग तटरक्षक दल, टोही दस्ते सभी देश व द्वीप की सुरक्षा में चौबीसो घंटे तैनात रहते है। इसी कारण हमारा सीमावर्ती गाँव 'शास्त्री नगर' जो केम्पबल बे द्वीप पर अवस्थित है काफी प्रसिद्धी पा रहा है।

भारत के महान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर इस गाँव का नाम 'शास्त्री नगर' रखा गया है। कैम्पबेल बे के जेट्टी से सड़कमार्ग द्वारा 35 कि.मी. दूरी पर यह गाँव बसा है। यहां से की 26 कि.मी. की दूरी पर देश का अंतिम छोर इंदिरा प्वांइट अवस्थित है। कई भौगोलिक चुनौतियाँ आज भी यहाँ विद्यमान हैं। इसके बावजूद भी सैन्य दृष्टि से सेवानिवृत्त लोगों के परिवार इस द्वीप में बसाए गए। जिनमें पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडू से सेवानिवृत्त परिवार ग्रेट निकोबार लाए गए। साथ ही आन्ध्र प्रदेश के कुछ मछुवारे, छतीसगढ़ व झारखंड से राँची समुदाय के लोग भी लाए व बसाए गए। 1960-1980 तक सेना से सेवानिवृत्त परिवारों के लोग यहाँ लाए गए। भारत सरकार व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त जो सेना से तुरंत रिटायर हुए थे। जिनकी आयु 30-35 वर्ष रही होगी वे परिवार के साथ ग्रेट निकोबार में बसाये गए।

शास्त्री नगर उत्तर दक्षिण तटीय आबाद स्थानों से सड़क मार्ग से जुड़ा है। जो उत्तर दक्षिण ग्रेट निकोबार के पूर्वी तट पर बिछी है। 42 कि.मी. शून्य से प्रारंभ हो अब 61 कि. मी. पर इंदिरा प्वांइट है व 35 कि.मी. पर 'शास्त्री नगर' गाँव है। राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशीलता के तहत् शास्त्री नगर में पंजाब, महाराष्ट्र व तमिलनाडु के सेना से सेवानिवृत्त परिवारों के लोग बसाए गए। जैसा कहा जाता है 'धर्मो रक्षति रक्षत:' तो रक्षा उनकी होती जो देश धर्म व स्वंय की रक्षा में सक्षम हैं तब प्रदेश की रक्षा अपने आप होती है।

इस प्रकार भारत भूमि का यह अंश शास्त्री नगर गाँव उपजाऊ जमीं, उपोष्ण आर्द्र जलवायु, अनुछुई हुम्मस से लबालब भरे उर्वर मिट्टी से सम्पन्न है। पर्यावरणीय गुण व्यवहार में एश्वर्यपूर्ण व भौगोलिक वैविध्य से परिपूर्ण भारत वर्ष से भौगोलिक रूप से विलग होने के बावजूद भी भारतीयों की धनी संस्कृति से सुसंपन्न है।

गाँव में पंजाबी, मलयाली, तमिल, मराठी, राँची परिवार बसते हैं। होली, क्रिसमस, गुरुपर्व व देशीय पर्व खुशी से मनाते हैं। सेना से सेवानिवृत्त परिवारों के लोग

यहाँ कृषि नारियल के बगान व चावल की खेती करते हैं। और यह सैन्य सेवाओं से जुड़े होने के कारण सेना की काबिलियत तो रखते हैं। तात्पर्य यह है कि देश की सुरक्षा में डटने के कौशल से परिपूर्ण, कहा जाता सकता है।

देश रक्षा में तत्पर रक्षक शास्त्री नगर में बसे है गाँव में शिव व हनुमान जी के दो मंदिर, नारियल के बागान व हाट लगती है। दो पान की दुकान है। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्वास्थ्य के लिए और देश का अंतिम प्राथमिक विद्यालय भी इसी गाँव में है जहाँ सेना से सेवानिवृत्त के बच्चे (सी बी एस ई) पाठ्यक्रम पढ़ते है। जहाँ तीन शिक्षक व पंद्रह विद्यार्थी हैं। इससे सटा हुआ विजयनगर गाँव भी शास्त्री नगर को सहायता देता रहता है। जनसंख्या 200 के करीब व 30-40 मकान हैं। जिसमें से दो या तीन निजी मकान हैं और बाकी सभी सुनामी शेलटर में रहते हैं। जिसमें रहने वाले सड़कमार्ग से जुड़ी बस सेवा से खुश है। दुधारू पशु गाय का दूध, नारियल की गिरी, केला, पपीता, चीकू इत्यादि फल से पुष्ट है। पेयजल के पाइप लाइन व तालाब है व बिजली भी है। एक पंचायत व वार्ड सदस्य भी है जो प्रशासनिक ढाँचे को पुष्ट करता है। साइकिल व जीप की सवारियाँ भी देखी जा सकती हैं। सीमा से सटे होने के कारण गाँववासी बार्डर रोड संस्था व सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवा विकास के कार्यकलापों में हिस्सा लेकर कामगारी द्वारा आय पा जाते हैं और कृषि, खासकर नारियल के चूर्ण तथा नारियल के खोल व तेल बनाने में भी संलग्न रहते हैं व फल, फूल सब्जी इत्यादि भी उगाते हैं व खूब आत्मनिर्भर हैं।

सेवानिवृत सैनिक ऐसे योद्धा हैं जो सेना से तो जुड़े हैं लेकिन भूकंपीय क्षेत्र के अत्यंत संवेदनशील जोन पाँच में रहने के कारण, भूकंप 2004, सुनामी की पीड़ा भी झेल गए। 80% भू-भाग सुनामी के कारण इस गाँव के कई मकान नष्ट हुए। एक या दो मकानों को छोड़ सभी लोग सुनामी शैलटर में रहते हैं। वर्तमान समय में वे आमदनी के लिए खेती योग्य भूमि के नष्ट हो जाने के कारण गाय पालन व नारियल के खोल का कोयला निर्यात करवाने, नारियल की गिरी का चूर्ण व नारियल तेल निकालने के काम में संलग्न हैं। गाँव में एक मिल भी है जो चावल, गेहूँ इत्यादि की सफाई कुटाई में काम आती है और गाँव वाले विजयनगर स्थित "रिफ्लैक्स मिल" (नारियल से सम्बद्ध) व 35 कि.मी. से अपने गाँव से 62 कि.मी. तक यानि करीब 26 कि.मी. तक बनने वाले सड़क व अन्य विकास की गतिविधियों में बॉडर रोड संस्था तथा सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवा, सैन्यबल 'बाज' इत्यादि की सहायता करते नहीं थकते व आपसी भाईचारा व परोपकार की भावना से पल्लवित हैं व लोक कल्याण की इच्छा रखते हैं। आपस में हिन्दी भाषा के सेतु (सम्पर्क भाषा) से जुड़े हैं तथा माँ भारती से बड़े गर्व के साथ भारत के अंतिम छोर के गाँव के नाम से विख्यात गाँवों की तंतु से जुड़े हैं।

सरकारी योजनाएँ व विकास के प्रयास अनमोल हैं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यहां बनने जा रहा है। सीमा रेखा से मात्र 150 कि.मी. की दूरी पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के जहाजों के लिए एक अप्रतिम गोदी होगी। एक नागरिक हवाईअड्डा गांधीनगर व शास्त्रीनगर व विजयनगर गाँवों को जोड़कर निर्माणाधीन होने जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय परीपेक्ष्य में पर्यटन की खातिर आने वाले वर्षों में शास्त्री नगर गाँव व अंडमान निकोबार द्वीप प्रसिद्धि पा जायेगा।

हिंदुस्तानी भाव लेकर जो भी इन द्वीपों में आया, टापुओं की श्रृंखला को मानवीयता से जोड़ता गया

अंतत: 'वसुधैव कुटुम्बकम' के भावों का पुरजोर समर्थन करने हेतु सक्षम भारत का यह गाँव (शास्त्री नगर) विश्व प्रसिद्धि के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

जय हिंद

नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे,
त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्।

माननीय राजनाथ सिंह जी (केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री)

श्री राजीव मल्होत्रा जी (लेखक),
वाइस एडमिरल श्री ए.के. चावला जी एवं श्री रविंद्र अग्रवाल जी

श्री पुरषोत्तम रूपाला जी (केंद्रीय मंत्रीश्री)
एवं नौसेना प्रमुख श्री आर. हरी कुमारजी

माननीय डॉ मनसुख मांडविया जी (केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रीश्री)

लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे जी
एयर मार्शल आर.सी बाजपेयी जी

गुजरात - माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल जी

श्री विवेक सहाय जी, डीजीपी - गुजरात

श्री नितिन अग्रवाल जी
महानिदेशक - सीमा सुरक्षा बल

लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी जी,
लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जी

माननीय सांसद श्री सतीश चंद्र दुबे जी - बिहार

श्री संजय अग्रवाल जी, श्री सौरभ गौतम जी एवं
श्री अनिल वलसांगकर जी

श्री के. पी. महादेवस्वामी, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के
चेयरमैन और प्रबंध निदेशक

श्री रक्षित शाह जी - कार्यकारी निदेशक
अदाणी पोर्ट्स और एसईज़ेड लिमिटेड

कर्नल रणबीर सिंह जमवाल और उनकी टीम

श्री सुजान चिनॉय जी - महानिदेशक
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

LEADING MANUFACTURER IN GHAZIABAD

SHIV SHANKAR ENTERPRISES

QUALITY 100% ASSURANCE

Based in Ghaziabad, we specialize in crafting high-quality cotton fabric, tapestry, coated fabric, and synthetic leather. Our commitment to excellence ensures premium products tailored to meet diverse needs. Whether it's luxurious cotton or durable synthetic leather, we deliver superior textiles for various industries. Elevate your projects with our top-notch materials.

ORDER NOW

PAN INDIA DELIVERY

RAMA DEVI
PROPRIETOR

Contact us
9927660160

Address
SHIV SHANKAR ENTERPRISES
MAIN ROAD MURADNAGAR
GHAZIABAD, UTTAR PRADESH

S.R SUPER STORE

Your one-stop shop for daily household essentials in Ghaziabad! From groceries to household products, we offer unbeatable prices and free home delivery. Get everything you need conveniently and affordably. Shop with us and experience the ease of stress-free shopping for your everyday needs

ORDER NOW

QUALITY 100% ASSURANCE

FREE HOME DELIVERY

Contact us
8272009242
8191920111

Address
S.R SUPER STORE
MAIN ROAD MURADNAGAR
GHAZIABAD, UTTAR PRADESH

ARJUN GUPTA
PROPRIETOR

Printed By : Apical Book Agency, Flat No. 2, First Floor, Daryaganj, Delhi-110002

Owner & Publisher

Seema Jagran Manch, A-161, Bahubalui Enclave, Surajmal Vihar, New Delhi-110092